

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

खण्ड-2, अंक-1

अधिकृत विवरण

विशय सूची

भुक्रवार, 17 मार्च, 2006

पृष्ठ संख्या

शोक प्रस्ताव	(2)1
ताराकित प्रान एवम उत्तर	(2)7
नियमो 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तरांकित प्रानो के लिखित उत्तर	(2)29
अताराकित प्रान एवम उत्तर	(2)47

घोशणाए	
(क) अध्यक्ष महोदय द्वारा,	
(i) सभापतियों की सूची	(2)59
(ii) अनुपस्थिति की अनुमति	(2)59
(ख) सचिव द्वारा	
राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलो संबंधी	(2)63
बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी का पहली रिपोर्ट	(2)64
नियम 121 के अधीन प्रस्ताव	(2)66
सदन की मेज पर रखे गए/पुन रखे गए कागज पत्र	(2)67
वाक आउट	(2)68
अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत करना	(2)68
प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना	(2)69
वर्ष 2006-07 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करना	(2)69

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 29 सितम्बर 2004

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 4.00 बजे हुई। अध्यक्ष (डा० रघबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

भाक प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now, the Chief Minister will make obituary references.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा): अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र और इस सत्र के अन्तराल में हमारे कई साथ हमें छोड़कर चले गए हैं। मैं सदन में उनके भाक प्रस्ताव रखता हूँ।

सरदार लछमन सिंह, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री सरदार लछमन सिंह के 21 फरवरी, 2006 को हुए दुखद निधन पर गहरा भाक प्रकट करता हूँ।

उनका जन्म 10 जनवरी, 1922 को हुआ। वे 1967 में हरियाणा विधान सभा के लिए चुने गये और मंत्री रहे। वे 1977 और 1982 में पुनः हरियाणा विधान सभा के लिए चुने गये तथा 1996 में राज्य सभा के लिए भी चुने गये। उन्होंने सदैव आम

आदमी के उत्थान के लिए कार्य किया। उन्होंने कई दे गो की यात्राए की।

उनके निधन से दे गो एक योग्य प्र शासक की सेवाओ से वचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक सतप्त परिवार के सदस्यो के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानी

यही सदन उन स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है, जिन्होंने दे गो की आजादी के संघर्ष मे अपने बहुमूल्य योगदान दिया।

इस महान स्वतन्त्रता सेनानियो के नाम इस प्रकार से है'—

1. श्री हरद्वारी लाल, गांव डाढीबाना, जिला भिवानी।
2. श्री उत्तम चंद भारर, पानीपत।
3. श्री भयोराम, गांव चकरपुर, जिला गुडगांव।
4. श्री मलखान सिंह, गांव खेडलाख जिला गुडगांव।
5. श्री चन्द्रभान, रोहतक।
6. श्री फूल चंद गांव किसानजफरगढ, जिला जींद।
7. श्री तुलसाराम, गांव दगडौली, जिला भिवानी।

8. श्री बलबीर सिंह, गांव सफेदा नगर, जिला गुडगांव।
9. श्री भयोनारायण, गांव करीरा, जिला महेन्द्रगढ।
10. श्री परशुराम, गांव डाडावास, जिला गुडगांव।
11. श्री उदमीराम, गांव सुरपुरा खुर्द, जिला भिवानी।
12. श्री रामकिशन गांव ईरगाह जिला जींद।
13. श्री शिवलाल, गांव मुसैदपुर, जिला गुडगांव।
14. श्री प्रभु सिंह, गांव राजली, जिला हिसार।

यह सदन इन महाने स्वतंत्रता सेनानियों को भात भात नमन करता है और इनके भाोक संतप्त परिवारो के सदस्यो के प्रति अपनी हार्दिक संवदेना प्रकट करता है।

हरियाणा के भाहीद

यही सदन उन वीर सैनिको को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है, जिन्होने हमारी मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता से लडते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया।

इस महान वीर सैनिको के नाम इस प्रकार से है'—

1. लेफ्टिनेंट कर्नल राजीव बख्शी, पंचकूला।
2. हवलदार रोहता शर्मा सिंह गांव दुजाना, जिला झज्जर।

3. हवलदार रूपचंद, गांव नंदगाव, जिला भिवानी ।
4. लांस नायक विरेन्द्र, गांव भुआपुर, जिला फरीदाबाद ।
5. नायक राम निवास, गांव अलिमुदीनपुर, जिला गुडगांव ।
6. सिपाही महिपाल सिंह, गांव भाहजादपुर, जिला अम्बाला ।
7. सिपाही जय भगवान, गांव सिवाह, जिला जींद ।
8. सिपाही सुरेन्द्र सिंह, गांव चुलियाणा, जिला रोहतक ।
9. सिपाही भीष्ण, गांव खरक पाण्डवां, जिला कैथल ।
10. सिपाही सुनील कुमार, गांव दूधवा, जिला भिवानी ।

यह सदन इन महान वीरो की भाहादत पर इन्हे भात भात नमन करता है और इनके भाोक संतप्त परिवारो के सदस्यो के प्रति अपनी हार्दिक संवदेना प्रकट करता है ।

वाराणसी बम विस्फोट मे मारे गये लोग

यह सदन 7 मार्च, 2006 को वाराणसी मे हुए बम विस्फोट मे मारे गये मासूमो के दुखद निधन पर भाोक प्रकट करता है ।

यह सदन ऐसी जघन्य घटना की घोर निन्दा करता है तथा दिवंगतो के भाोक संतप्त परिवारों के सदस्यो के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है

सामान्य

यह सदन मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा के मामा के पोते श्री आ गीशा,

हरियाणा विधान सभा के सदस्य री दुडाराम के पिता, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री भजन लल के भाई उप मुख्यमंत्री श्री चन्द्रमोहन तथा सांसद श्री कुलदीप बिानोई के चाचा श्री मनफूल सिंह तथा संसदीय सचिव कुमारी भारदा राठौर के पिता श्री अमर सिंह के दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतो के भाोक संतप्त परिवारों के सदस्यो के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है

डा० सु गीला इंदौरा (ऐलनाबाद एस०सी०): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुडा जी ने भाोक प्रस्ताव सदन मे प्रस्तुत किया है मैं उस भाोक प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए अपनी तरफ से, अपने साथियो की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से गहरा भाोक प्रकट करता हू। सरदार लक्षमन सिंह, भूतपूर्व मंत्री के निधन पर मैं गहरा भाोक प्रकट करता हू। वे बहुत ही सुलझे हुए राजनीतिज्ञ थे। मुझे उनके साथ

राज्यसभा के काम करने का अवसर मिला था। राज्यसभा की एक कमेटी में हम दोनों एक साथ मੈबर थे। उस समय मैंने उनसे काफी कुछ सीखा। वे एक योग्य समाज सेवक थे और उन्होंने हर वर्ग के विकास में अहम भूमिका निभाई है। उनके निधन से मुझे गहरा दुख है। मैं अपनी तरफ, अपने साथियों की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से हमारे स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा भाव प्रकट करता हूँ। इस महान स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार से हैं—

1. श्री हरद्वारी लाल, गांव डाढीबाना, जिला भिवानी।
2. श्री उत्तम चंद भारर, पानीपत।
3. श्री भयोराम, गांव चकरपुर, जिला गुडगांव।
4. श्री मलखान सिंह, गांव खेडलारु जिला गुडगांव।
5. श्री चन्द्रभान, रोहतक।
6. श्री फूल चंद गांव किसानजफरगढ, जिला जींद।
7. श्री तुलसाराम, गांव दगडौली, जिला भिवानी।
8. श्री बलबीर सिंह, गांव सफेदा नगर, जिला गुडगांव।
9. श्री भयोनारायण, गांव करीरा, जिला महेन्द्रगढ।
10. श्री पर जुराम, गांव डाडावास, जिला गुडगांव।

11. श्री उदमीराम, गांव सुरपुरा खुर्द, जिला भिवानी।
12. श्री रामकिान गांव ईरगाह जिला जींद।
13. श्री शिवलाल, गांव मुसैदपुर, जिला गुडगांव।
14. श्री प्रभु सिंह, गांव राजली, जिला हिसार।

हमारी पार्टी इन सब स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा भाोक प्रकट करती है। अध्यक्ष महोदय, यह सदन स्वतन्त्रता सेनानियों को प्रणाम करता है, हम भी स्वतन्त्रता सेनानियों को प्रणाम करते हैं। हमारी सोच रही है कि हरियाणा प्रदेश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको मान सम्मान दिया जाये। उनके नाम पर हरियाणा में जो बड़ी बड़ी संस्थाए हैं, उनके नाम रखे जाये। पूरा सदन इस बात पर गौरव भी महसूस करेगा लेकिन बड़े दुख की बात है कि मौजूदा सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है पानीपत थर्मल प्लांट का नाम महान् स्वतंत्रता सेनानी स्वीर्गीय चौधरी देवी लाल के नाम से रखा हुआ था। मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूँ। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से हमारे स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता हूँ। यह सदन 7 मार्च, 2006 को वाराणसी में हुए बम विस्फोट में मारे गये मासूमों के दुखद निधन पर भाोक प्रकट करता है तथा दिवंगतों के भाोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है इसके अतिरिक्त मैं अपनी तरफ से और अपनी

पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा के मामा के पोते श्री आ गीश के निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है। मैं अपने तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से श्री मनफूल सिंह, के निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता हू। वे बहुत अच्छे समाज सेवी थे। वे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल के भाई ही नहीं बल्कि उनके एक अच्छे दोस्त के रूप में भी उनका साथ दिया था। वे मेरे साथी विधायक चौधरी दुडाराम जी के पिता श्री थे, हमारे उप मुख्यमंत्री चौधरी चन्द्र मोहन जी और सांसद सदस्य श्री कुलदीप बि नोई के चाचा थे। इससे पता चलता है कि एक राजनीतिक परिवारों से जुड़ा हुए थे। वे अचानक हमें छोड़कर चले गये? उनके निधन पर मैं अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से गहरा भाोक प्रकट करता हू इसके अतिरिक्त हमारे संसदीय सचिव कुमारी भारदा राठौर के पिता श्री अमर सिंह के निधन पर भी मैं अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से गहरा भाोक प्रकट करता हू। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ और अपनी पार्टी की तरफ से चौधरी ओम प्रकाश तथा अपनी पार्टी के साथियों की तरफ से सभी दिवंगत लोगों के निधन पर गहरा भाोक व्यक्त करता हू तथा परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हू कि वे इन दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे तथा उनके परिवारों को यह असीम दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री राधे याम भार्मा अमर (नारनौल): अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता आदणीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुडा की तरफ से भाोक प्रस्ताव सदन मे प्रस्तुत किया गया है, मै उसका समर्थन करता हू। हमारे पूर्व मंत्री सरदार लक्षमन सिंह सांसद भी रहे और बहुत ही अच्छे विधायक से तथा बहुत ही बढिया सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। वे लोगो की मुसीबतो तथा दुख दर्ज को बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक सुनते थे। वे लोगो की समस्याओ का समाधान करने मे गहरी रूचित रखते थे और उन समस्याओ को हल करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया करते थे। एक बात मेरे गांव मे भी उनका जाना हुआ था उनके वहां जाने पर आस पास के काफी लोग वहां पर एकत्रित हो गए थे और लोगो ने उनकी बातो को बडे ध्यान से सुना और वहां के लोगो ने उनकी बहुत ही प्रसा भी की। मै उनके निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता हू। अध्यक्ष महोदय, हमारे जो महान स्वतन्त्रता सेनानी रहे है उन्ही के बलिदानो के कारण तथा उनकी कुर्बानियो की वजह से ही आज हम यहां पर स्वतन्त्र रूप से बैठे हुए है। मै प्रस्ताव मे वर्णित स्वतन्त्रता सेनानियो के निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करता हू। वे सैनिक जो देा की रक्षा करते हुए भाहीद हुए और इस देा की रक्षा करते हुए अपने प्राणो की बाजी लगाई उनके निधन पर मै अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हू। इसके साथ ही वाराणसी के अन्दर जो भीशण बम विस्फोट हुए जिसके कारण अनेको निर्दोश भाई बहन मारे गए और अनेको घायल हुए, उनके प्रति मै गहरा दुख व्यक्त करता हू तथा इन बम विस्फोटो की निन्दा करता

हू। वाराणसी मे हिन्दु मुस्लिम लोगो को मै अपनी बधाई और धन्यवाद देना चाहता हू कि उन्होने वाराणसी मे हिन्दु मुस्लिम अथवा धार्मिक तनाव पैदा नही होने दिया और वातावरण को बहुत ही बढिया तथा सौहार्दपूर्ण बनाए रखा। हमारे सदन के नेता चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुडा के मामा के पोते श्री आ गीश का असामयिक निधन हो गया है और सारे सदन ने उनके निधन पर गहरा भाोक प्रकट किया है मै भी उनके प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हू। इसी प्रकार से हमारे साथी विधायक श्री दुडा राम के पिता जी, हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री चन्द्र मोहन जी के चाचा चौधरी मनफूल सिंह के निधन पर मै गहरा भाोक प्रकट करता हू। हमारे संसदीय सचिव माननीय कुमारी भारदा राठौर के पिता श्री अमर सिंह जी का असामायिक निधन हो गया है सारे सदन के साथ मे अपनी तरफ से उनके प्रति गहरा भाोक प्रकट करता हू तथा परमपिता परमात्मा से यह प्रार्थना करता हू कि दिवंगत आत्माओ को अपने चरणो मे स्थान दे तथा उनके परिवारो को यह असीम दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे। धन्यवाद।

शिक्षा मंत्री (श्री फूल चन्द मुलाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो भाोक प्रस्ताव रखा है मै अपने आप को इस प्रस्ताव के साथ जोडता हू। सरदार लक्षमन सिंह जी हमारे बहुत ही पुरान राजनेता था। उन्होने 1967 मे पहली बार कालका से चुनाव लडा था और मैने भी 1957 मे ही

पहली बार छछरौली हल्के से चुनाव लडा था, तब से लेकर उनके निधन तक उनके साथी मेरे बहुत ही मधुर सम्बन्ध रहे। वे बहुत ही जिन्दादिल व्यक्ति थे। सरदार लछमन सिंह जी से जब भी पूछते थे कि आपकी आयु कितनी है तो वे कहा करते थे गुलामी का जो समय था मैं उसको अपनी उम्र नहीं गिनता और दूसरे जब जब हमारी सरकार नहीं रही उसको भी मैं अपनी उम्र से नहीं गिनता बाकी आप लगा लीजिए कि मेरी उम्र कितनी होगी और अगर सारी उम्र गिने तो मेरी उम्र करीब 20-25 साल हुई है। अध्यक्ष महोदय, वे बहुत ही खुादिल और जवादिल व्यक्ति थे। वे बाथरूम से नहा कर निकले और बाथरूम के बाहर ही वहां पर गिर गए विधि का विधान देखिए।

जमाना बडे भोक से चुन रहा था दांस्तां अपनी, हम ही सो गए दांस्तां कहते कहते।

अध्यक्ष महोदय, 1992 मे वे मेरे साथी ही मंत्री थे और 1983 मे हम इक्टटे ही मन्त्रिमण्डल से बर्खास्त किया गया था। हमारे उनके साथ बहुत ही मधुर सम्बन्ध थे। मुझे उनके निधन पर गहरा दुख हुआ है। इसी प्रकार सदन के नेता ने स्वतन्त्रता सेनानियां के निधन पर, हरियाणा के भाहीदो के निधन पर और वाराणसी बम विस्फोट मे कई निर्दोश लोगो के निधन पर बारे मे भी भोक प्रस्ताव रखा है। मैं इस पर गहरा भोक प्रकट करता हू। स्पीकर महोदय, स्वतन्त्रता सेनानियों के सहारे ही हम आज वहां पर बैठे हुए है। यहा पर उनके लिए यह कहना सही होगा कि

भाहीदो की चिताओ पर लगोगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालो का यह बाकी निगा होगा। तो हम सब का फर्ज है कि हम उनको नमन करे। इसी प्रकार से यह जो आतंकावाद मे लोग मारे गए है यह बहुत ही दुखद घटना है। आज सारे देश मे आंतकवाद के खिलाफ बहुत जोर भाोर से लडाई लडी जा रही है लेकिन बहुत सारे अंगी ऐसे है जिनका इन्सानियत से कोई तालुक नही है। यह आंतकवादी इन्सानियत के खिलाफ है। इनके खिलाफ हम सभी को मिलकर जंग लडनी होगी। इसी के साथ सदन के नेता श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा जी के मामाम के पोते श्री आशिष का दुखद निधन हो गया है, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री दुडाराम छोडकर के चले गए है उनके प्रति भी मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हू। हमारी सदन की सदस्या कुमारी भारदा राठौरा के पिता श्री अमर सिंह जी बहुत ही अच्छे आदमी थे। कुमारी भारदा राठौर जी बता रही थी कि उनके पिता ही उनको राजनीति मे लेकर आए थे। उनके प्रति भी मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हू। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो भाोक प्रस्ताव सदन मे रखा है मैं अपने आपको उसके साथ जोडता हू और दिंगवतो के भाोक संतप्त परिवारो के सदस्यो के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हू। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य गण मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव मे रखा है और दिवंगत आदमियो के प्रति माननीय सदस्यो ने जो अपने विचार प्रकट करे है, मैं भी अपनी भावनाएं उनके

साथ जोड़ता हूँ। पिछले सैं उन के समाप्त होने के बाद और इस सैं उन के आरम्भ होने के बीच में हमारे बीच में कई महान विभूतियाँ इस दुनिया को छोड़ कर चली गई हैं। सबसे पहले मैं सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री सरदार लछमन सिंह के हुए दुखद निधन पर गहरा भाव प्रकट करता हूँ। उनका निधन हृदय गति रुक जाने की वजह से हुआ है। वे बहुत ही अनुभवी विधायक थे। वे 1967, 1977 और 1982 में हरियाणा विधान सभा के लिए चुनाव लड़कर आए थे। उन्होंने खासकर कालका क्षेत्र की जी जान से सेवा की थी। उन्होंने 1978 से लेकर 1983 तक मंत्री रहते हुए कई कार्यालयों का कार्य भार सम्भाला था। आज वे हमारे बीच में नहीं रहे हैं इसका हमें बेहद दुख है इसके साथ ही मैं स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर जिना नाम मुख्यमंत्री जी ने भाव प्रस्ताव में दिया है , गहरा भाव प्रकट करता हूँ, आज स्वतन्त्रता सेनानियों के बलिदानों का नतीजा है कि आज हम आजाद देश में बैठे हुए हैं। आज हमें उनके बलिदान से प्रेरणा लेनी चाहिए और सच्चे मन से तन से और धन से देश की सेवा करनी चाहिए। मैं उन सभी भावीदों को भात भात नमन करता हूँ जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है। मैं उन भावीदों के प्रति गहरा भाव प्रकट करता हूँ। इसके साथ वाराणसी में हुए बम विस्फोट में मारे गये मासूमों के दुखद निधन पर भाव प्रकट करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा के मामा के पोते श्री आशिश, के दुखद निधन पर भाव प्रकट करता हूँ। हमारे हरियाणा विधान सभा के सदस्य

री दुडाराम के पिता, हमारे उप मुख्यमंत्री के चाचा और हरियाणा विधान सभा के सदस्रू चौधरी भजन लालजी के छोट भाई श्री मनफूल सिंह तथा संसदीय सचिव कुमारी भारदा राठौर के पिता श्री अमर सिंह के दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है। मै दिवंगतो के भाोक संतप्त परिवारों के सदस्यो के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है मै परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्माओ को भान्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हू। उन भाोक संतप्त परिवारो तक इस सदन की संवदेना पहुचा दी जाएगी। अब मै दिवंगतो आत्माओ के सम्मान मे उन्ह श्रद्धाजति देने के लिए दो मिनट का मौन धारण करने के लिए सदन के सभी सदस्यो से खडा होने के लिए अनुरोध करता हू।

इस समय सदन ने दिवंगत आत्माओ के सम्मान मे खडे होकर उनके आत्मा की भान्ति के लिए दो मिनट का मौन धारण किया।

ताराकित प्रान एवम उतर

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे।

Damage caused to the Mustard Crop

389. Sh. Radhey Shyam Sharma: Will the Minister for Revenue be please to state-

(a) whether it is a fact that the mustard crop in Sourhern Haryana has been damaged due to severe cold during this year; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to provide financial assistance to the affected farmers of the said area?

Revenue Minister (Capt Ajay Singh Yadav):

(a) Yes, Sir

(b) No, Sir

श्री राधे भयाम भार्मा अमर: स्पीकर साहब, यह सरकार किसानों की सरकार है और किसानों का हित करने वाला सरकार है। अगर राज्य सरकार किसी कानून के कारण मुआवजा नहीं दे सकती तो क्या माननीय मंत्री महोदय कोई और विकल्प ढूंढकर उन किसानों को जिनकी सरसों की फसल पहले तो सर्दियों के कारण समाप्त हो गयी और अब जो वर्षा हुई, उससे उनकी सरसों की सारी खड़ी फसल के दाने झड़ गये, किसानों को कुछ नहीं मिला, उनको मुआवजा दिलवाने की कृपा करेंगे ? क्या माननीय मंत्री महोदय और कोई विकल्प ढूंढकर किसानों की सहायता करने में समर्थ नहीं है?

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो सरसों की फसल के बारे में मुद्दा उठाया है तो यह बात सही है कि इस बारे में जीरो डिग्री से कम तापमान चला गया था लेकिन जो क्लैमिटी रिलीफ फंडज 12वे फाईनेंस कमीशन द्वारा बनाया गया था उसमें पाला कवर्ड नहीं है। इसके तहत साइक्लोन, ड्राउट, हेल स्टोर्म, अर्थ क्वेक, फायर, फ्लड, और सुनामी जैसी कई किस्में कि

बात कवर्ड है। जो क्लैमिटी रिलीफ फंडज है इसके 75 परसेंट पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का और 25 परसेंट पैसा हमारा होता है। मुख्यमंत्री जी ने भारद पवार जी जो भी 25.1.2006 को सरसो की फसल के बारे में लिखा है कि जो पाला है उसको भी क्लैमिटी रिलीफ फंडज के तहत कवर्ड किया जाए स्वयं भी मुख्यमंत्री महोदय इस बारे में उनसे मिले हैं और इसके बाद उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखी है इसके अलावा उन्होंने एक चिट्ठी पाटिल साहब को भी लिखी है लेकिन इसमें समस्या यह है कि सी0आर0एफ0 की जो परिभाषा है उसमें पाला कवर नहीं होता है। फिर मैं इनको बताना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर पहली बार अपनी नैशनल इंयोरैन्स स्कीम इस बारे में चलायी गयी है। इस स्कीम में 13 जिलों के अंदर 73 ब्लॉक्स हैं। इस स्कीम के तहत हिसार, फतेहबाद, सोनीपत, गुडगांव, फरीदाबाद, रोहतक, सिरसा, भिवानी, झज्जर, जींद, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी और मेवात जिलों का कवर्ड किया गया है। स्पीकर साहब, इससे पहले किसी भी सरकार ने मस्टर्ड क्राप को इंयोरैन्स स्कीम के तहत कवर नहीं किया है लेकिन हमारे मुख्यमंत्री महोदय के प्रयासों से पहली बार मस्टर्ड और गन्ना की क्राप्स को इस स्कीम के तहत लाया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली स्टेट गवर्नमेंट ने जनवरी, 2002 में सेंट्रल गवर्नमेंट को लैटर लिखा, उस समय सेंटर में एन0डी0ए0 की सरकार थी और श्री औम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे उनकी उस रिक्वेस्ट को भी उन्होंने टर्न डाउन कर दिया था। नैशनल इंयोरैन्स स्कीम के तहत अगर 20

परसैट से ज्यादा किसी भी फसल का नुकसान होता है तो उसको इन्कलायूड किया गया है। टोटल 48833 किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी क्राप को इं योर्ड करवा रखा है, जिसके तहत उनकी फसल का नुकसान होने पर उन्हें रिलीफ मिल सकता है। लेकिन जब तक ये सी0आर0एफ0 में इन्कलायूड नहीं किया जाता तब तक सरकार अपनी तरफ से पैसा दे सकती है क्योंकि इसमें 75 परसैट कंट्रीब्यूशन सैन्ट्रल गवर्नमेंट का है।

श्री एस0एस सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि हरियाणा का पूरा जोन स्टोर्म ज़ोन है। ये सर्वविदित है, एग्रीकल्चरिस्ट जानते हैं और रेवैन्यू वाले भी जानते हैं। पूरा हरियाणा ओला वृष्टि के जोन में है। कोई सवाल ऐसा नहीं जाता कि जब जनवरी फरवरी में कहीं न कहीं ओले न पड़ते हों। इसी तरह से हर साल सर्दियों में पाला पड़ता है। सरसों की क्राप कमजोर क्राप है इसलिए पाले को सरसों की फसल बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या मुख्यमंत्री सैन्ट्रल गवर्नमेंट से दोबारा बात करेंगे कि पाला और ओला वृष्टि इन दोनों को भी एन0सी0आर0एफ0 के अंदर शामिल किया जाए नहीं तो हरियाणा का किसान इसी तरह से मरता रहेगा? जहां तक मंत्री महोदय ने इं योरेंस स्कीम की बात की है तो मैं कहना चाहूंगा कि वर्तमान स्थिति में आज में इं योरेंस स्कीम है वह केवल कोऑपरेटिव बैंक के जो लोनीज है यानि जो मैम्बरज है, उनके ऊपर लागू है जो कि बहुत कम लोग हैं। लेकिन मुक्ति कल

यह कि तहसील या ब्लाक ही उसका एरिया है, पूरे गांव या पूरे इलाके इसमें कवर्ड नहीं होते। जब स्कोप वाइड नहीं करेंगे तब तक इसका पूरा फायदा आम आदमी को नहीं हो पाएगा इसलिए स्कोप वाइड करना चाहिए। इसके साथ साथ मेरी अर्ज है कि ओला वृष्टि और पाले को एन.सी.आर.एफ. में शामिल करवाया जाए।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैंने विस्तार से इस स्कीम के बारे में बतारया है कि मुख्यमंत्री महोदय ने इसके लिए खूब प्रयास किए हैं और उन्होंने सैट्रल गवर्नमेंट को लैटर भी लिखे हैं जहां तक उन्होंने सवाल उठाया है कि पाले को भी एन.सी.आर.एफ. में इन्क्लूड किया जाए तो इस बारे में हमारी कोर्चि। अभी भी जारी है। जहां तक उन्होंने इं योरेंस स्कीम के बारे में बात की है तो इसमें जो नॉन लोनीज है वे भी अपनी क्राप को इं योर करवा सकते हैं। सरकार इस बारे में पूरा प्रयास कर रही है कि इसका पूरा प्रचार किया जाए। केवल 20 प्रति। त जो किसान को देना पड़ता है उसमें से 10 प्रति। त प्रीमियम सबसिडी स्टेट गवर्नमेंट देती है इसलिए सरकार की तरफ से इसमें सबसिडी का भी प्रावधान है और हर प्रकार की सुविधा है लेकिन आने वाले समय में सरकार इसका थोड़ा प्रचार और करेगी ताकि आम व्यक्ति अपनी क्राप को इं योर करवा सके। मैं समझता हू कि इसका पता आम व्यक्ति हो होना जरूरी है।

श्री नरे । यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने विस्तार से इस स्कीम के बारे में बताते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने लैटर्ज लिखे हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी, गोदबलाया, और अटेली के कुछ ऐसे ब्लॉक हैं जिनके अंदर 6 महीनों से पानी की एक बूंद भी नहीं गई जिसके कारण उनकी सरसों की फसल बर्बाद हो गई। बैंकों के अधिकारी अपनी जीप और गाड़ियों लेकर अभी भी किसानों को परेशान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय सदन में मौजूद हैं क्या वे बताएंगे कि किसानों के ऋण की अदायगी करने का काम करेंगे क्योंकि यह राहत उन्हें केवल सरकार दे सकती है?

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से साथी को बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री ने कोओपरेटिव बैंक के अधिकारियों को किसानों को अरैस्ट करने की जो हिदायतें दे रखी थी, उन पर अब रोक लगाने के लिए कहा है और हरियाणा पहला प्रदेश है जहां इस प्रकार का इंतजाम किया गया है। जहां तक महेन्द्रगढ़ की बात इन्होंने की है तो मैं इनको कहना चाहूंगा कि महेन्द्रगढ़ में 29211 ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपनी क्राप इंयोर करवा रखी है। मैं बताना चाहूंगा कि जहां तक फसल का सवाल है, फसल आज के दिन बहुत अच्छी है। यह बात ठीक है कि फसल को कुछ नुकसान हुआ है। जहां तक पानी टेल तक पहुंचाने की बात है, पानी टेल तक पहुंचा है और कुछ

एरियाज मे टेल तक पानी पहुंचाने के लिए काम चल रहा है, वहां भी पानी टेल तक पहुंचोगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने हैफेड के जरिये पिछले साल तीन लाख छ हजार टन सरसो किसानों से खरीदी है कि पहली बार हुआ है जबकि पिछली सरकार के समय मे 75 हजार टन सरसों ही खरीदी गई थी। विपक्ष के साथी तो अपने आपको किसान हितैशी कहते थे लेकिन इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किसानो का एक दाना नही खरीदा।

डा० सु गीला इंदौरा: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी की इस बात से सहमत हू कि केन्द्र सरकार फसल पर पाले की मार को नैचूरल क्लेमिटी रिलीफ फंड मे भामिल नही करती। हरियाणा प्रदे 1 कृशि प्रधान दे 1 है और अनाज के मामले मे केन्द्रीय पूल मे अच्छा योगदान हरियाणा प्रदे 1 का होता है। जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी ने किसानो का 1600 करोड रूपये का बिजली का बिल माफ किया है उसी आधार पर जिन किसानो की फसलों को पाले के कारण नुकसान हुआ है क्या उनको मुआवजा देने का कोई प्रावधान सरकार की तरफ से बजट मे किया जायेगा? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हू कि फसल खराब होने के कारण किसान आबयान नही भर सकते क्या उनका आबयान माफ किया जायेगा ?

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, जिस समय इनकी सरकार हरियाणा मे थी और केन्द्र मे एन०डी०ए० की

सरकार थी जिसमें ये भाई भी शामिल थे, उस समय इन्होंने भी इस बारे में केन्द्र सरकार की पत्र लिखा था लेकिन केन्द्र सरकार ने पाले की मार को नैचूरल क्लेमिटी रिलीफ फंड में नहीं माना। मैं अपने साथियों को बताना चाहूंगा कि जब तक इसको केन्द्र सरकार नैचूरल क्लेमिटी रिलीफ फंड के दायरे में नहीं लेगी तब तक हमारी सरकार पैसा नहीं दे सकती। (विधन)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा): अध्यक्ष महोदय, जो मेरे साथियों ने चर्चा की है उस बारे में कहना चाहूंगा कि जहां तक हरियाणा सरकार का सवाल है, हरियाणा सरकार किसान हितैशी सरकार है। जो पहले वाली सरकार थी वह सिर्फ किसानों का नाम नाम लिया करती थी लेकिन किसानों के हितार्थ कोई कार्य नहीं किया। जहां तक सरसों की फसल का सवाल है आपको जानकारी प्रसन्नता होगी कि पिछले साल हमारी सरकार ने तीन लाख मीट्रिक टन सरसों किसानों की खरीदी थी जो कि अपने आप में एक रिकार्ड है। अब की बार भी हमारी सरकार सरसों की फसल और दूसरी फसलों की खरीददारी करेगी। अब की बार अनुमानित 4 से 5 लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद हमारी सरकार करेगी। इसके अतिरिक्त दो तीन सवाल और उठे हैं। एक सवाल तो चौधरी भाम और सिंह सुरजेवाला जी ने उठाया था। मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि हेल स्टोर्म तो पहले से ही एन.सी.आर.एफ. में कवर है। पिछली सरकार के समय में हेल स्टोर्म से फसलों को जो नुकसान हुआ था उसका मुआवजा भी हमारी

सरकारी ने आने के बाद किसानों को दिया है। इसके अतिरिक्त इन् योरैस की बात कही गई। यह बात ठीक है कि इस समय ब्लॉक यूनिट चल रहे हैं और फसल को कितना नुकसान हुआ है इसका आंकलन फसल आने के बाद ही हो सकता है कि कितने प्रति टन फसल कम हुई है। अध्यक्ष महोदय, फसल इन् योरैस स्कीम सभी किसानों के लिए ओपन है जिसमें 10 प्रति टन पैसा सरकार देती है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपनी फसल का बीमा नहीं करवाया है। इनकी यह बात ठीक है कि ब्लॉक लैवल की यूनिट न बनाकर विपेज लेवल पर यूनिट बनाइ जाये। इस पर हम विचार करेंगे और इन् योरैस कंपनी वालों से भी बात करेंगे। मैं सदन को यह जानकारी भी देना चाहूंगा कि पिछले साल जब सरसों की खरीद चल रही थी तो कुछ मण्डियों में समस्या हुई थी। किसानों को लम्बी लॉन लगाकर खड़ा होना पड़ा था और कई कई दिन उनको इंतजार करना पड़ा था। नैफेड सरसों की खरीद कर रहा था और नैफेड ने यह कहा कि सिर्फ सोसाइटीज के थ्रू नैफेड सरसों खरीदगा। हमने भी प्रयास किया और व्यापारियों और आठतियों के थ्रू हमने सरसों की खरीद की। अब की बार हमने यह फैसला किया है कि नैफेड, नैफेड के थ्रू सरसों खरीदगा। लेकिन जो आठती है वे भी खरीदगे ताकि किसानों को सुविधा हो और समय पर उनकी सरसों की खरीद हो जाए जो सरसों आठतियों के थ्रू आएगा उसका साफ करने के लिए 10.70 रूपये नैफेड अपनी कमी टन में से देगा ताकि जल्दी से जल्दी उसका निपटारा हो सके।

Desilting of Canals

393. Dr. Sita Ram: Will the Minister for Revenue be please to state-

(a) whether the desilting and repair work of the canals has been done to the State During the year 2005; if so, the district wise details of the amounts spent thereon; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to provide financial assistance to the affected farmers of the said area?

Revenue Minister (Capt Ajay Singh Yadav):

(a) and (b) Sir, a Statement is laid on the Tabe of the House.

Statement

Against a budget provision of Rs. 45.54 Crores during 2005-06 for the purpose, and expenditure, of Rs. 3171 Crores has been reported up to 31-1-2006. Distritct wise detaisl as under:-

(Rs. In Lacs)

Sr. No.	Name of District	Amount Spent
1.	Ambala	51.74
2.	Bhiwani	495.01
3.	Faridabad	52.00

4.	Fatehabad	223.20
5.	Gurgaon	40.50
6.	Hissar	323.50
7.	Jhajjar	101.40
8.	Jind	238.30
9.	Kaithal	132.00
10.	Karnal	108.92
11.	Kurukshetra	94.95
12.	Mahendergarh	240.42
13.	Panipat	106.00
14.	Rewari	163.50
15.	Rohtak	260.56
16.	Sirsa	266.56
17.	Sonepat	182.00
18.	YamunaNagar	91.20
	Total	3171.20
Say Rs. 31.71 Crores		

Desiting and repair of Canals is an annual teature and a provision would be made in the Annual Budget of 2006-07.

डा० सीता राम: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपनी रिप्लार्ड में कहा है कि वर्ष 2005-06 के अन्दर नहरों की गाद निकालने एवम मरम्मत के लिए 45.54 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया है और खर्च सिर्फ 31.71 करोड़ रुपये हुए है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि जितनी हमारी नहरें और खालें हैं तथा जो मार्इनर्ज हैं क्या उनकी डिसिल्टिंग की गई है, क्या गाद निकालने का काम पूरे प्रदेश में किया गया है? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या अभी भी कुछ नहरें और ड्रेनज ऐसी हैं जिनकी गाद निकालने का काम अधूरा रह गया है? इसके साथ मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि किस एजेंसी के माध्यम से नहरों की गाद निकालने का काम किया गया है?

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बातना चाहता हूँ कि जो टोटल प्रावधान दिया था वह 45.54 करोड़ रुपये का किया गया है जिसमें से 10 मार्च तक हमने 34.90 करोड़ रुपये इस कार्य पर खर्च कर दिये हैं। इसके साथ ही मैं इनको यह भी बताना चाहूँगा कि टोटल 29.11 करोड़ रुपये वर्ष 2004-05 में डि सिल्टिंग के कार्य पर खर्च किए गए थे और उससे पहले वर्ष 2003-04 में 23 करोड़ रुपये इस काम पर खर्च हुए थे, वर्ष 2002-03 में 15.78 करोड़ रुपये और वर्ष 2001-02 के अन्दर 22.95 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। इस साल हमने 34.94 करोड़ रुपये की डि सिल्टिंग के काम के लिए खर्च कर दिए हैं। मैं समझता हूँ कि अभी भी

हमारे पास समय और भी पडा हुआ है लेकिन जो हम डि सिलिटिंग करवा रहे है उसमे ट्रांसपिरैसी लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आदे 1 से हमने एस0डी0एम0 के अण्डर एक कमेटी बनाई है। अब पेमेंट का ऐसा सिस्टम नही है कि मन मे आया जिस किसी को पेमेंट कर दी। अब सिस्टम यह है कि जब तक एस0डी0एम0 इन्डोर्स नही करेगा कि डि सिलिटिंग का काम अच्छी तरह से हो गया है तक उसकी पेमेंट नही होगी। यह जो टैंडर सिस्टम किया है उसमे अलग अलग एजेंसीज है जो अपने तौर पर अपने लैवल पर टैंडर सबमिट करती है और सारा खर्च उनके द्वारा किया गया है। उसमे पेमेंट बाकायदा तभी की जाती है जब एस0डी0एम0 उसका इन्डोर्स करता है उस कमेटी मे हमने नान आफिियल मैम्बर्ज बनाने का प्रावधान भी किया है जो गाद निकाली जाती है उसको हम चैक करवा रहे है और अगर कही पर किसी प्रकार की कोई गलती पाई जाती है तो हम उनके खिलाफ कार्यवाही करते है।

डा0 सीता राम: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि डि सिलिटिंग का काम पूरे प्रदे 1 मे चल रहा है। हम भी लोगो के बीच मे घूमते फिरते है लेकिन हमे कही पर भी ऐसा नही लगा कि पूरे प्रदे 1 मे डि सिलिटिंग का काम चल रहा है, नहरो और माईनर्ज की सफाई का काम चल रहा है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, अगर कोई स्पैसिफिक माईनर है तो उसके बारे मे आप बताईये।

डा० सीता राम: अध्यक्ष महोदय, डबवाली माईनर है, चौटाला माईनर है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, चौटाला माईनर नहीं है तो मेजर है।

डा० सीता राम: अध्यक्ष महोदय, डबवाली डिस्ट्रिक्ट ब्यूटरी है, वहां पर जाने के बाद मैंने देखा है कि वहां पर कोई काम नहीं हुआ है।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, प्रोपर सिरसा जिला के अन्दर इनकी सरकार के समय में 293.17 लाख रुपये खर्च किए गये थे। अभी 31 मार्च दूर है लेकिन हमने अब तक 269.50 लाख रुपये खर्च कर दिए हैं। इनके समय में रिवाड़ी में केवल 75 लाख रुपये में खर्च किए गए थे जब कि हमारे समय में 185 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको यह बताना चाहता हूँ कि इनकी सरकार की तरह हमने किसी भी कास्टीच्यूएंसी में भेदभाव की नीति नहीं अपनाई। इनके समय में पूरे हरियाणा प्रदेश के अन्दर केवल एक ही टेंडर हुआ करता था जबकि हमारी सरकार के समय में इस प्रकार की बात नहीं है। (विघ्न)

Mr. Speaker: Yadav Ji, what is your supplementary?

श्री नरे । यादव: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में डिसिल्टिंग का पैसा तो लग रहा है लेकिन जो मोस्ट इफैक्टिव एरिया नागल चौधरी और अटेली है, वहां पर पानी की बहुत दिक्कत है। क्या किसी एक मार्इनर का नाम ये बताएंगे जहां पर सफाई पर कार्य किया जा रहा है?

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं महेन्द्रगढ़ के बारे में बता रहा था। वहां पर पिछले साल 96.4 लाख रुपये पर खर्च हुए हैं।

श्री नरे । यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि ये मुझे सिर्फ नागल चौधरी और अटेली की किसी एक मार्इनर का नाम बता दे, कि इस मार्इनर पर काम हो रहा है या हुआ है।

Mr. Speaker: Yadav Ji, you ask separate question.

कैप्टन अजय सिंह यादव: नरे । यादव जी, आपको तो यह कहना चाहिए कि काम हो रहा है आप तो उल्टा गलतियों निकालने का काम कर रहे हो।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से सवाल है कि डिसिल्टिंग का क्या पीरियड निर्धारित किया हुआ है कि कब कब और कहा कहा पर डिसिल्टिंग की जाएगी? स्पीकर साहब, डिसिल्टिंग का जितना फंड है उसका मिसयूज होता है। जब बरसाते आती हैं तो नहरे चलने लग जाती

है लेकिन उसके थोड़े दिन पहले ही यहा पर यह काम किया जाता है जिसका कोई फायदा नहीं होता है मैं कैप्टन साहब की उस बात का एप्रीं टिएट करता हू कि जो इन्होने कहा है कि डिसिलिट के लिए एक कमेटी बनाई हुई है ।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि रबी, खरीब और पैडी की फसल की बोआई से पहले नहरो की सफाई करवाते है । अध्यक्ष महोदय, सभी नहरे डिफरेंट पीरियाडर्ज मे चलती है, उसके बंद होने पर हम उनकी सफाई करवाते है । हम साल मे पांच बार सफाई का काम भुरु करवाते है । जहा पर जिस वक्त सफाई की जरूरत होती है वहां पर उसी हिसाब से काम करवाते है ।

Irregularity committed in the Appointment of Class IV

343. Sh. Karan Singh Dalal: Will the Minister for Education be please to state-

(a) whether the State Government has received any complaint with affidavit in regard to the irregularities committed in the regularization/appointment of class IV employees in the Schools of district Mahendergarh during the year 2004 and 2005.

(b) whether any enquiry has been conducted in this regard, if so, the action taken thereon; and

(c) whether any responsibility has been fixed for the lapses; if so, details thereof and action taken against them?

Education Minister) Sh. Pholl Chand Mullana):

(a) Yes, Sir A complaint was received form Sh. Rajesh Kumar. JBT teacher, Govt. Primary School, Bass Khudana (Mahendergarh) in regard to the irregularities committed in the regularization/appointment of Class IV employees.

(b) Yes Sir, An enquiry was conducted into the matter by Sh. Anil Shrama HCS. Joint Director, Administration (Primary) On the basis of the enquiry report, show cause notices were issued to the concerned employees who were irregular employed. Thereafter, these employees filed a CWP No. 6241 of 2005 in the Hon'ble High Court and the Hon'ble High Court has quashed the orders of showcasue notices in its decision dated 25-4-2005. After further consideration , the Haryana Govt. has ordered a Vigilance Inquiry into the matter vide its memo No. 63/64/2004-VIG (II) dated 17-1-06. The inquiry report is still awaited.

(c) Yes. Sir, On the Basis of the departmental enquiry, 2 District Education Officers, 1 district Primary Education Officer, 6 Sub-Divisional Education Officers, 22 Block Education officers, 3 Principals and 14 Head Masters were found responsible for such irregularities. Before further action could be taken against these persons, the same complainant Sh. Rajesh Kumkar, JBT teacher. Govt Primary School, Bass Khudana (Mahendergarh) filed a fresh Public Interest Litigatin through CWP No. 1562 of 2005 in the Hon'ble High court and prayed for fresh enquiry. Accordingly, the Department has again ordered a fresh inquiry. Accordingly, the Department has again ordered a fresh enquiry

into the matter, by appointing Sh. Shish Pal Yadav, Joint Director O/o Commissioner & Director General Scholl Education Harayana, as Enquiry officer. In the meanwhile, the Haryana Govt, Vigilance Department Vide its memo No. 63/64/2004 VIG (II) dated 17-1-06 has also ordered Vigilance Inquiry into the matter. Action would be taken after receipt of the Inquiry report. (s)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो जानकारी इन्होंने सदन के पटल पर रखी है वह साफा तौर पर यह दर्शाती है कि क्लास आई0वी0 के इम्प्लॉयर्स की भर्ती पर 1996 में पाबन्दी होने के बावजूद गैर कानूनी तरीके से भर्ती की गई। मंत्री जी ने अपने जवाब में भी माना है कि कई अधिकारी इसमें शामिल हैं जिन्होंने प्रदेश के खजाने को नुकसान पहुंचाने के लिए गैर कानूनी लोगों को भर्ती करने की एक साजिश की थी। इसमें डी0ई0ओज0, बी0ई0ओज0 और एस0डी0ओज0 शामिल हैं। उन्होंने पिछली सरकार के राजतंत्र की मिली भगत से यह काम किया है। उनकी मिलीभगत के बिना यह काम हो नहीं सकता। मैं शिक्षा मंत्री जी से यह आशा करता हूँ कि जो भी बड़े अधिकारी उसमें शामिल थे और राजतंत्र से जुड़े हुए लोग थे, क्या उनको कानूनी तौर पर ये सजा दिलवाएंगे ?

श्री फूल चंद मूलाना: अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैंने पिछले सत्र में एक सवाल के जवाब में भी बताया था। अध्यक्ष महोदय, उनका तो वही हिसाब है कि एक बार एक तारीख बोलो,

रमलू तने रोल्यू ।तो रमनू बोला ताई ईबे क्या तू आगे आगे देखी जा और तूं रोई जा। स्पीकर सर, जहां पर भी कोई गडबडी सामने आती है तो यह सारी भर्ती उन ओम प्रका । चौटाला के राज की ही है चाहे आपराधिक मामले वाले अध्यापको की बात हो यह चाहे फोर्थ क्लास कर्मचारियो की भर्ती की बात हो, यह सब उन्ही के समय की है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड की बात है। हमारे पास लिखा हुआ है । अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुडा, की सरकार की जांच के आदे । दिए और जहांच के बाद कई सारे लोग दोशी पाए गए। वे हाई कोर्ट मे चले गये। हाई कोर्ट ने यह नोटिस क्वै । कर दिया और कहा कि इसको दोबारा सुना जाए। जब दोबारा सुनवाई की गयी तो फिर एक बार रिट पैटी ।न हाई कोर्ट मे हो गई और हाई कोर्ट ने फिर कहा कि इसकी दोबारा जांच की जाए। अध्यक्ष महोदय, दोबारा जांच हो रही है और जाच मे जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि इनमे दोशी और भी हो सकते है लेकिन जहां के दौरान जो कोई भी यदि दोशी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक और आ वासन लेना चाहता हू कि जिस ि ।कायतकर्ता ने इस बारे मे ऐफ़डेविट दिया था वह इनके विभाग मे एक अध्यापक है। उसकी सुरक्षा के लिए या उसको कोई नुकसान न हो तो क्या ये इस बारे मे भी गौर करेगे?

श्री फूल चन्द मुलाना: अध्यक्ष महोदय, जो भी िाकायतकर्ता है उसकी िाकायत पर ही यह सारी कार्यवाही हो रही है इसलिए उसको पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

Replacement of Electricity old wires and conductors

352. Maj. Nirpender Singh Sangwan: Will the Minister for Power be please to state-

(a) whether there is any proposl under considerationof the Government to replace the obsolete electricity wires & conductors of the villages of Dadri constituency; and

(b) if so, by what time the aforesaid proposal is likely to be materialized?

Power Minister (Sh. Vinod Kumar Sharma):

(a) Yes Sir, the obsolete and worn out the electricity conductors are being regularly removed and replaced with new conductiors as and when required. The Scheme for replacement/agumentation of Conductors of 5 No. of feedersin Dadri Area have been prepared.

(b) The replacement of obsolete consuctors of 5 No. 11 KVfeeders will ve completed by December, 2006.

श्री एस0ए0 सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, बिजली के कंडक्टर्ज के बारे मे मंत्री जी ने यह बताया कि the obsolete and worn out electricity conductiors are being regularly removed and replaced with new conductors. यह बहुत अच्छी बात है

क्योकि यह काम पन्द्रह साल या दस साल से भुरु किया गया है। इनकी हालत बहुत खराब है। गांवो मे कई जगहो पर बिजली की तारे लटकी हुई है जिसकी वजह से ऐक्सीडैटस होते है। मै आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी आपके यह बात नोटिस मे है कि डिपार्टमेंट ने एक रेडीक्यूलेटिज तो मै नही कहूंगा लेकिन एक बडा अजीब सा फैसला ले रखा है कि जब ट्रासफार्मर जल जाएगा तो उसको रिप्लेस करेगे? जलने से पहले अगर उनसे कहते है वह ट्रासफार्मर 100 के0वी0ए0 का है और उस पर 150 या 200 के0वी0ए0 लोड है इसलिए उसको 200 के0वी0ए0 का कर दे तो यह बात जानते हुए भी कह देते है कि हम मजबूर है ऊपर से हुक्म है हम इसको जलने ही दे और जलने के बाद ही इसको बदलेगे तथा हम इसको जिन्दा रिप्लेस नही कर सकते। यह बडी गलत नीति है क्या मंत्री जी इसको चेंज करेगे? अध्यक्ष महोदय, जो ओवर लोड ट्रासफार्मरर्ज है क्या मंत्री जी रिप्लेस करवाऐगे?

श्री विनोद कुमार भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति कही कही हो सकती है कि जहां पर ओवर लोडिंग होती हो। लेकिन हमारे पास ऐसे कोई भी साधन नही है जो हमे बता सके कि कौन से ट्रासफार्मर पर कब ओवर लोडिंग हो जाएगी। कौन कौन से लोग बिजली का इस्तेमाल कर रहे है और कहां कहां पर कितने ओवर लोडिंग है इसका कोई अन्दाजा पहले से नही लगाया

जाता। अध्यक्ष महोदय, जितनी जरूरत होती है तो जरूरत के हिसाब से ही ही हम ट्रांसफार्मर लाईन पर लगाते हैं अगर कहीं पर ितकायत है या अगर कहीं पर हमें पता चले कि रैगुलेर बेसिज पर ओवर लोडिंग हो रही है तो वहां पर ट्रांसफार्मर की रिप्लेसिंग की जाती है।

मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि कंडक्टर 40 सालो से भी ज्यादा पुराने हैं और मेरे हल्के के सभी गावों में कंडक्टर लूज हैंग हो रहे हैं जिससे रोजना कोई न कोई हादसा हो जाता है। कभी ये तारे किसी ट्रैक्टर के आगे अड जाती हैं तो कभी किसी और गाड़ी के आगे अड जाती हैं खेतों में जो कंडक्टर लगे हुए हैं वहां पर भी कोई न कोई हादसा हो जाता है खड़ी फसले जल जाती हैं यहाँ कहीं कोई मवेशी मर जाते हैं। मैं चाहूँगा कि इन कंडक्टर को जल्दी से जल्दी कार्यवाही करके बदला जाए। अगर इनको जल्दी नहीं बदला गया तो ये हादसे रोजना होते रहेंगे। जहाँ तक कम्पनसैशन की बात है तो यह भी उनको नहीं मिलता, इसके लिए सालो उनके केस बिजली के मकहमें चलते रहते हैं। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि ट्रांसफार्मर पर कहीं भी ओफ एण्ड आन स्विच नहीं लगे हुए हैं। तारे भी बहुत कमजोर हो चुकी हैं। मकहमें वाले इनको टाइट करने की कोशिश करते हैं तो वे टूट जाती हैं ये तारे किसी के

घर की छत पर, सडक या गली मे आकर गिरती है जिससे नुकसान का खतरा रहता है।

श्री अध्यक्ष: मेजर साहब, आप सप्लीमैटरी पूछे।

मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवान: अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हू कि जब तक हर ट्रांसफार्मर पर आफ एण्ड आन स्विच नहीं लगाए जाएंगे तब तक ये हादसे बन्द नहीं होंगे। इसलिए मैं मंत्री महोदय में जानना चाहूंगा कि ट्रांसफार्मर पर आफ एण्ड आन स्विच कब तक लगाए जाएंगे?

श्री विनोद कुमार भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब में भुरु में ही बताया है कि दिसम्बर, 2006 तक सभी कंडक्टर रिप्लेस कर दिए जाएंगे। जहां तक माननीय साथी ने आफ एण्ड आन स्विच की बात की है तो मेरी समझ में तो ऐसा कोई स्विच नहीं है ट्रिपिंग की बात तो समझ में आती है।

मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवान: अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हू कि जहां तक बिजली आगे जा रही है वही से बन्द कर दी जाये।

श्री विनोद कुमार भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से साथी से पूछना चाहता हू कि वे हाई टेंशन लाईन्स की बात कर रहे हैं या लो टेंशन लाईन्स की बात कर रहे हैं या 33 केवी सब स्टेजों की बात कर रहे हैं ये बताने का कष्ट करें?

मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से कहना चाहूंगा कि मैं लो टै इन लाईन्स की बात कर रहा हूँ जिससे बिजली सप्लाई हो रही है।

श्री विनोद कुमार भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा स्विच नहीं है जिससे चलती तार को कहीं भी किसी वक्त आफ या आन किया जा सके।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान: अध्यक्ष महोदय, यहां बार बार 700 करोड़ रुपये की राजीव गांधी ग्रामीण योजना का जिक्र आता है कि 700 करोड़ रुपये से इन तारों की बदला जाएगा। क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा योजना है कि पूरे राज्य की लाईनों को बदलने की कांस्ट को आंका जा सके? देहातो में तारों की हालत बहुत बुरी है। बिजली विभाग के किसी एक्स0इ0एन0 या एस0इ0 या किसी और अधिकारी को कहते हैं कि इस गांव में यह हादसा हो गया है इसलिए ये तारे बदल दी जाये तो वे अपनी लाचारी का जिक्र करते हैं और इसी 700 करोड़ रुपये का जिक्र करते हैं कि 700 करोड़ रुपये की स्कीम आने वाली है इसलिए मैं मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि बेहतर यह होगा कि आप सारे जिले की तारों की कीमत को आंककर बाकी के पैसे के लिए वित्त मंत्री महोदय से कहे क्योंकि उन्होंने सारे हरियाणा स्टेट के लिए बिजली के लिए बहुत पैसा रखा है।

श्री विनोद कुमार भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी की बात से सहमत हूँ। जहाँ तक कन्डक्टर्स को बदलने की बात है तो हमने 2004-2005 में 1700 किलोमीटर के कन्डक्टर्स बदले हैं और 2005-06 में 2345 किलोमीटर कन्डक्टर्स बदले गये हैं। इस प्रकार हमने पिछले साल के मुकाबले आलमोस्ट 33 प्रतिशत ज्यादा कन्डक्टर्स बदले हैं और आने वाला समय में और भी ज्यादा कन्डक्टर्स को बदलने की कोशिशें करेगे।

श्री भादी लाल बत्रा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि कन्डक्टर्स और ट्रांसफार्मर जो फील्ड में लगे हुए हैं उसकी नार्मल लाईफ कितनी है और अगर उनकी नार्मल लाईफ पूरी हो गई है तो उनको बदलने की सरकार की क्या योजना है?

श्री विनोद कुमार भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि मेरे कन्डक्टर्स के बारे में तो जवाब देना बहुत मुश्किल है लेकिन पता लेगे कि कितने हजार किलोमीटर कन्डक्टर्स लगे हुए हैं और उनमें से कितने पुराने हैं और कितने बदलने वाले हैं इसका विश्लेषण करवा लिया जायेगा।

श्री दूडा राम: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या खेतों और ढाणियों में

बिजली के कनेक्टान देने के बारे में सरकार की कोई योजना है ?

श्री विनोद कुमार भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि अगर कनेक्टान के लिए हमारे पास कोई भी एप्लीकेटान आयेगी तो उस पर विचार किया जाएगा।

श्री अर्जन सिंह: अध्यक्ष महोदय, जिन किसानों ने ट्यूबवैल के कनेक्टान लेने के लिए 15-20 साल पहले सिक्योरिटी बरी थी उनको कनेक्टान नहीं दिए गए, उनकी सिक्योरिटी कैसिल कर दी गई है और नई स्कीम के तहत पैसे लेकर ट्यूबवैल के कनेक्टान दिए जा रहे हैं जो गरीब किसान हैं वे इतना अधिक पैसा नहीं दे सकते। क्या उन किसानों को जिन्होंने 15-20 साल पहले सिक्योरिटी बरी थी उनको बिना पैसे जमा करवाये पिछली सिनियोरिटी के आधार पर ट्यूबवैल के कनेक्टान दिए जायेंगे? इसके साथ साथ मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि मेरे हल्के मैं बिजली की तारे बहुत लूज हैं जिसके कारण बीचपुडी, लाकडमय प्रतापपुर, खदरी टप्पू माजरी आदि कई गावों के फूस के मकानों में आग लग गई। इसके कारण ही कई पुा जल गये। एक औरत इतनी अधिक मात्रा में जल गई कि उसे पी0जी0आई0 चण्डीगढ में भर्ती करवाना पडा और आज भी वह वही भर्ती है। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना

चाहता हू कि मेरे हल्के मे जो बिजली की तारे लूज है उनको कब तक बदला जायेगा ?

मुख्यमंत्री (चौ० भूपेन्द्र सिंह हुडा): अध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे कई माननीय सदस्यो सवाल उठाये है। मै पूरे सदन की जानकारी मे लाना चाहूंग कि हम राजीव गांधी ग्रामीण विधुत योजना के अंतर्गत 700 करोड रूपये की परियोजना भुरु कर रहे है जिसमे 84 करोड रूपये की मंजूरी हो भी गई है। आने वाले पांच साल तक यह योजना पूरी की जायेगी। उसके बाद बिजली के क्षेत्र मे किसी तरह की कोई दिक्कत नही रहेगी।

Releasing of Electricity Connections to Tubewells

396. Sh. Naresh Yadav: Will the Minister for Power be please to state-

(a) the total number of electirictiy connections to tubewells for agricultural sector release in district Mahendergarh during the period for 2004 to 2005 togetherwith the details of total number of applications for such electricity connections lying pending at present in the said district; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to formulate any new and simple policy to release the electricity tubewell connections for agriucultural sectors; if so, the details thereof?

Power Minister (Sh. Vinod Kumar Sharma):

(a) Sir, during the financial year 2005-05 and 2005-06 up to 2/2006 in Mahendergarh district 460 and 491 tubewell connections respectively were release, 934 No. tubewell connections are lying pending for release as on 28-2-2006.

(b) As per policy, the work of release of tubewells connections is being got done on turn key basis. for which all the material except Transformers is being supplied by the contractor. It is expected that the pendency of Tubewells as on 28-2-2006 will be cleared by 30-9-2006.

श्री नरे । यादव: अध्यक्ष महोदय, पहली बात मैं यह कहना चाहता हू कि किसानों ने अपने ट्यूबवैल्ज के लिए बिजली के कनेक्टान लेने के लिए एक डेढ साल से पैसे भरे हुए हैं। जिन किसानों को इतना समय पैसे भरे हुए हो गया और जिनको अब तक कनेक्टान नहीं मिले है क्या सरकार उनको जो पैसा उन्होंने भरा है, उस पर ब्याज देगी? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हू कि अब ठेकेदारी द्वारा बिजली के कनेक्टान देने के लिए रि वत लेते थे, अब ठेकेदारों के लोगों को किसान पहले अपना नम्बर लगवाने के लिए पैसे देते हैं। अगर उनको पैसे नहीं दिए जाते तो वे कनेक्टान देने में डिले कर देते हैं क्या उन पर सरकार कोई कार्यवाही करेगी?

श्री विनोद कुमार भार्मा: अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे साथी ठेकेदारों द्वारा पहले कनेक्टान देने की बात कह रहे हैं इस बारे में मैं मेरे साथी को बताना चाहूंगा कि ठेकेदारी को विभाग

की तरफ से नम्बरिंग दी जाती है उसी हिसाब से वे कनैक्शन करते हैं। अपने हिसाब से वे कनैक्शन पहले या बाद में नहीं कर सकते। जहाँ तक पैसे जमा करवाने की बात है एक डिमांड नोटिस के अग्रेन्सट 20 हजार रुपये जमा करवाये जाते हैं और पर स्पैन के हिसाब अलग पैसे जमा करवाये जाते हैं। महेन्द्रगढ़ जिले में अब तक जो ट्यूबवैल्व के कनैक्शन दिए गए हैं उनकी जानकारी मैं अपने लोगों ने 20 हजार रु० जमा करवाये थे। इनमें से 4637 लोगों ने आगे की रिक्वायर्ड अगाउंट जमा करवाई थी। इसलिए इसमें से 4090 कनैक्शन रिलीज हो गये हैं और 547 कनैक्शन अभी वीडिंग है।

श्री राम किशन फौजी: अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि हमारी सरकार ने ट्यूबवैल्व के कनैक्शन के रेट कम किए हैं लेकिन अब भी ऐसे छोटे किसान हैं जिनके पास एक या दो एकड़ जमीन ही है और वे अब भी ट्यूबवैल्व के कनैक्शन के पैसे नहीं भर सकते। क्या ऐसे छोटे किसानों की सरकार कोई राहत देगी ताकि वे भी अपने ट्यूबवैल्व लगा सकें? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने बताया कि राजीव गांधी जी के नाम से बिजली की योजना चलाई जायेगी जिसके तहत किसानों को ट्यूबवैल्व के कनैक्शन भी दिए जायेंगे। उसके तहत विभाग वाले कहते हैं कि 6 या 7 खम्बों में ज्यादा का एस्टीमेट नहीं बनाया जायेगा और एक गांव की एक ढाणी में ही इस योजना का लाभ दिया जायेगा। लेकिन कई जगह तो एक गांव की दसस बसस या

पचास पचास ढाणिया होती है। क्या हम ढाणी मे इस योजना के तहत कनैव ान देने का प्रावधान किया जायेगा?

15.00 बजे

श्री विनोद कुमार भार्मा: अध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि आज किसान को कनैव ान देने के लिए पैसे देने पडते है लेकिन यह भी सही है कि बिजली हमे बाहर के प्रदे ा से भी खरीदनी पडती है। जितनी बिजली हम बनाते है उससे कही ज्यादा बिजली को खपत हमारे प्रदे ा मे है। सरकार की कोर्ि ा ा यह है कि किसान को बिजली की किल्लत महसूस न हो और फसल को बनाने के लिए जितनी बिजली की जरूरत है उतनी बिजली उसको मिलती रहे इस तरफ सरकार का हमे ा से प्रयास रहा है। अगर हम यह सोचे कि किसी और ऐरिया मे बिजली कम दे कर किसानो की बिजली की आपूर्ति करे तो मै समझता हू कि यह सम्भव नही है।

श्री सोमवीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय मत्री जी से यह जानना चाहता हम कि ट्यूबवैल के जो कनै ान्ज दिये जाते है उसमे ट्रांसफार्मर्ज लगाए जाते है और ट्रांसफार्मर्ज मे जी०ए० स्विच चेंज आफ स्विच लगता है उसके लिए किसान से पैसे भी लिये जाते है पिछले पांच साल मे जिनको बिजली के ट्यूबवैल के कनैव ान्ज मिले है उनसे पैसे ले लिये गए है लेकिन जी०ए० स्विच नही लगाए गए है। जमीदार बार बार

चक्कर लगाते रहते हैं लेकिन उनको जी०ए० स्विच नहीं मिलते हैं। महीने में एस०डी०ओ० हैड क्वार्टर पर दो तीन जी०ए० स्विच आते हैं। लेकिन जो कर्मचारी हैं वे अपनी मर्जी से चलाते हैं और जहा चाहे लगा देते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या वे कोई टाईम लिमिट तय करेंगे कि वे जी०ए० स्विच कब तक पूरे लगवा देंगे?

श्री विनोद कुमार भार्मा: अध्यक्ष महोदय, पिछले पांच साल की बात तो हमारे सामने बैठने वालों के भासनकाल की बात है अगर इनके समक्ष ऐसी कोई बात है तथा खास तौर पर अगर ये यह बता सकेंगे कि पैसा लेने के बाद कहां से पर इस प्रकार के स्विच नहीं लगे हैं तो उस पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री सोमवीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह मेरी अपनी कास्टीच्यूएंसी की बात है। मैं लोहारू की बात कह रहा हूँ। मेरे लोहारू डिवीजन में ढिंगावा सब डिवीजन तथा बहल सब डिवीजन में आधे से ज्यादा टयूबवैल्ज ऐसे हैं जहां पर चेज आफ स्विच नहीं लगे हैं।

श्री विनोद कुमार भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहता हूँ कि अगर वे लिखकर भिजवा दें कि कहा पर मैं स्विच नहीं लगे हैं तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। (विधन)

श्री राधे भयाम भार्मा अमर: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि महेन्द्रगढ जिले मे 934 ट्यूबवैल्ज के कनैक् ान्ज पैडिंग है और लगभग तीन तीन साल से यह पैडिंग चल रहे है। बिजली की कमी तो मजबूरी है लेकिन जो कनैक् ान नही मिल रहे है यह सामान की कमी की वजह से नही मिल रहे है। मै माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हू कि वहां पर बिजली के पोल्ट्ज तथा ट्रांसफार्मर्ज नही है क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगे कि वहां पर से जिन किसानो की फसले खराब हो रही है क्या उन किसानो का भला किया जाएगा तथा सरकार उनके बारे मे क्या सोच रही है ?

श्री विनोद कुमार भार्मा: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन को मैने इस प्र ान के उतर मे बताया था कि दिनांक 30.9.2006 तक महेन्द्रगढ जिले मे जो पैडिंग कनैक् ान्ज है उनको पूरा कर दिया जाएगा।

श्री० छतर पाल सिंह: स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बहुत ही अच्छी योजना के तहत 1600 करोड रूपये बिजली के बिलो की माफी दी थी और उसमे किसानो और मजदूरो को बडा भारी लाभ हुआ था। मै आपके माध्यम से माननीय पावर मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हू कि अभी इस बारे मे कुछेक रिक्वैस्ट्स आती रहती है क्या डेट एक्सटैंड करने के बारे मे कोई विचार सरकार कर रही है?

Sh. Vinod Kuamkr Sharma: The date has been extended up to 31st , March 2006.

Prof. Chhattar Pal Singh: Thank you very much.

Memorial in the name of Kargil Heroes

434. Sh. Dharampal Singh Malik: Will the Chief Minister for Power be please to state whether there is any proposal under consideration of the Government to establish any memorial in the name of Kargil Heroes in the State?

Transport Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala): A state Level War Memorial exists at Rohatk where names of War Heroes of all the war, including Kargil War, are being engraved. In addition, War Memorial at distircit level would be set up where the names of all war Heroes of that particular district shall be engraced. At present 14 district level War Memorials exist in Haryana.

(इस समय कई माननीय सदस्य अपनी सीटो पर खडे होकर बोलने लगे ।)

Mr. Speaker: Mr. Indora, maintain the decorum of the House. (Noises and interruptions) इन्दौरा साहब, आप बहुत ही सुलझे और तजुर्बेकार व्यक्ति है अभी सभी लोग अपनी सीटो पर बैठे तथा हाउस मे डैकोरम को बनाए रखे । Malik Sahib, Please ask your supplementary.

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, जो लोग कारगिल मे भाहीद हुए है उनके नाम अकित करने के बारे मे

जवाब मिला है। मैं मंत्री जी आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार की कोई ऐसी पालिसी है जिसके तहत उन भाहीदों के नाम से सड़को, स्कूलों, कालेजों, और अस्पतालों के नाम रखे जा सकें? जैसे भाहीद होठियार सिंह के नाम पर एक दस जमादों स्कूल का नाम रखा गया है। अगर सरकार ऐसी करती है तो आने वाले समय में हमारे बच्चे उन भाहीदों को जान सकेंगे। जैसे आपने इन विजय में हमारे हरियाणा के बहुत से लड़के भाहीद हुए हैं। क्या उनके लिए ऐसे मैमोरियल बनाने का सरकार का कोई विचार है?

Sh. Randeep Singh Surjewala: Sir, this is a separate question. इस बारे में माननीय साथी जी अलग से लिख कर दें। (गौर एवम व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री० भूपेन्द्र सिंह हुडा): अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री से यही पूछा है कि कारगिल के हीरो के नाम से हास्पिटल के नाम, स्कूलों, कालेजों के नाम या सड़कों के नाम रखने का विचार सरकार का है कि नहीं है? मैंने सिर्फ यही पूछा था। इसके जवाब में मंत्री जी ने कह दिया कि सैप्रेट में इन पूछें। इसके लिए सैप्रेट में इन देने की कोई जरूरत नहीं है। मंत्री जी सिर्फ यही बता दें कि कोई जरूरत नहीं है। मंत्री जी सिर्फ यही बता दें कि क्या ऐसा कोई विचार सरकार के विचाराधीन है कि नहीं?

Mr. Speaker: Malik Sahib, please ask your supplementary.

Shortage of Electricity

360. Dr. Sushil Indora: Will the Minister for Power be please to state.

(a) whether it has been decided by the Government to purchase the electricity from other States; during the current financial year to meet out the shortage of electricity; if so, the names of the States and the quantum of electricity to be purchased from each State; and

(b) will the requirement of electricity of the State be met out from purchasing of electricity?

Power Minister (Sh. Vinod Kumar Sharma):

(a) Yes Sir, a Statement is laid on the Table of the House.

(b) No, Sir.

Statement

The details regarding quantum of electricity purchased from other States alongwith the names of each state are as given below:-

Details of Biollateral Arrangemnet for Short term Power Purchased from Licenced Traders & Surplus Power States for the year 2005-2006 (Up to Feb. 06)						
Sr. No.	Names of Traders/Suppliers	Project/s ource of power	Quantium type of power	Form	To	Quant um of power

						received (Lus)
1.	Tata Power Trading co Ltd.	Hindustan Zins Ltd. (Rajasthan)	35 MW (Round the Clock)	1-6-05	30-6-05	68.05
2.	Uttranchal Power Co-op-Ltd	Uttranchal	75 MW off peak (20 Hrs.) to bank June Sept. 05 & Banked out at 105% from Nov. 5-March-06	11-6-05	31-3-06	Banking
3.	Govt. of Himachal Pardesh	Nathpa Jhakri Power Project	9% of energy generated (Ex Bus) of NJHPS	1-7-2005	31-10-05	654.73
4.	PTC India Ltd.	Gujarat Power	100 MW off Peak 18hrs	1-7-05	10-9-05	820-08
5.	PTC India Ltd.	Gujarat Power	200 MW off Peak 6 hrs 300 MW off peak 18 hrs (As & when	1-7-05	10-9-05	820-08

			available power)			
6-	Adani Exporst Ltd/	WBSEB Power	1500 MW of peak 6 hrs. (11-00 - 17.00)	22-6-2005	30-6-05	77-044
7.	PTC India Ltd.	AP Power	135 MW of peak 3 hrs. (00-00 - 3000 hrs)	5-6-05	8-6-05	15-70
8.						

डा0 सु गीला इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, मैने जो सवाल पूछा है उसके बारे मे मंत्री जी ने स्टेटमैट सदन के पटल पर रखी है इसमे काफी विस्तार से बताया है कि इन्होने किस किस प्रदे ा से कब कब, कितनी कितनी बिजली किस किस रेट पर खरीदी है । मै इस बारे मे मंत्री जी से जानना चाहता हू कि हरियाणा प्रदे ा के लोगो के लिए बिजली की आपूर्ति करने के लिए क्या सरकार ने कोई लॉग टर्म इन्तजाम किया है? अगर किया है तो किस रेअ से किया है और कब तक का किया है ? इसके साथ ही मंत्री जी यह भी बताए कि हरियाणा के लोगो को कितनी बिजली की

जरूरत है और उसकी पूर्ति करने के लिए सरकार के क्या इंतजाम किया है?

श्री विनोद कुमार भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हम अपने प्रदेश में जो बिजली पैदा करते हैं उसके अलावा हम दूसरे सोर्सिंज जैसे बीबीएमबी, एलएचपीसी, एनटीपीसी, एनपीसी, आईपी, मैगनम आदि से बिजली लेते हैं वह 4 हजार 33 मैगावाट है। जबकि हमारी बिजली की खपत इससे भी कहीं ज्यादा है। उस खपत को पूरा करने के लिए हम समय समय पर दूसरे सोर्सिंज से बिजली खरीदते रहते हैं। पिछले 15 महीनों में यह देखा गया है कि प्रदेश में जब बिजली की कमी महसूस हुई तो यह हरियाणा में नहीं हुई है बल्कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और दूसरे कई प्रदेशों में भी कमी महसूस हुई है। स्पीकर साहब, बिजली खरीदने के लिए जहाँ भी बिजली अवेलेबल है, हम वहाँ से बिजली लेने की कोशिश करते हैं। कई बार पीक सीजन में बिजली महंगे रेटेस पर भी खरीदनी पड़ती है। मेरे माननीय साथी को जो सवाल है कि हम आगे आने वाले समय के लिए क्या कर रहे हैं ताकि बिजली की कमी की पूर्ति की जा सके। अध्यक्ष महोदय, हमने लॉग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों मैथड अपनाये हैं। अपने प्रदेश में बिजली की पैदावार बढ़ायी जा सके उसको देखते हुए बहुत से प्रोजेक्ट टेकअप किए गए हैं जैसे यमुनानगर में हमारा जो पावर जेनरेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है वह

भायद दो ढाई साल मे पूरा हो जाएगा, इसके अलावा हिसार मे और फरीदाबाद मे भी हमने दूसरे पांव प्रोजैक्ट्स रखे है जिनसे हम चार हजार मेगावाट बिजली आने वाले चार पांच साल मे पैदा करने की क्षमता रखेगे। हम यह नही कह सकते कि कितनी बिजली हमे दूसरे प्रदे गो से मुतवातर मिलती रहेगी क्योकि जितनी बिजली की डिमांडज है हम उसके हिसाब से ही बिजली को खरीदते रहेगे। अध्यक्ष महोदय, जितनी बिजली हमे दूसरे प्रदे गो से उपलब्ध होगी उतनी बिजली हम अपने किसानो के लिए अपने हरियाणा के निवासियों के लिए खरीदने की कोशिश करते रहेगे।

डा० सु गीला इंदौरा: अध्यक्ष महोदय जी, यमुनानगर के पांवर थर्मल प्लांट के बारे मे इन्होने कहा कि इस पर काम चल रहा है। मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हू कि इनके अलावा पूरे हरियाणा प्रदे गो मे क्या आज के दिन किसी और जैनरे इन पावर प्लांट पर काम चल रहा है?

श्री विनोद कुमार भार्मा: अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हिसार के पवार प्लांट की प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनाने का कार्य भुरू हो चुका है। यह प्लांट एक हजार से लेकर 1200 मैगावाट का होगा। दिसम्बर तक हम यह प्रोजैक्ट रिपोर्ट कम्पलीट कर लेगे और आर्डर प्लेस कर देगे। इसके तीस महीने के बाद यह प्लांट अपनी क्षमता के मुताबिक प्रोडक्शन मे आ जाएगा।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा): अध्यक्ष महोदय, बिजली की समस्या आज के दिन हरियाणा के लिए सबसे प्राथमिकता देने वाली है। जिसके कारण हरियाणा के लोग परेशान हैं। लेकिन यह तथ्य है और यह कहते हुए मुझे बड़ा अफसोस भी होता है कि चालीस साल हरियाणा बने हुए हो गये हैं लेकिन हरियाणा की बिजली क्षमता केवल चार हजार मेगावाट ही है। कई कई साल लोग भासन में रहे हैं लेकिन किसी ने भी बिजली के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ नहीं सोचा है। आज कुल क्षमता चार हजार मेगावाट ही है जबकि मांग नौ हजार मेगावाट के करीब है। इस तरह से बड़ी भारी गैप है और इसी कारण हमें अलग अलग जगहों से बहुत महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, जब से यह सरकार आयी है तब से सरकार ने इस तरफ बहुत ध्यान दिया है। जितनी बिजली क्षमता चालीस साल से है हम अपनी योजना के अनुसार उतनी ही बिजली की क्षमता आने वाले चार साल में हरियाणा में पैदा करेंगे। इसमें 600 मेगावाट यमुनानगर में 1065 मेगावाट फरीदाबाद में एक हजार मेगावाट हिसार में और पांच सौ मेगावाट पैटेको से पानीपत में होगी। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है कि हमारी पाईप लाईन से और भी क्षमता है। मैं भी बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ कि हमारे लिए यह बड़ी तकलीफ वाली बात है कि पिछले चालीस साल से आज तक केवल चार हजार मेगावाट बिजली पैदा करने करने की ही क्षमता हरियाणा की है। इस बात को सबको देखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हर साल महंगी बिजली

खरीदनी पडती है। पिछले साल भी बिजली की दिक्कत हुई थी इसलिए हमने पिछले साल भी बिजली खरीदनी थी। हमने पिछले साल भी उससे पिछले साल से ज्यादा बिजली खरीदकर लोगों को दी। लेकिन मांग लगातार बढ़ रही है और आगे यह और भी बढ़ेगी। इस स्थिति को देखते हुए हमारा बिजली की क्षमता बढ़ाने का पूरा प्रयास है लेकिन हमें आप सबके सहयोग की जरूरत है।

Draining out of Rainy Water

354. Shri. Ranbir Singh Mahendra: Will the Minister for irrigation be please to state.

(a) what are the number of regular drains to drain out the rainy water area of Dhanana, Talu, Mundhal Khurd, Mundhal Kalan, Sukhpura, Jatai, Badesaram Ghuskani, Mitathalm Gurjrani, Chang, Baund Kalan, Unn, Nimri, Sankror and Ranila Villages of District Bhiwani; and

(b) whether these drains were desilted internally in the year 2005-06, if so, in which month these were desilted toghetherwith the steps taken or proposed to be taken to save the said villages from flood?

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav): Sir, the information is placed on Table of the House.

Information

(a) Sir, at present there are 36 no. regular drains in use for draining out rain/flood water from these area of villages of district Bhiwani in question.

(b) Yes Sir, All 36 no. drains were internally cleared during the period from May, 2005 to August, 2005. Apart from this, construction of Mundal Talu link, Jatai drain, Tigrana link drain, Prem Nagar drain increasing capacity of Dhanana drain no. II and extension of Gujrani drain are in progress which shall provide relief to the affected area. The schemes are estimated to cost about Rs. 925 lacs and are likely to be completed before the coming rainy season.

In addition, schemes for Mitathal drain No. 2, Baund drain, Unn drain, Hindal drain, Kharak drain extension and remodeling of Keylanga drain No. 2 Linking Bhaini Jatan drain, Ditch drain along Kunger minor, Thakran link drain, Siwana link drain and procurement of additional pumping sets are proposed to be implemented.

श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इन ड्रेन्स के होते हुए पिछले साल बाढ़ से काफी बुरी हालत हो गयी थी इसलिए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या कोई नई ड्रेन्स बनाने का प्रोजेक्ट भी किया गया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इनके एरिया में टोटल 30 रेगुलर ड्रेने हैं, इसके अलावा चार नई ड्रेने हैं जिन पर काम चल रहा है जिनमें से पहली ड्रेन है मुण्डाल तालू लिंक ड्रेन जिस पर 500.19 लाख रुपये लगेंगे। दूसरी जतैई ड्रेन है जिस पर 103.7 लाख रुपये लगेंगे। तीसरी तिगडाना लिंक ड्रेन है जिस पर

87.86 लाख रूपये लगेगे। इससे तिगडाना और घूसखानी गावों को लाभ होगा। चौथी प्रेम नगर ड्रेन है जिस पर 57.40 लाख रूपये लगेगे। इन चारो ड्रेनो पर काम चल रहा है। दो ड्रेने और है जिन पर काम चल रहा है। एक धनाणा ड्रेन है जिस पर तकरीबन 96.53 लाख रूपये खर्च होगा और दुसरी गुजरानी ड्रेन है जिस पर 16.36 लाख रूपये लगेगे। इस प्रकार 924.73 लाख रूपयं का आलरेडी काम चल रहा है। इसके अलावा अभी हाल ही जो स्टेट फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग हुई है उसमे हमने 10 ड्रेने और ली है जिनमे से एक तो मिथतल ड्रेन है जिस पर 25.70 लाख रूपये खर्च होंगे और दूसरी बाँद ड्रेन है, जिस पर 235 लाख रूपये होंगे और उन ड्रेन पर 88.49 लाख रूपये लगेगे। टोटल 10 ड्रेनो पर 1204 लाख रूपये लगेगे जिसका जिकर मैं अपने जवाब मे पहले ही कर चुका हू। मैं समझता हू कि इन ड्रेनो के बनने के बाद इनके यहा फ्लड की समस्या का काफी समाधान हो जायेगा।

श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि यह ड्रेन कब तक तैयार हो जायेगी ?

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यमसे माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि पूरी कोशिश करेंगे कि ये ड्रेने जून के महीने तक तैयार हो जाये। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये जून के महीने तक तैयार हो जायेगी। फिर

भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि बरसात के होने से पहले पहले इन ड्रेनो का जितना काम पूरा हो सके, करवा दिया जाये।

Opening fo Government College of Bawani Khera

386. Sh. Ram Kishan Fauji: Will the Minister for Education be please to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government College at Bawani Khera?

श्री राम किशन फौजी: अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी होती अगर मंत्री मेरे प्रश्न का जवाब हां सर मे देते। इनको जवाब हां मे देना चाहिए था क्योंकि हमारी सरकार का शिक्षा की तरफ काफी ध्यान है। अध्यक्ष महोदय, हमारे बवानी खेडा हल्का मे ब्लाक और तहसील मे तीस बतीस बडे गांव है। यहां पर कालेज न होने से यहां के बच्चो को बहुत दिक्कत होती है। हमारे यहां कालेज की मांग काफी समय से है। मुख्यमंत्री जी जब विपक्ष मे थे तो उस समय हमने बवानी खेडा मे रैली भी की थी और उस रैली मे भी लोगो ने कालेज की मांग की थी। हुडा जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी हमने इनके सामने कालेज की माग रखी थी कि हमने हल्क बवानी खेडा मे कालेज खुलना चाहिए जिसके लिए 15 एकड, 20 एकड या 30 एकड जमीन हमारी नगरपालिका दे देगी। इसलिए मै चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी हां कर दे और उस कालेज की मांग को मजूर किया जाये क्योंकि हमारे यहां के बच्चो को पढने के लिए दूर दूर जाना पडता है।

श्री फूल चन्द मुलाना: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन ने ठीक कहा है कि सरकार का शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान है और यही कारण है कि मौजूदा सरकार ने चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुडा के नेतृत्व में शिक्षा को प्राथमिकता के आधार पर लिया है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि बवानी खेडा भिवानी जिले में है और भिवानी जिले में पहले से ही 14 कालेज है। बवानी खेडा भिवानी और हांसी इन दोनों भाहरों से 20 किलोमीटर की दूरी पड़ता है और आज के दिन यातायात के साधन भी उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से 15 मिनट में बवानी खेडा से इन भाहरों तक पहुंचा जा सकता है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावना को कद्र करता हूँ लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं बवानी खेडा में कालेज बनाने का वायदा करके आया था, इस बारे में मैं मेरे साथी को बताना चाहूंगा कि मैं बाल्मीकि जयंती पर वहां गया जरूरत था लेकिन इस तरह का कोई वायदा नहीं करके आया था।

श्री राम किशन फौजी: अध्यक्ष महोदय, वहां के लोगो ने वहां कालेज बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी से मांग रखी थी।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, Questions Hour is over.

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तरांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Sale of Tehsil Land, Karnal

347. Sh. Tejendra Pal Singh Mann: Will the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) whether the State Government has instituted any enquiry in regard to the sale of Tehsil (old) land in Karnal Town during the regime of the previous Government; and

(b) if so, whether some officers have been questioned in this regard?

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव):

(क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) प्र । नहीं नहीं उठता।

Providing of Compensation

405. Shri Somvir Singh: Will the Minister for Irrigation be pleased to state-

(a) whether it is a fact that more than 25 years have passed for the construction of Madhogarh Branch and the minors emanating therefrom on the Mahenderagarh Canal System in Lohary constituency but the compensation of the land acquired for the purpose has not been given so far, if so, the names of the canals and minors in respect of which compensation has not been given so far together with the time limit by which the compensation will be given, and

(b) whether the compensation of the land will be given at present prevailing rate?

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव):

(क) हां, श्रीमान जी सरकार के समक्ष यह तथ्य आया कि सुरेहटी माइनर की भूमि का मुआवजा अभी तक भूमि मालिकों को प्रदान नहीं किया गया है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी है और 6 माह के अन्दर मुआवजा दिए जाने की सम्भावना है।

(ख) भूमि का मुआवजा भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा तय की गई दर के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

Construction of a Bus Stand

448. Sh. Mahender Partab Singh: Will the Minister for Transport be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Bus Stand in sector-12, Faridabad, if so, upto what time the said proposed Bus Stand is likely to be constructed?

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): नहीं, श्रीमान जी।

Development of Sector in Karnal

442. Sh. Jai Singh Rana: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) whether any land was acquired by the Government for developing of Sector 32 and 33 by Haryana Urban Development Authority in Karnal during last five years; if so, the progress so far made in this regard; and

(b) whether any coloniser has been granted licence for the development of the land referred to in part (a) above, if so, the details thereof?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा):

(क) जी हां, श्रीमान। करनाल में रिहायशी सैक्टर 32 तथा 33 विकसित करने के लिए हुडा द्वारा लगभग 669 एकड़ भूमि 21.12.2004 को अधिगृहित की गई।

(ख) नहीं, श्रीमान।

Construction of Roads

457. Shri Bachan Singh Arya: Will the Minister for Agriculture be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration for the Government to construct the following roads of the Safidon Constituency-

(i) Bhuslana to Goli (It has been sanctioned by the Marketing Board, Haryana)

(ii) Nirmabad to Malikpur;

(iii) Rodh to Muwana;

(iv) Khera Khemawati to Rampura;

(v) Rajana Khurd to Kalwa;

(vi) Milkpur Village to Dera Wadhawa Singh;

(vii) Aftabgarh to Rodh;

(viii) Aftabgarh to Pajukalan; and

(ix) Todi Kheri to Sahanpur road; and

(b) if so, up to what time these roads are likely to be constructed?

कृषि मंत्री (सरदार एच०एस० चट्ठा):

(क) श्रीमान जी। भुसलाना से गोली तक सम्पर्क सडक पहले ही मण्डी बोर्ड द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। भोश आठ सडको बारे मे विचार किया जा रहा है।

(ख) सम्पर्क सडक भुसलाना से गोली का निर्माण वितीय वर्ष 2006-07 तक पूरा होने की सम्भावना है। यधपि भोश सडको के निर्माण बारे मे कोई समय अवधि नही बताई जा सकती।

Number of Culprites Killed in Police Encounter

413. Prof. Chattar Pal Singh: Will the Minister for Agriculture be pleased to state the number of culprites killed in police encounter in the State after the formation fo present Government togetherwith the details of criminal records thereof?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा): सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

क्रमांक	नम व पता दोशियान जो पुलिस मुठभेड मे मारे गए	मरने वाले दोशी का आपराधिक रिकार्ड
1.	युद्धबीर पुत्र ई वर सिंह वासी फरमान, जिला रोहतक जो दिनांक 12.5.2005 को पुलिस मुठभेड मे मारो गया	1. मु0न0 532 दिनांक 12.9.96 धारा 307 भा0द0स0 थाना भाहर सोनीपत ।
		2. मु0न0 131 दिनांक 24.3.96 धारा 307 भा0द0स0 थाना भाहर सोनीपत ।
		3. मु0न0 393 दिनांक 24.3.2000 धारा 379 / 406 भा0द0स0 थाना भाहर सोनीपत ।
		4. मु0न0 49 दिनांक 24.3.2000 धारा भास्त्र अधिनियम थाना भाहर सोनीपत ।

		5. मु0न0 491 दिनांक 13.11.2000 धारा 307 / 452 / 506 / 34 भा0द0स0 एवम भास्त्र थाना भाहर सोनीपत ।
		6. मु0न0 262 दिनांक 14.9.2001 धारा 323 / 506 भा0द0स0 थाना भाहर सोनीपत ।
		7. मु0न0 311 दिनांक 18.10.2001 धारा 307 / 506 भा0द0स0 एवम भास्त्र अधिनियम थाना भाहर सोनीपत ।
		8. मु0न0 29 दिनांक 21.2.2001 धारा 302 / 34 भा0द0स0 थाना सिवील लाईन सोनीपत ।
		9. मु0न0 520 दिनांक 12.8.2001 धारा 506 / 507 / 385 भा0द0स0 थाना भाहर रोहतक ।
		10. मु0न0 206 दिनांक 19.4. 2001 धारा 302 / 307 / 320 बी0 / 109 / 34 भा0द0स0 थाना भाहर रोहतक ।

		11. मु0न0 280 दिनांक 31.5.2001 धारा 506 भा0द0स0 थाना सिविल लाईन रोहतक ।
		12. मु0न0 610 दिनांक 9.11.2001 धारा 25 / 54 / 59 भास्त्र अधिनियम थाना नजफगढ दिल्ली ।
		13. मु0न0 155 दिनांक 6.6.2002 धारा 307 / 120बी0 / 34 / भा0द0स0 भास्त्र अधिनियम थाना भाहर सोनीपत
		14. मु0न0 159 दिनांक 6.6.2002 धारा 307 / 120बी0 / 34 / भा0द0स0 थाना भाहर सोनीपत
		15. मु0न0 321 दिनांक 31.12.2003 धारा 323 / 506 / 120बी / 34 भा0द0स0 थाना भाहर सोनीपत ।
		16. मु0न0 70 दिनांक 15.5.2004 धारा 8 / 9 जेल अधिनियम भा0द0स0 थाना खरखौदा, सोनीपत

		17. मु0न0 84 दिनांक 1.4.2001 धारा 387 भा0द0स0 थाना भाहर सोनीपत ।
		18. मु0न0 208 दिनांक 4.9.2004 धारा 384 / 387 / 307 भा0द0स0 एवम भास्त्र अधिनियम थाना सदर भाहर बहादुरगढ झज्जर ।
		19. मु0न0 83 / 2005 धारा 392 भा0द0स0 थाना सदर भाहर बहादुरगढ झज्जर ।
		20. मु0न0 138 दिनांक 12.5.2005 धारा 186 / 332 / 353 / 307 भा0द0स0 एवम भास्त्र अधिनियम थाना सदर भाहर बहादुरगढ झज्जर ।
		21. मु0न0 383 दिनांक 19.6.2001 धारा 302 / 307 / 34 भा0द0स0 एवम भास्त्र अधिनियम थाना भाहर रोहतक ।
		22. मु0न0 177 दिनांक 19.7.2001

		धारा 302 / 307 / 34 भा0द0स0 एवम भास्त्र अधिनियम सापंला रोहतक ।
		23. मु0न0 206 दिनांक 19.4.2001 धारा 302 / 307 / 449 / 34 भा0द0स0 एवम भास्त्र अधिनियम थाना सिविल लाईन रोहतक ।
2.	अ गोक मलिक पुत्र धर्मपाल वासी नरेला, दिल्ली जो दिनांक 26.5.2005 को जिला रोहतक मे पुलिस मुठभेडम मे मारा गया ।	1. मु0न0 153 दिनांक 12.9.2003 धारा 392 भा0द0स0 थाना सिविल लाईन रोहतक ।
		2. मु0न0 56 दिनांक 20.3.2005 धारा 302 / 34 भा0द0स0 थाना राई सोनीपत ।
		3. मु0न0 47 दिनांक 4.4.2005 धारा 392 / 397 / 342 भा0द0स0 एवम भास्त्र अधिनियम थाना कुण्डली

		सोनीपत
		4. मु०न० 56 दिनांक 2002 धारा 365 भा०द०स० थाना अलीपुर दिल्ली ।
		5. मु०न० 475 दिनांक 2002 धारा 302 भा०द०स० थाना सब्जी मण्डी, दिल्ली ।
		6. मु०न० 200 दिनांक 2004 धारा 223 / 224 भा०द०स० थाना सब्जी मण्डी, दिल्ली ।
		7. मु०न० 212 दिनांक 2004 धारा 387 / 506 भा०द०स० थाना रूपनगर दिल्ली ।
		8. मु०न० 228 दिनांक 19.6.2002 धारा 302 / 402 भा०द०स० थाना असंध पानीपत ।
		9. मु०न० 44 / 2004 धारा 399 / 402 भा०द०स० थाना इंसराना पानीपत ।

		10. मु0न0 222 दिनांक 27.8.2004 धारा 392 / 394 भा0द0स0 एवम थाना भास्त्र अधिनियम थाना समालखा पानीपत ।
		11. मु0न0 89 दिनांक 11.8.2004 धारा 395 / 397 भा0द0स0 थाना इंसराना पानीपत ।
		12. मु0न0 114 दिनांक 21.9.2004 धारा 399 / 402 भा0द0स0 थाना इंसराना पानीपत ।
		13. मु0न0 324 / 2005 धारा 392 / 34 भा0द0स0 थाना सदर बहादुरगढ, झज्जर ।
		14. मु0न0 55 / 2005 धारा 392 / 34 भा0द0स0 एवम भास्त्र अधिनियम थाना एन0आई0टी0 फतेहबाद ।
		15. मु0न0 211 / 1999 धारा 308 / 506 / 365 / 34 भा0द0स0 थाना अलीपूर, दिल्ली ।

		16. मु0न0 472 / 2002 धारा 302 भा0द0स0 थाना अलीपूर, दिल्ली।
		17. मु0न0 103 धारा 302 भा0द0स0 थाना अलीपूर, दिल्ली।
		18. मु0न0 111 दिनांक 26.5.2005 धारा307 / 353 / 106 / 427 / 379 / 34 भा0द0स0 एवम भास्त्र अधिनियम थाना महम, रोहतक।
3.	अनूप पुत्र जय भगवान राजपूरा कलां नई दिल्ली दिनांक 26.5. 2005 को पुलिस मुठभेड मारा गया।	1. मु0न0 111 दिनांक 26.5.2005 धारा 307 / 353 / 186 / 427 / 379 / 34 भा0द0स0 एवम भास्त्र अधिनियम थाना महम, रोहतक।
		2. मु0न0 184 दिनांक 26.5.2005 धारा 323 / 341 / 34 भा0द0स0 थाना अलीपूर दिल्ली।
4.	सुनील पुत्र रामभज वासी खन्दराई, थाना गोहाना, जिला सोनीपत जो कि	1. मु0न0 399 / 1996 धारा 148 / 149 / 323 / 325 / 452 भा0द0स0 थाना गोहाना सोनीपत।

	दिनांक 7.6.2005 को पुलिस मुठभेड मे मारा गया ।	
		2. मु0न0 68 दिनांक 6.6.2000 धारा 148 / 149 / 302 भा0द0स0 थाना गोहाना जिला सोनीपत
		3. . मु0न0 62 दिनांक 7.6.2000 धारा 322 / 353 भा0द0स0 थाना गोहाना जिला सोनीपत
		4. . मु0न0 21 दिनांक 21.5.2001 धारा 392 / 120 बी0 भा0द0स0 एवम भास्त्र अधिनियम थाना महम, रोहतक
		5. . मु0न0 34 दिनांक 7.3.2001 धारा 395 / 397 भा0द0स0 थाना सिविल लाईन रोहतक ।
		6. मु0न0 26 दिनांक 13.2.2001 धारा 379 भा0द0स0 थाना गन्नौर, सोनीपत ।

		7. मु0न0 26 दिनांक 29.1.2001 धारा 392 / 397 भा0द0स0 थाना गन्नौर, सोनीपत ।
		8. मु0न0 49 दिनांक 11.4.2002 धारा 379 भा0द0स0 थाना खरखौदा, सोनीपत ।
		9. मु0न0 233 दिनांक 20.1.2002 धारा 307 / 120बी0 भा0द0स0 थाना खरखौदा, सोनीपत ।
		10. मु0न0 135 / 2002 धारा 303 / 34 भा0द0स0 एवम भास्त्र अधिनियम सदर जीन्द ।
		11. मु0न0 172 दिनांक 26.11.2002 धारा 223 / 120बी0 भा0द0स0 थाना गोहाना, सोनीपत
		12. मु0न0 142 दिनांक 18.12.2004 धारा 302 / 34 भा0द0स0 एवम भास्त्र अधिनियम थाना बरौदा, सोनीपत
		13. मु0न0 71 दिनांक 20.6.2004 धारा 307 / 120बी / 34 भा0द0स0

		एवम भास्त्र अधिनियम थाना गोहाना, जिला सोनीपत।
		14. मु0न0 104 दिनांक 7.6.2005 धारा 332 / 307 / 353 भा0द0स0 एवम भास्त्र अधिनियम थाना गोहाना, सोनीपत।
5.	जोगिद्र सिंह पुत्र रत्न सिंह वासी कलीरावन जिला सिरसा जो कि दिनांक 21.6.2005 को पुलिस मुठभेड मे जिला हिसार मे मारा गया।	1. मु0न0 47 दिनांक 23.2.2003 धारा 303 / 34 भा0द0स0 एवम भास्त्र अधिनियम थाना अग्रोहा, हिसार।
		2. मु0न0 146 / 2003 धारा 457 / 380 भा0द0स0 थाना अग्रोहा हिसार।
		3. मु0न0 147 / 2003 धारा 457 / 380 भा0द0स0 थाना अग्रोहा हिसार।
		4. मु0न0 110 / 2003 धारा

		392 / 394 भा0द0स0 थाना बरवाला हिसार।
		5. मु0न0 388 / 2003 धारा 379 भा0द0स0 थाना भाहर हिसार।
		6. मु0न0 72 / 05 धारा 307 / 452 / 379 / 34 भा0द0स0 थाना अग्रोहा, हिसार।
		7. मु0न0 76 / 04 धारा 307 / 352 / 34 भा0द0स0 थाना अग्रोहा, हिसार।
		8. मु0न0 316 / 05 धारा 304 / 394 / 307 / 120 बी0 भा0द0स0 थाना सिरसा।
		9. मु0न0 114 / 05 धारा 307 / 34 भा0द0स0 थाना अग्रोहा, हिसार।
6.	थ्वनोद उर्फ सोनू पुत्र राम कुमार वासी कलीरावना जिला सिरसा जो कि दिनांक 21.52005 को पुलिस	1. मु0न0 327 / 03 धारा 160 भा0द0स0 थाना हिसार।

	मुठभेड मारा गया।	
		2. मु0न0 146 / 03 धारा 457 / 380 भा0द0स0 थाना अग्रोहा, हिसार।
		3. मु0न0 110 / 03 धारा 392 / 394 भा0द0स0 एवम भास्त्र अधिनियम थाना बरवाला, हिसार।
		4. मु0न0 147 / 03 धारा 457 / 380 भा0द0स0 थाना अग्रोहा, हिसार।
		5. मु0न0 72 / 05 धारा 307 / 452 / 379 / 34 भा0द0स0 थाना अग्रोहा, हिसार।
		6. मु0न0 76 / 04 धारा 307 / 352 / 34 भा0द0स0 थाना अग्रोहा, हिसार।
		7. मु0न0 316 / 05 धारा 304 / 394 / 307 / 120बी0 भा0द0स0 थाना सिरसा।
		8. मु0न0 114 / 05 धारा 307 / 34 भा0द0स0 थाना अग्रोहा, हिसार।

7.	<p>रोहता ा पुत्र लाल चन्द वासी थैड मोहल्ला सिरसा जो कि दिनांक 21.6.2005 को पुलिस मुठभेड मे मारा गया।</p>	<p>1. मु0न0 72 / 05 धारा 307 / 452 / 379 / 34 भा0द0स0 थाना अग्रोहा, हिसार।</p>
		<p>2. मु0न0 76 / 04 धारा 307 / 352 / 34 भा0द0स0 थाना अग्रोहा, हिसार।</p>
		<p>3. मु0न0 316 / 05 धारा 304 / 394 / 307 / 120 बी0 भा0द0स0 थाना सिरसा।</p>
		<p>4. मु0न0 114 / 05 धारा 307 / 34 भा0द0स0 थाना अग्रोहा, हिसार।</p>
8.	<p>जगबीर उर्फ कुन्ती पुत्र प्रतापसिंहवासी दनौदाकंला, जीन्द जो कि दिनांक 24.6.2005 पुलिस मुठभेड मे मारा गया।</p>	<p>1. मु0न0 28 / 05 धारा 392 भा0द0स0 थाना बरवाला, हिसार।</p>

		2. मु0न0 32 / 02 धारा 302 / 34 भा0द0स0 थाना सदर नरवाना, जीन्द ।
		3. मु0न0 92 / 03 धारा 392 भा0द0स0 थाना बरवाला, हिसार ।
		4. मु0न0 67 / 03 धारा 399 / 402 भा0द0स0 थाना नरवाना जीन्द ।
		5. मु0न0 109 / 03 धारा 302 भा0द0स0 थाना बरवाला, हिसार ।
		6. मु0न0 96 / 03 धारा 398 / 401 भा0द0स0 थाना उचाना, जीन्द ।
		7. मु0न0 74 / 04 धारा 15 / 61 / 85 भा0द0स0 द्रव्य अधिनियम थाना नरवाना जीन्द ।
		8. मु0न0 8 / 05 धारा 302 / 307 / 148 / 149 / 34 भा0द0स0 थाना भाहर नरवाना जीन्द ।
		9. मु0न0 129 / 05 धारा

		307 / 353 / 332 भा0द0स0 थाना उकलाना जीन्द ।
		10. मु0न0 109 / 03 धारा 302 भा0द0स0 थाना बरवाला, हिसार ।
9.	रविन्द्र पुत्र रमे । वासी नेहरा थाना कुण्डली, सोनीपत जो कि पुलिस मुठभेड मे दिनांक 4.7.2006 को मारा गया ।	1. मु0न0 378 / 05 भा0द0स0 थाना मंगोलपुरी दिल्ली ।
		2. मु0न0 659 / 05 धारा 379 भा0द0स0 थाना रोहनी, दिल्ली ।
		3. मु0न0 181 / 05 धारा 392 / 397 भा0द0स0 थाना सोनीपत ।
		4. मु0न0 293 / 5 धारा 392 / 397 भा0द0स0 थाना नरेला, दिल्ली ।
		5. मु0न0 115 / 05 धारा 394 / 397 भा0द0स0 थाना नरेला, दिल्ली ।
		6. मु0न0 119 / 05 धारा

		307 / 186 / 353 / 34 भा0द0स0 थाना गन्नौर, सोनीपत ।
10.	डमे ा पुत्र होि ायार सिंह वासी जाहिदपुर थाना केसली, रिवाडी जो कि दिनांक 14.7. 2005 को पुलिस मुठभेड मे मारा गया ।	1. मु0न0 534 / 5 धारा 148 / 149 / 307 / 323 / 506 भा0द0स0 थाना कोसली, रिवाडी ।
		2. मु0न0 48 / 05 धारा 332 / 353 / 333 / 186 / 307 / 34 भा0द0स0 थाना जाटूसाना, रिवाडी ।
11.	भादर कुमार पुत्र ओमप्रका ा वासी देव स्तान मोहल्ला नारनौल जो कि दिनांक 5.8.2005 को पुलिस मुठभेड मे मारा गया ।	1. मु0न0 389 / 053 धारा 363 / 364 भा0द0स0 थाना सदर, गुडगांव ।
		2. मु0न0 519 / 05 धारा 307 / 353 / 34 भा0द0स0 थाना

		डी0ए0एफ0 गुडगांव ।
12.	कृष्ण पुत्र ओमप्रकाश वासी देव स्तान मोहल्ला, नाननौल जो कि दिनांक 5.8.2005 को पुलिस मुठभेड मे मारा गया ।	1. मु0न0 389 / 05 भा0द0स0 थाना सदर, गुडगांव ।
		2. मु0न0 519 / 05 धारा 307 / 353 / 34 भा0द0स0 थाना डी0ए0एफ0 गुडगांव ।
13.	लीला उर्फ सुरेन्द्र पुत्र धर्मपाल वासी सिसाय, हिसार जो कि दिनांक 10.6.2005 को जिला भिवानी मे मारा गया ।	1. मु0न0 109 / 97 धारा अ0 अधिनियम थाना भाहर हांसी, हिसार ।
		2. मु0न0 591 / 97 धारा धारा अ0 अधिनियम थाना भाहर हांसी, हिसार ।
		3. मु0न0 50 / 98 धारा 354 भा0द0स0 थाना भाहर हांसी, हिसार ।

		4. 241 / 44.मु0न0 241 / 93 धारा 148 / 149 / 307 / 302 / भा0द0स0 थाना भाहर हांसी, हिसार ।
		5. मु0न0 281 / 98 धारा 324 भा0द0स0 थाना भाहर हांसी, हिसार ।
		6. मु0न0 236 / 99 धारा 454 / 506 भा0द0स0 थाना भाहर हांसी, हिसार ।
		7.मु0न0 84 / 2000 धारा 386 / 506 / 34 भा0द0स0 थाना भाहर हांसी, हिसार ।
		8.मु0न0 462 / 98 धारा 324 / 323 / 506 / 34 भा0द0स0 थाना भाहर हांसी, हिसार ।
		9. मु0न0 67 / 98 धारा 392 / 411 भा0द0स0 थाना अलेवा, हिसार ।
		10. मु0न0 171 / 01 धारा 386 भा0द0स0 थाना भाहर हांसी, हिसार ।
		11. मु0न0 131 / 99 धारा 392 / 398 भा0द0स0 थाना बवानी खेडा, हिसार ।

		12. मु०न० 235 / 99 धारा 395 भा०द०स० थाना बरवाला, हिसार ।
		13. मु०न० 516 / 01 धारा 332 / 353 / 307 / 34 भा०द०स० थाना भाहर हांसी, हिसार ।
		14. मु०न० 517 / 01 धारा 332 / 353 / 307 / 34 भा०द०स० थाना भाहर हांसी, हिसार ।
		15 मु०न० 658 / 01 धारा 353 / 186 / भा०द०स० थाना सि०ल०, हिसार ।
		16. मु०न० 151 / 02 धारा 302 / 120 बी० भा०द०स० थाना भाहर हांसी, हिसार ।
		17. मु०न० 215 / 03 धारा 323 / 353 भा०द०स० थाना भाहर हांसी, हिसार ।
		18. मु०न० 120 / 98 धारा 452 / 323 / 506 / 34 भा०द०स० थाना भाहर हांसी, हिसार ।

		19. मु0न0 474 / 04 धारा 302 भा0द0स0 थाना भाहर हांसी, हिसार।
		20. मु0न0 48 / 05 धारा 302 / 120 बी0 भा0द0स0 थाना भाहर हांसी, हिसार।
		21. मु0न0 11 / 05 धारा 302 / 120 बी0 भा0द0स0 थाना भाहर हांसी, हिसार।
		22. मु0न0 384 / 04 धारा 384 / 511 भा0द0स0 थाना भाहर हांसी, हिसार।
		23. मु0न0 419 / 04 धारा 302 / 201 / 34 / 379 भा0द0स0 थाना भाहर फतेहबाद।
		24. मु0न0 193 / 04 धारा 307 / 34 भा0द0स0 थाना सि0ला0, हिसार।
		25. मु0न0 136 / 05 धारा 307 / 120 बी0 भा0द0स0 थाना सि0ला0 भिवानी।
14.	पुनीत वासी डीसी	1. मु0न0 136 / 05 धारा 307 / 120

	कालोनी भिवानी जो कि दिनांक 10.8.2005 को पुलिस मुठभेड मे संख्या 13 पर अकित दोशी के साथ मारा गया।	बी0 भा0द0स0 थाना सि0ला0 भिवानी।
15.	संदीप पुत्र महेन्द्र सिंह वासी कामी जो कि दिनांक 18.11.2005 को पुलिस मुठभेड मे मारा गया।	1. मु0न0 323 / 05 धारा 307 / 120 बी0 भा0द0स0 थाना सि0ला0 भिवानी।
		2. मु0न0 357 / 05 धारा 395 / 397 भा0द0स0 थाना समालखा, पानीपत।
		3. मु0न0 258 / 05 धारा 307 / 353 भा0द0स0 थाना समालखा, पानीपत।
		4. मु0न0 195 / 05 धारा 302 / 34 भा0द0स0 थाना सदर, पानीपत।
		5. मु0न0 160 / 05 धारा 379 भा0द0स0 थाना मुरथल, सोनीपत।

		6. मु0न0 218 / 05 धारा 392 भा0द0स0 थाना गन्नौर, सोनीपत ।
		7. मु0न0 344 / 05 धारा 397 भा0द0स0 थाना भाहबाद, कुरुक्षेत्र ।
		8.
		8. मु0न0 252 / 05 धारा 392 / 3497 भा0द0स0 थाना अ गोक विहार, दिल्ली ।
16.	हेमन्त पुत्र रामनारयण वासी नजफगढ दिल्ली जो कि दिनांक 7.3. 2005 को पुलिस मुठभेड मे मारा गया ।	1. मु0न0 186 / 98 धारा 302 / 307 / 34 भा0द0स0 थाना नजफगढ, दिल्ली ।
		2. मु0न0 16 / 99 धारा 392 / 34 भा0द0स0 थाना भाहर, गुडगांव ।
		3. मु0न0 5 / 2000 धारा 452 / 307 / 394 / 397 / 34 भा0द0स0 थाना करौल बाग, दिल्ली ।
		4. मु0न0 18 / 2000 धारा 379 / 411

		भा0द0स0 थाना सि0ला0, रोहतक
		5. मु0न0 197 / 2000 धारा 392 / 34 भा0द0स0 थाना, यमुनानगर ।
		6. मु0न0 240 / 2000 धारा 394 भा0द0स0 थाना डिफैंस कालोनी, दिल्ली ।
		7. मु0न0 179 / 01 धारा 397 / 34 भा0द0स0 थाना हांसखास, दिल्ली ।
		8. मु0न0 191 / 01 धारा 392 / 397 भा0द0स0 थाना भालीमार बाग, दिल्ली ।
		9. मु0न0 29 / 02 धारा 392 / 34 भा0द0स0 थाना भामली यू0पी0 ।
		10. मु0न0 72 / 02 धारा 392 / 397 / 342 / 506 भा0द0स0 थाना, सुलान्तपूरी, दिल्ली ।
		11. मु0न0 653 / 01 धारा 402 भा0द0स0 थाना मालवीय नगर, दिल्ली ।

		12. मु0न0 60 / 02 धारा 379 भा0द0स0 थाना माधुरी, दिल्ली।
		13. मु0न0 173 / 02 धारा 392 भा0द0स0 थाना डी0एल0एफ0 गुडंगव।
		14. मु0न0 193 / 02 धारा 392 भा0द0स0 थाना डी0एल0एफ0 गुडंगव।
		15. मु0न0 150 / 02 धारा 379 भा0द0स0 थाना बंसत बिहार दिल्ली।
		16.. मु0न0 220 / 02 धारा 397 / 397 / 34 भा0द0स0 थाना हिमारपूरी दिल्ली।
		17. मु0न0 262 / 02 धारा 397 / 392 भा0द0स0 थाना सदर, पलवल फरीदाबाद।
		18. मु0न0 476 / 02 धारा 394 / 397 भा0द0स0 थाना मालवीय नगर, दिल्ली।

		19. मु०न० 250 / 04 धारा 307 / 37 भा०द०स० थाना महरौली, दिल्ली।
		20. मु०न० 6 / 05 धारा 392 भा०द०स० थाना भामली यू०पी०
		21. मु०न० 20 / 05 धारा 307 / 34 भा०द०स० थाना महरौली, दिल्ली।
		22. मु०न० 242 / 05 धारा 302 / 120बी० / 34 भा०द०स० थाना भाहर बहादुरगढ, झज्जर।
		23. मु०न० 652 / 05 धारा 302 / 34 भा०द०स० थाना नजफगढ, दिल्ली।
		24. मु०न० 441 / 05 धारा 302 / 34 भा०द०स० थाना भाहर गुडगांव।
		25. मु०न० 52 / 06 धारा 302 / 34 भा०द०स० थाना भाहर गुडगांव।
		26 मु०न० 129 / 06 धारा 302 / 34 भा०द०स० थाना भाहर गुडगांव।
17.	जसवन्त पुत्र जगदी ा वासी	1. मु०न० 237 / 2000 धारा 341 / 323 / 34 भा०द०स० थाना

	<p>नजफगढ, दिल्ली जो कि दिनांक 7.3.2006 को पुलिस मुठभेड मे मारा गया।</p>	<p>नफजगढ, दिल्ली।</p>
		<p>2. मु0न0 497 / 01 धारा 341 / 323 / 379 / 34 भा0द0स0 थाना नफजगढ, दिल्ली।</p>
		<p>3. मु0न0 650 / 01 धारा 394 / 379 भा0द0स0 थाना नफजगढ, दिल्ली।</p>
		<p>4. मु0न0 291 / 01 धारा 392 / 397 / 365 / 34 भा0द0स0 थाना द्वारिकापुरी, दिल्ली।</p>
		<p>5. मु0न0 593 / 01 धारा 392 / 342 भा0द0स0 थाना सदर गुडगांव।</p>
		<p>6. मु0न0 338 / 01 धारा 392 / 34 भा0द0स0 थाना सदर बहादुरगढ, झज्जर।</p>
		<p>6. मु0न0 650 / 01 धारा 394 / 379 भा0द0स0 थाना नफजगढ, दिल्ली।</p>

		7. मु0न0 392 / 03 धारा 392 / 34 भा0द0स0 थाना उत्तम नगर , दिल्ली ।
		8. मु0न0 661 / 03 धारा 399 / 402 / 411 / 473 / 34 भा0द0स0 थाना उत्तम नगर दिल्ली ।
		9. मु0न0 227 / 05 धारा 406 / 506 भा0द0स0 थाना नफजगढ, दिल्ली ।
		10. मु0न0 123 / 06 धारा 307 / 387 / 34 भा0द0स0 थाना नफजगढ, दिल्ली ।
		11. मु0न0 441 / 06 धारा 341 / 323 / 379 / 34 भा0द0स0 थाना नफजगढ, दिल्ली ।
		12. मु0न0 52 / 06 धारा 302 / 34 भा0द0स0 थाना भाहर गुडगांव ।
		13. मु0न0 129 / 06 धारा 302 / 34 भा0द0स0 थाना भाहर गुडगांव ।
18.	जय प्रका I पुत्र भूप सिंह वासी नजफगढ,	1. मु0न0 441 / 05 धारा 302 / 34 भा0द0स0 थाना भाहर गुडगांव ।

	<p>जो कि दिनांक 7.3.2006 को पुलिस मुठभेड मे मारा गया।</p>	
		<p>2. मु0न0 52 / 06 धारा 302 / 34 भा0द0स0 थाना भाहर गुडगांव।</p>
		<p>3. मु0न0 129 / 06 धारा 302 / 34 भा0द0स0 थाना भाहर गुडगांव।</p>
		<p>4. मु0न0 650 / 015 धारा 394 / 397 भा0द0स0 थाना नजफगढ, दिल्ली।</p>
		<p>5. मु0न0 1065 / 99 धारा 379 भा0द0स0 थाना नजफगढ, दिल्ली।</p>
		<p>6. मु0न0 766 / 99 धारा 379 / 397 / 411 भा0द0स0 थाना रोहनी, दिल्ली।</p>
		<p>7. मु0न0 12 / 03 धारा 452 / 394 / 397 भा0द0स0 थाना नजफगढ, दिल्ली।</p>
		<p>8. मु0न0 558 / 98 धारा 376 / 452 / 341 भा0द0स0 थाना</p>

		नजफगढ, दिल्ली।
		9. मु0न0 123/06 धारा 307,387 भा0द0स0 थाना नजफगढ, दिल्ली।

PERONS LIVING BELOW POVERTY

422. Sh. Rakesh Kamboj: Will the Chief Minister be pleased to state

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to conduct a fresh survey in the State to identify the people living below poverty line; and

(b) if so, up to what time the survey is to be conducted?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा):

(क) और (ख) ग्रामीण तथा भाहरी क्षेत्रो मे नया सर्वेक्षण पहले ही करवाया जा चुका है।

Removing of Encroachments

418. Sh. Ram Kumar Gautam: Will the Minister for Urban Development be pleased to state-

(a) whether Government is aware of the fact that there are large scale encroachmentns on the Municipal Land of Narnaud City; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to remove the encroachment

at least form the cremation ground and the passage leading to BUDHI MATA Shrine of the aforesaid City?

भाहरी विकास राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री जिंदल):

(क) जी हां, नगरपालिका नारनोंद से सूचित किया है कि पालिका भूमि पर लगभग 500 मकानों का निर्माण किया हुआ है।

(ख) जी हां, उपायुक्त हिसार ने सूचित किया है कि बुढी माता स्थल को जाने वाले रास्ते पर किये गये अस्थाई कब्जों को हटा दिया गया है भाम गान घाट पर हुए नाजायज कब्जों को हटाने के लिए कार्रवाई भुरू की जा रही है।

Trees planted on Bayal Panchayat Land

390. Shri Radhye Shyam Sharma: Will the Minister for Forest be pleased to state-

(a) whether it is fact that all the trees of Forest Department planted on the Bayal Panchayat Land in Narnaud Constituency have been sold by an officer during the last six years after cutting them, if so the name of the said officers alongwith action taken or to be taken against him.

(b) whether any enquiry was got conducted in the said matter;

(c) if so, whether the enquiry was found satisfactory;

has been taken or proposed to be taken against the enquiry officer who has given the wrong report; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to conduct a fresh enquiry in the matter referred to in part (a) above?

वन राज्य मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी): इस सम्बन्ध में वाछिंत सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

(अ) नहीं, श्रीमान जी। बायल पंचायत भूमि पर वृक्षों की नाजायज कटाई की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। वन विभाग का कोई भी कर्मचारी नाजायज कटाई में संलिप्त नहीं था।

(ब) हां, श्रीमान जी। बायल ग्रामवासियों ढाणी रावता द्वारा 30.7.2004 को वन मण्डल अधिकारी, महेन्द्रगढ़ को रिपोर्ट की गई जिसमें यह आरोप लगाया गया कि बायल पंचायत भूमि से वृक्षों की अवैध कटान करके बेचे गये। वन मण्डल अधिकारी महेन्द्रगढ़ द्वारा इसकी जांच करवाई गई। श्रीमान राज, वन खण्ड अधिकारी, जांच अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट वन राजिक अधिकारी, नारनौल के माध्यम से 04.09.2004 महेन्द्रगढ़ को पत्र क्रमांक दिनांक 17.9.2004 द्वारा भेजी गई। जांचकर्ता ने यह पाया कि पेड़ काटे गए थे। वन विभाग के कर्मचारियों ने दोशियों को पकड़ा तथा उन पर 2300 रु० जुर्माना लगाया। 60 क्विंटल लकड़ी

जुर्मकर्ताओ से बरामद की गई। इस अवैध कटाई व बिकरी मे वन विभाग के किसी कर्मचारी का संलिप्त होना नही पाया गया था।

(स) जांच रिपोर्ट संतोशजनक पाई गई।

(द) चूंकि जांच रिपोर्ट संतोशजनक पाई गई है अतः जांच अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित नही है।

(ई) श्री लाल सिंह, भूतपूर्व सरपंच, बायल ग्राम, द्वारा पुनः दूसरी रिाकायत दर्ज कराई गई, जिसकी जाच वन मण्डल अधिकारी, महेन्द्रगढ द्वारा की गई। जांच मे किसी अधिकारी को दोशी नही पाया गया।

Compensation Provided to Farmers

394. Dr. Sita Ram: Will the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) whether it is fact that the loss of life, property, crops and live stock was caused in the State due to storm on 9th June, 2005; if so, the kind of relief alongwith the total amount provided by the Government to the affected persons;

(b) whether is is also fact that the loss was caused to many Gauhalas of Sttae due to storm referred to in part (a) above.

(c) whether any kind of financial assistance hass been provided to the said Gauslalas; if so, the names of such Gaushalas alongwith amount provided to them; and

(d) if so, reply to part (c) above is in negative, whether there is any proposal under consideration of the Government to provide financial assistance to the said Gaushalas.?

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव):

(क) दिनांक 9.10.2005 की रात को आए तूफान के कारण राज्य में 25 व्यक्तियों व 97 पशुओं की मृत्यु हुई थी, 700 बिजली के खम्भे तथा 20 ट्रांसफार्मर एवम् 1110 वृक्षों के गिरने का नुकसान हुआ था। राज्य सरकार द्वारा प्रभावित परिवारों के लिये 38.64 लाख रुपये की राहत राशि स्वीकृत की गई थी।

(ख) जी हां। उपायुक्त, सिरसा ने सूचित किया है कि उनके जिले में तीन गौशालाओं को लगभग 746400 रु० की राशि का नुकसान हुआ था। यद्यपि दिनांक 9/10.6.2005 को आये तूफान के कारण इन गौशालाओं में किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

**Irregularities Committed in Selection/Recruitment in
Haryana Public Service Commission**

344. Sh. Karan Singh Dalal: Will the Chief Minister be pleased to state whether the State Government has received any complaint in regard to the irregularities committed in the

selection/recruitments made to the posts of different categories of various departments/boards and corporations of Haryana Government, on the recommendations of the Haryana Public Services Commission during the last six years (since 1999-2000 till date); if so, the details thereof togetherwith the action taken thereon?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा): सूची सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूची

हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों/बोर्डों तथा निगमों के विभिन्न पदों पर किये गये चयन/भर्ती सम्बन्धी अनियमितताओं के आरोपों बारे में जांच प्राप्त हुई है। इन जांचों के आधार पर हरियाणा सरकार द्वारा राज्य चौकसी ब्यूरो को यह निर्देश दिए गये कि वह मामले की छानबीन करे। तदनुसार राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा पांच जांचें भंग की हैं।

इन पांच जांचों की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है:—

1. जांच क्रमांक 3/2005, चण्डीगढ़ प्रथम अधिसूचना 20/2005 हिसार के विरुद्ध श्री के.सी. बांगड, भूतपूर्व अध्यक्ष, हरियाणा लोग सेवा और श्री ओम प्रकाश चौटाला, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा 1. हरियाणा सिविल सेवाएं (कार्यकारी भाखा) तथा अन्य सम्बन्धी सेवाएं वर्ष 2004 के चयन में अनियमितताएं। 2. वर्ष 2001 में विभिन्न विषयों के प्राध्यापक (महाविद्यालय वर्ग) के

चयन मे की गई अनियमितताए। 3. चौधरी `देवी लाल मैमोरियल कालेज आफ इजीनियरिंग, पानीवाला मोटा सिरसा मे वर्ष 2003 के प्राध्यापको के पदों पर चयन की गई अनियमितताए। 4. गुरु जम्बे वर वि वविधालय, हिसार के प्राध्यापको के पदों के चयन मे की गई अनियमितताए। 5. कृशि विभाग के श्रेणी 1 व 2 के पदों के चयन मे की गई अनियमितताए, जांच प्रगति पर है। हरियाणा लोग सेवा आयोग से रिकार्ड प्राप्त होने पर चौकसी विभाग द्वारा जांच पूर्ण कर ली जायेगी

2. जांच क्रमांक 5/2005, चण्डीगढ प्रथम अधिसूचना 15/2000, रोहतक के विरुद्ध श्री के0सी0 बांगड, भूतपूर्व अध्यक्ष, हरियाणा लोग सेवा वर्ष 2004 मे औशधी निरीक्षक के पद पर किये गये गलत चयन बारे। श्री के0सी0 बांगड, भूतपूर्व अध्यक्ष, हरियाणा को इस केस मे अभी तक गिरफतार नही किया गया है, क्योंकि उस द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय मे अग्रिम जमानत हेतु आपाराधिक एस0एल0पी0 दायर की गई है, इस केस मे अगली सुनवाई की तिथि 20.3.2005 निश्चित है उनकी गिरफतारी पर अग्रिम रोक प्रदान की गई है।

3. जांच क्रमांक 4/2005, चण्डीग, विरुद्ध हरियाणा लोक सेवा आयोग, प्रदुशण नियंत्रण बोर्ड मे वर्ष 2004 मे पर्यावरण इजीनियरों के चयन मे की गई अनियमितताए मामले मे जांच रिपोर्ट अभी अपेक्षित है।

4. जांच क्रमांक 4/2005, चण्डीग, विरुद्ध श्री हरदीप सिंह, एच0सी0एस0 भूतपूर्व सचिव, हरियाणा लोक सेवा आयोग, वर्ष 2003 में हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई परीक्षाओं में लाखों रुपये की रिक्त लेने बारे। जांच रिपोर्ट अभी अपेक्षित है।

5. जांच क्रमांक 1/2006, चण्डीग, वर्ष 2004 में तहसीलदार/आबकारी एमव कराधान अधिकारी उप अधीक्षक पुलिस के पदों पर किये गये चयन में अनियमितताएं। जांच रिपोर्ट अभी अपेक्षित है।

अतरांकित प्रश्न एवम उत्तर

26. Dr. Sushil Indora: Will the Minister for Welfare of Scheduled Castes & Back Ward Classes be pleased to state what steps were taken by the Government for the Social Justice and upliftment of the people belonging to downtrodden classes during the year 2004-2005.?

स्वास्थ्य मंत्री (बहन करतार देवी): श्री मान जी। दलित वर्गों के सामाजिक न्याय तथा उत्थान विभाग की चालू योजनाओं के अन्तर्गत 50.45 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई थी।

Development of Food Park

34. Dr. Sita Ram: Will the Minister for Industries be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Governement to development new food parks in the State during the financial year 2005-06; and

(b) whether the sanction has ben a accorded to develop the food park in Dabwali in district Sirsa; if so, the extent to which the work has been completed on the said project togetherwith the time by which it is likely to be completed?

उधोग मंत्री (श्री लक्षमन दास अरोडा):

(क) वितीय वर्ष 2005-06 के दौरान राज्य मे नए फूड पार्क विकसित करने का ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नही है।

(ख) नही, श्रीमान।

Upgradation of 132 KV Sub station, Kirmach

29. Shri Jai Singh Rana: Will the Minister for Industries be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Governement to upgrade 132 KV Sub station, Kirmach, district Kurukshetra; and

(b) if so, by what time if is likely to be upgraded?

बिजली मंत्री (श्री विनोद कुमार भार्मा):

(क) जिला कुरुक्षेत्र मे 33 के०वी० उपकेन्द्र किरमिच का दर्जा बढाकर 132 के०वी० करने के प्रस्ताव की तकनीकी औचित्यता की जांच की जा रही है।

(ख) 33 के०वी० उपकेन्द्र किरमिच का दर्जा बढाना, नीलोखेडी मे एक 220 के०वी० फीडिंग उपकेन्द्र स्थापित करने करने के साथ सम्बन्धित है, जिसका निर्माण वित्तीय वर्ष 2007-08 के अन्त तक किया जाना सम्भावित है।

Number of Senior Secondary Schools in the State

27. Shri Jai Karan Singh: Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) the district wise number of Senior Secondary Schools with faculty wise, in rural and urban separately in the State as on 31st December, 2005.

(b) the number of Senior Secondary Schools referred to in part (a) above where are regular Principal on the above Started dated; and

(c) the number of Senior Secondary Schools referred to in part (a) above in which Lecturers of all the subjects were imposition as on 31st December, 2005 ?

शिक्षा मंत्री (श्री फूलचन्द मुलाना):

(क) 31.12.2005 की स्थितिनुसार जिला वाईज/फैक्टरी वाईज, भाहरी व ग्रामीण वरिष्ठ माध्यमिक विधालयो की संख्या निम्न प्रकार से है:-

	कला		विज्ञान		कांमर्स	
अम्बाला		49		11		25
ग्रामीण	38		3		14	
भाहरी	11		8		11	
भिवानी		122		17		32
ग्रामीण	114		11		26	
भाहरी	8		6		6	
फरीदाबाद		67		32		43
ग्रामीण	53		19		30	
भाहरी	14		13		13	
फतेहबाद		36		4		8
ग्रामीण	30		4		5	
भाहरी	6				3	

गुडगांव		69		21		28
ग्रामीण	58		14		20	
भाहरी	11		8		8	
झज्जर		70		9		20
ग्रामीण	64		4		15	
भाहरी	6		5		5	
जींद		59		7		11
ग्रामीण	52		2		5	
भाहरी	7		5		6	
कैथल		51		3		8
ग्रामीण	45		1		3	
भाहरी	6		2		5	
करनाल		6		15		26
ग्रामीण	48		6		15	
भाहरी	12		9		11	

कुरुक्षेत्र		34		9		16
ग्रामीण	28		4		11	
भाहरी	6		5		5	
महेन्द्रगढ		60		12		28
ग्रामीण	56		9		24	
भाहरी	4		3		4	
पंचकूला		23		11		13
ग्रामीण	17		5		8	
भाहरी	6		6		5	
पानीपत		36		8		10
ग्रामीण	31		4		6	
भाहरी	5		4		4	
रेवाडी		48		15		27
ग्रामीण	44		12		23	
भाहरी	4		3		4	

रोहतक		52		10		20
ग्रामीण	43		4		13	
भाहरी	9		6		7	
सिरसा		51		7		11
ग्रामीण	41		1		4	
भाहरी	10		6		7	
सोनीपत	81	90		15		22
ग्रामीण	9		9		17	
भाहरी			6		5	
यमुनानगर		34		11		19
ग्रामीण	28		7		13	
भाहरी	6		4		8	
		1909		232		393

(ख) जिला वार वरिष्ठ माध्यमिक विधालयो की संख्या/सूचना जिनमे नियमित प्राचार्य कार्यरत है। (31.12.2005 की स्थिति अनुसार)

क्रमांक स०	जिले का नाम	कुल	ग्रामीण	भाहरी
1.	अम्बाला	22	14	08
2.	भिवानी	63	58	05
3.	फरीदाबाद	39	29	10
4.	फतेहबाद	22	20	02
5.	गुडगांव	33	30	03
6.	थहसार	67	60	07
7.	झज्जर	39	37	02
8.	जिंद	37	33	04
9.	कैथल	25	22	03
10.	करनाल	36	28	08
11.	कुरुक्षेत्र	21	16	05
12.	महेन्द्रगढ़	26	22	04
13.	पंचकूला	11	07	04
14.	पनीपत	07	04	03

15.	रेवाडी	25	24	01
16.	श्रोहतक	43	34	09
17.	थसरसा	34	30	04
18.	सेनीपत	24	21	03
19	यमुनानगर	12	11	01
	कुल योग	586	500	86
			पांच सौ	छयासी

(ग) जिला वार वरिष्ठ माध्यमिक विधालयो की संख्या/सूचना जिन मे सभी प्राध्यापक कार्यरत है। (31.12.1995 की स्थिति अनुसार)

राज्य मे वरिष्ठ विधालयो की संख्या

जिले का नाम		ग्रामीण	भाहरी
1		2	3
अम्बाला	क्ला	16	8
	कामर्स	9	7
	विज्ञान	2	7

	कुल	27	22
सेनीपत	कला	27	6
	कामर्स	12	5
	विज्ञान	6	6
	कुल	45	17
कैथल	कला	24	4
	कामर्स	3	3
	विज्ञान	..	2
	कुल	27	9
श्रोहतक	कला	27	7
	कामर्स	9	7
	विज्ञान	6	7
	कुल	42	20
श्रेवाडी	कला	23	3
	कामर्स	13	3

	विज्ञान	11	3
	कुल	47	9
यमुनानगर	कला	10	6
	कामर्स	7	6
	विज्ञान	5	3
	कुल	22	15
भिवानी	कला	27	6
	कामर्स	10	5
	विज्ञान	3	6
	कुल	40	17
करनाल	कला	12	11
	कामर्स	4	9
	विज्ञान	2	7
	कुल	18	27
झज्जर	कला	17	4

	कामर्स	7	4
	विज्ञान	3	4
	कुल	27	12
थसरसा	कला	10	3
	कामर्स	2	3
	विज्ञान	3	3
	कुल	13	9
जींद	कला	17	7
	कामर्स	1	4
	विज्ञान	1	5
	कुल	19	16
पनीपत	कला	5	3
	कामर्स	3	3
	विज्ञान	1	3
	कुल	11	9

फरीदाबाद	कला	15	15
	कामर्स	11	13
	विज्ञान	5	12
	कुल	31	40
फतेहाबाद	कला	4	5
	कामर्स	..	4
	विज्ञान	..	4
	कुल	4	13
हिसार	कला	29	8
	कामर्स	7	8
	विज्ञान	4	7
	कुल	40	23
गुडगांव	कला	18	3
	कामर्स	9	2
	विज्ञान	7	2

	कुल	34	7
नरनौल	कला	27	4
	कामर्स	14	4
	विज्ञान	3	3
	कुल	44	11
कुरुक्षेत्र	कला	17	3
	कामर्स	6	3
	विज्ञान	6	3
	कुल	29	9
पंचकूला	कला	6	6
	कामर्स	4	6
	विज्ञान	1	6
	कुल	11	18

Providing of Incentives

30. Sh. Dharampal Singh Malik: Will the Minister for Finance be pleased to state whether there is any proposal under consideration of State Government to give some

incentives to the Government employees to be posted in rural areas in the State?

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह): जी नहीं।

Kundli Manesar Palwal Express Highway

39. Dr. Sushil Indora: Will the Minister for PWD (B&R) be pleased to state whether there is any proposal under consideration of State Government to construct Kundli Manesar Palwal Express Highway; if so, the detail thereof?

उद्योग मंत्री (श्री लक्ष्मण दास अरोडा): हां, श्रीमान जी।
कुण्डली 9

मानेसर पलवल एक्सप्रेसहाईवे बनाने की परियोजना सरकार के विचाराधीन है। हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम इस परियोजना की कार्यकारिणी संस्था है। 135 किलो मीटर लम्बी यह एक्सप्रेसहाईवे कुण्डली सोनीपत में राष्ट्रीय मार्ग 1 से भुरू होकर झज्जर, बहादुरगढ़, (राष्ट्रीय राजमार्ग 10) मानेसर, गुडगांव राष्ट्रीय राजमार्ग 8 से होता हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को पलवल फरीदाबाद से मिलेगा। करीब 1200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह चार लेनों में विभाजित सड़क परियोजना बी०ओ०टी० के आधार पर क्रियान्वित की जायेगी। राज्य सरकार ने एच०एस०आई०डी०सी० के लिए इस परियोजना के लिए 900 एकड़ भूमि अधिग्रहण कर ली है और इसके अतिरिक्त 2400 एकड़ और भूमि अधिग्रहण की जा रही है। एच०एस०आई०डी०सी० ने इस

परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए मैसर्स के0एम0पी0 एक्सप्रेस वे लिमिटेड की स्वीकृति पत्र जारी किया है इस परियोजना पर जुलाई, 2006 में कार्य शुरू होने की सम्भावना है। इन कंसप्रेसहार्डवे के आस पास औद्योगिक विकास को बढ़ाव देने के लिए बहुत से आर्थिक क्षेत्र विकसित किये जायेंगे।

Cut Imposed on Supply of Electricity

35. Dr. Sita Ram: Will the Minister for Power be pleased to state the month wise detail of the declared and undeclared hours of cuts imposed on rural and Urban feeders during the period from January, 2004 to 31st December, 2004 and March, 2005 to 31st December 2005 separately in the State togetherwith the number of hours the electricity was supplied for 3 phase and 2 phase in 24 hours to each feeder during the above said period?

विद्युत मंत्री (श्री विनोद कुमार भार्मा): श्रीमान् इस प्रान का पूर्ण उत्तर देने के लिए कई लाख आंकड़ों का सर्कलन करना जरूरी है। वाछिंत सूचना इकट्ठी करने में अत्याधिक समय तथा साधन जुटाने पडेगे, जिनकी तुलना में इस प्रान का उत्तर देना लाभप्रद नहीं होगा।

Transfer of Teachers

36. Dr. Sita Ram: Will the Minister for Education be pleased to state

(a) the number of teachers transferred by the Education Department in the Primary, Secondary and Senior Secondary Schools during the year 2005;

(b) whether the said transfers were made according to the Government policy; and

© the financial burden borne by the department on the tranferreferred to in part (a) above?

शिक्षा मंत्री (श्री फूल चन्द मुलाना):

(क) वर्ष 2005 के दौरान प्राथमिक, माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा विभागों द्वारा 11167 अध्यापकों के स्थानान्तरण किए गए।

(ख) हां, श्रीमान जी, ये सभी स्थानान्तरण सरकार की नीति के अनुसार किए गए हैं, केवल 36 अध्यापकों के स्थानान्तरण किए गए।

(ग) इन स्थानान्तरणों के कारण विभाग द्वारा 176491 रू० का वित्तीय बोझ वहन करना पड़ा है।

Violation of Rules

28. Sh. Karan Singh Dalal: Will the Minister for Industries be pleased to state details of prohibited activities/projects which have come up on the lands specified to the table appended to the Aravail Notification dated 7-5-1992 of Ministry of Environment and Forest, Government of India in District Gurgaon since the commencement of

notification till date togetherwith the action taken against the violators and the officers who allowed the violation?

उधोग मंत्री (श्री लक्षमन दास अरोडा): निर्धारित अरावली क्षेत्र मे पर्यावरण संरक्षण हेतू कुछ गतिविधियो को वर्जित करने हेतू पर्यावरण एवम वन मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना न० एस०ओ० 319 (ई) दिनांक 7 मई, 1992 द्वारा जिला गुडगांव हरियाणा एवम जिला अलवर राजस्थान मे कुछेक प्रक्रियाओ और गतिविधियों को बिना पूर्व अनुमति के स्थापित करने को वर्जित किया है। इन गतिविधियो मे खनन, रिहाय गी इकाईयों का निर्माण, फार्महाउस और निर्माण से संबधित अन्य गतिविधियो इत्यादि सम्मिलित है। निर्धारित क्षेत्र मे गैर मुमकिन पहाड वन क्षेत्र आदि सम्मिलि है।

पर्यावरण एवम वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 20.11.1999 (4.1.2000 को संचारित) के द्वारा अधिसूचना 7.5.1992 से सम्बन्धित भाक्तियां राज्य सरकार को प्रदान की गई है इन प्रदान भाक्तियों के अन्तर्गत निर्धारित क्षेत्र मे प्रस्तावित प्रोजैक्ट एमव गतिविधियो के क्लीयरेंस की सिफारि ा करने हेतू एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया जिस अनुसार प्रस्तावित प्रोजैक्ट एमव आवेदकर्ता द्वारा 1992 की अधिसूचना मे दी गई विधि के अनुसार आवेरदन पत्र देना अपेक्षित है। राज्य सरकार के अरावली अधिसूचना के अन्तर्गत अरवाली क्षेत्र मे अब तक 84 गतिविधियो एवम प्रोजैक्टस और स्टोन क्र ार इकाईयो

सडक निर्माण, भूमिगत पाईपलाईन, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, फील्ड फायरिंग रेज आदि सम्मिलित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के तहत सभी उल्लिखित मार्किंग गतिविधियों/प्रोजेक्टों को 2002 से बन्द कर दिया गया है। जहां तक अरवाली अधिनियम की उल्लंखना करने वालों की पहचान का प्रश्न है (जिन्होंने समक्ष प्राधिकरण के पूर्व क्लैसिफिकेशन के बिना उन प्रोजेक्ट/गतिविधियों/निर्माण जो अधिसूचना में दिये गये हैं को आरम्भ किया है।) मई जून 2005 में बोर्ड के गुडगांव स्थित क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण विभाग के अधिकारी, वन एवम खनन विभाग के अधिकारी तथा उपायुक्त द्वारा प्रतिनियुक्त राजस्व विभाग के अधिकारियों को सम्मिलित करके सर्वेक्षण किया गया। इन सर्वेक्षणों में अब तक 863 उल्लंखन कर्ता प्रकाश में आये हैं जिनमें फार्महाउस, रिहायशी कम्प्लैक्स, अन्य संस्थान आदि आते हैं जो मुख्य रूप से पूर्ण एमव आंशिक रूप से अरवाली अधिसूचना के क्लैसिफिकेशन के बगैर निर्मित किये गये प्रतीत होते हैं। भोश को ढूढने की प्रक्रिया जारी है।

अरवाली अधिसूचना के उद्देश्य की पालना करते हुए 561 उल्लंखकर्ताओं को पर्यावरण संरक्षण 1986 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं कि उनके खिलाफ उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही क्यों नहीं की जाये। अब तक 166 उल्लंखन कर्ताओं ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया है। उनके जवाब एवम दिये गये उत्तरों का पुनर्विचार करने हेतु

अधिकारियों की एक उपसमिति का गठन किया गया है। सर्वेक्षण एमव अध्ययन से अब तक यह साबित हुआ है कि 61 फार्महाउस बनाये गये हैं और 11 आंशिक रूप से निर्मित हैं क्षेत्रीय अधिकारी, गुडगांव द्वारा इन उल्लंघनकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। यह निर्णय लिया गया है कि इन प्रोजेक्टों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के नियम 15 के तहत विशेष पर्यावरण न्यायालय में प्रोसिक्यूशन करने के इरादे से शिकायत दायर की जाये।

दो डवैल्परस/बिल्डरस और एक कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को प्रोसिक्यूशन करने के लिए कारण बताओ नोटिस दे दिया गया है।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत कारण बताओ नोटिस देना या भोश अन्यो में उचित कार्यवाही करने हेतु रूप से सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जैसे कि मालिकों की पहचान, संचार पत्राचार आदि की कार्यवाही की जा रही है।

यह विभाग का उद्देश्य है कि अरवाली अधिसूचना को लागू करने में दृढ़ एवम कानूनी कार्यवाही की जाएं। उल्लंघनकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस दिये गये हैं और दिये जा रहे हैं और आगे कार्यवाही उचित विधि का अनुसरण करके ही की जायेगी। यह भी ध्यान में लाया जाता है कि पर्यावरण विभाग/हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अरवाली

अधिसूचना व इसको लागू करने हेतु दिनांक 17.7.2006 और 6.2.2006 को मुख्य समाचार पत्रों में नोटिस देकर आम जनता को आगाह एवम सूचित किया है। पर्यावरण विभाग ने विशेष रूप से नगर एवम बाहरी योजना विभाग सहित सभी सम्बन्धित विभागों को अरवाली अधिसूचना के अधीन निर्धारित क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को रोकने के लिए सूचित किया है। आम जनता की जागरूकता हेतु पर्यावरण विभाग/हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गुडगांव में तीन मुख्य स्थानों पर सचेत होर्डिंग लगावा दिये हैं समाचार पत्र में पडने वाली पचायतों को विशेष तौर पर सतर्क रहने के लिए विदित कर दिया है समाचार पत्र एवम इलैक्ट्रॉनिक मीडिया अरवाली मुद्दों को भामिल करने के लिए अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन सभी उपायों के सहित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत भी प्राकृतिक रूप से कार्यवाही की जा रही है और उम्मीद की जाती है कि अरवाली के साफ सुथरे पर्यावरण के संरक्षण एवम बचाव के लिये आम जनता में जागरूकता पैदा करने से वांछित फल मिलेगा व सभी सम्बन्धित विभागों एवम आम जनता के सहयोग से अरवाली अधिसूचना के उद्देश्यों की प्राप्ति होगी।

स्पष्ट रूप से अपर्याप्त चौकसी एवज जवाब देही को मध्य नजर रखते हुए जिन्होंने अरावली के निर्धारित क्षेत्र में बिना अनुमति के प्रोजैक्ट स्थापित करने की अनुमति दी उस सम्बन्धित

समय के बोर्ड के चार अधिकारियों के खिलाफ अनु नासनिक कार्यवाही भुरु कर दी गई है।

Recruitment made in Haryana Police

32.Sh. Dharam Pal Singh Malik: Will the Chief Minister be pleased to state whether any recruitment of Police Constables, Sub Inspectors and Inspecotrs has been made in Haryana Police during the period form 2000 to 2005; if so, the district was number thereof?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा): श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा है।

2003	निरीक्ष	उप	2002	निरीक्ष	उप	2001	निरीक्ष	उप	2000	वर्ष
सिपाही	सिपाही	सिपाही	सिपाही	पद
3404	1014	1979	001	1915	संख्या
44	04	27	15	पंचकूला
124	033	081	85	अम्बाला
93	34	68	67	यमुनानग
151	038	086	75	पुरुक्षेत्र
196	053	110	123	कैथल
131	037	069	105	गुडगांव
127	024	089	146	फरीदाबा
164	039	063	71	नाननौल
106	030	079	76	रिवाडी
3	मेवात
240	080	143	125	हिसार
226	069	109	129	सिरसा
426	121	176	147	भिवानी
346	113	146	126	जींद
92	39	97	49	फतेहबाद
2122	065	1361	152	रोहतक

		2005				2004			
निरीक्ष	उप	सिपाही	निरीक्ष	उप	सिपाही	निरीक्ष	उप	सिपाही	उप
		0070	0002	095	3419	017		
		03	01	03	15		
		06	02	130		
		02	02	85		
		001	003	151	001		
		002	004	178		
		004	003	149		
		003	140	001		
		003	005	148	001		
		005	004	128	001		
			
		002	011	288	001		
		011	291	002		
		001	001	009	413		
		004	006	428	003		
		03	117	01		
		0050	0060	1361		

घोशणाएं

(क) अध्यक्ष द्वारा

(i) सभापतियों की सूची

Mr. Speaker: Hon' ble Members, under Rule 13 (1) of Rules of Procedur and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the panel of Chairpersons.

1. Shri Balbir Pal Singh, M.L.A
2. Shri Anand Singh, M.L.A
3. Shri Sher Singh, M.L.A
4. Dr. Sushil Indora, M.L.A

(ii) अनुपस्थिति की अनुमति

Mr. Speaker: Hon' ble Members, I have received a letter from Shri Om Parkash Chautala, M.L.A which reads as under-

“I am to inform you that I shall be away to U.S.A for my own treatment. Therefore, I may not attend the Haryana Vidhan Sabha Session commencing from 17-3-2006. Therefore, Leave of absence may please be granted accordingly.

श्री आनंद सिंह राठी: अध्यक्ष महोदय, मै इस लीव एप्लीके तान का विरोध करता हू। (गोर एवम व्यवधान)

डा० सीता राम: अध्यक्ष महोदय, ये क्यों खड़े हो रहे हैं? डाक्टर ने उनको मैडीकल सर्टीफिकेट दिया हुआ है। (गोर एवम व्यवधान)

Shri Anand Singh Dangi: I have a right to speak.
(Interruptions)

Mr. Speaker: Please first know the sense of the House. (Interruptions) please know the sense of the House. Application received by me has been put forth before the House. Please know the sense of the House. (Interruptions)

डा० सु गीला इंदौरा: अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात सुनिए। (गोर एवम व्यवधान)

Mr. Speaker: Indora Ji, please take your seat. Let me know the comments of the Hon' ble Members? Let him speak. (Interruptions)

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब सदन में कब आयेगे? क्या उनमें सदन को फेस करने की हिम्मत नहीं है? (गोर एवम व्यवधान) वे कब स्वस्थ होंगे? (गोर एवम व्यवधान)

श्री आन्नद सिंह राठी: अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात सुनने की कोशिश तो करे। अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं है और वे पहले ही भाग मचा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सदन को बने हुए एक साल से ज्यादा का समय हो गया है और इसका यह

पांचवा सै ान चल रहा है। हर सै ान चल रहा है। हर सै ान मे एक एप्लके ान की जाती है कि श्री ओम प्रका ा चौटाला सदन मे उपस्थित नही हो सकते। अध्यक्ष महोदय, बडे दुख की बात है कि जो व्यक्ति जन सभाओ मे, ब्याह भाादियो मे और वकर्स की मीटिंग्ज मे जा सकता है वह आदमी इस सदन मे नही आ सकता। अध्यक्ष महोदय,रु मै जानना चाहता हू कि जो व्यक्ति 4-4 घंटे किसी सभा मे जाकर बैठ सकता है वह इस सदन मे दो घंटे आकर जन भावनाओ को प्रकट क्यों नही कर सकता ? अध्यक्ष महोदय, मै किसी राजनैतिक द्ववेशता के कारण ऐसी बात नही कर रहा हू, मै किसी की मजबूरी का फायदा नही उठा रहा हू। द्ववेशता के कारण ऐसी बात नही कर रहा हू, जो सही है, सच है। बीमार तो कभी कोई भी हो सकता है लेकिन जो आदमी सभाओ मे जाये उस समय उसकी बीमारी कहा चली जाती है? जिस समय पहली बार उनकी एप्लीके ान आई थी उस समय उसकी हमने भगवान से प्रार्थना की थी कि वह उनको जल्दी से से स्वस्थ करे ताकि वे यहां सदन मे आये और पिछले पांच साल के दौरान उन्होने जो गलत कार्य किया, उनको सुने। अध्यक्ष महोदय, ओम प्रका ा चौटाला जी सदन मे आने की हिम्मत ही नही कर पा रहे है क्योंकि उन्होने अपने पांच साल के राज मे हरियाणा की जनता के साथ जिस तरह का वि वासघात किया, उसको जनता आज भी नही भूल पाई है। उन्होने प्रदे ा को हर तरह से बर्बाद करने की को ि ा ा की और झूठ बोलकर जनता को लूटने का काम किया था। यही कारण है कि आज वे सदन मे आने की हिम्मत

नहीं कर पा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश को जिस तरह से बर्बाद और तबाह करने की कोशिश की गई, जिस प्रकार से झूठ बोल कर इस प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया गया, आज वह व्यक्ति इस सदन में आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह तो होना ही था। (विधन एवम व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, सैंस आफ मे मैं एक बार कह रहा हूँ इनके नेता ने जिस प्रकार कुकृत्य किए हैं उनकी बात सुन तो लीजिए। माननीय सदस्य वे बातें बताने लग रहे हैं। उनके कुकृत्य का छोटा या पिटारा है, दांगी साहब उसे खोलने का प्रयास कर रहे हैं। (विधन एवम भाोर) इस समय कई माननीय सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो कर बोलते रहे और भाोर भाराबा करते रहे।

Mr. Speaker: Indora Sahib, I should obtain the sense of the House that the House wants to grant the leave of absence or not.

श्री आनन्द सिंह डांगी: अध्यक्ष महोदय, हर आदमी जो चुनकर आया है, वह अपनी बात हाउस में रखने का अधिकार रखता है। यह बात यहां पर रखी जाएगी और लिखित रूप से रखी जाएगी। (विधन एवम भाोर) अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब का मन करता है सदन में आने का लेकिन ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। (विधन एवम भाोर)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, इन लोगो से कहिए कि ये लोग पहले अपने कान बन्द कर ले फिर डांगी साहब, अपनी बात कह लेंगे। उनकी कही हुई बात को सुनने का आपका कोई अधिकार और अख्तियार नहीं है। (विघ्न एवम भाोर) अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने कान बन्द नहीं किए हैं फिर इनके नेता इनको पार्टी से बाहर निकाल देंगे इसलिए इनको चाहिए कि ये अपने कान बन्द कर लें। ये लोग इन्स्ट्रक् ऑन्ज को पूरी तरह से लागू नहीं कर रहे हैं। (विघ्न एवम भाोर) वे लोगो को क्या कहेंगे? (विघ्न एवम भाोर) इन्दौरा साहब, आप लोग बन्द करके रखें नहीं तो उनको पता चल जाएगा। वे आपको वही से देख लेंगे। आलोचना न सुनने की उनकी आदत इतनी कम हो गई है कि धीरे धीरे आपके पूरे नम्बर लग जाएंगे, आप लोग अपने कान बन्द करके बैठ जाएं और उनकी बात सुनिए। (विघ्न एवम भाोर)

श्री आनन्द सिंह डांगी: अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सारे ही भारीफ लोग हैं लेकिन इनको ऐसे ही आदे ा देकर विधान सभा में भेजा जाता है कि सदन में ये लोग किसी भी आदमी को बोलने न दें और जब दूसरे लोग बोल रहे हों ये लोग बीच में इन्टरवीन करें। (विघ्न एवम भाोर)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, इनका कसूर नहीं है इन्होंने कान पकट कर माफी मांगी थी, एक बार ये लोग अपने कान पकड़े तो डांग साहब इनको माफ कर देंगे। ये लोग एक बार फिर कान पकड कर देखें। (विघ्न एवम भाोर)

श्री आनन्द सिंह डांगी: अध्यक्ष महोदय, मैं तो इस सदन में उनके न आने की असल वजह बता रहा हूँ। (विधन एवम भाोर) वह व्यक्ति सदन में आने से क्यों हिचकता है, हाउस में आने से क्यों डरता है क्योंकि ऐसी बातें सदन में कही गई हैं कि वह आज सदन में आकर इस सदन को फेस नहीं कर सकता। (विधन एवम भाोर)

Mr. Speaker: Please maintain the decorum of the House (Interruptions)

श्री आनन्द सिंह डांगी: अध्यक्ष महोदय, आप सब जानते हैं कि इस विधान सभा में जब ओम प्रकाश चौटाला इस सदन के नेता थे और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे तो ओम प्रकाश चौटाला जी खुले भावों में कहते थे कि जब तक जीउंगा तब तक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहूंगा और इन लोगों की छाती पर मूंग दलूंगा। (विधन एवम भाोर) अध्यक्ष महोदय, इन लोगों को चाहिए कि यह सपना को छोड़ दें। (विधन एवम भाोर) आज किस मुंह से वह इस सदन में आ सकते हैं? (विधन एवम भाोर) अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी आज सत्ता में आ गई है और जो यह कहते थे कि भूपेन्द्र सिंह हुडा कभी मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते वह आज देख लें। अध्यक्ष महोदय, आज हमें बड़े फरख के साथ कह सकते हैं और हरियाणा प्रदेश की जनता को बार बार हम इस बात के लिए बधाई देते हैं कि

उसने ऐसे घमण्डी व्यक्ति को सता से निकाल फेंका और चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुडा जैसे नैक इंसान को हरियाणा प्रदे 1 की सता हरियाणा प्रदे 1 को आगे बढाने के लिए सौपी है। (विघ्न एवम भाोर) स्पीकर साहब, आप भी उस समय इस माननीय सदन के सदस्य थे। (विघ्न एवम भाोर) आप विरोध भी उनका कर रहे थे कि यह मुख्यमंत्री सारी जिन्दगी रहेगा। लेकिन आज यहां पर उनकी बजाए चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुडा बैठ हुए है। (भाोर एवम व्यवधान) उस समय डा0 रघुबीर सिंह कादियान को सदन मे बोलने नही देते थे, सदन से बाहर कर देते थे लेकिन ये आज यहां पर स्पीकर के पद को सु ोभित कर रहे है। उस वक्त तो ओम प्रका 1 चौटाला यह कहा जाता है कि आन्द सिंह डांगी को जिन्दगी भर विधान सभा मे आने नही दूंगा, विधान सभा का मुंह नही देखने दूंगा। ये देखो आज मै विधान सभा मे बैठा हुआ हू। और मै ओम प्रका 1 चौटाला को चैलेज करता हू कि वे विधान सभा मे हाजिर हो और तब हम देखगे कि यह किस तरह से विधान सभा मे इस बात को डिफैड करता है? (भाोर एवम व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, चोरो को सभी चोर नजर आते है। दांगी साहब को सभी दांगी नजर आते है। मै तो यह कहता हू कि ओम प्रका 1 चौटाला जैसा चोर और ठग सारे हरियाणा मे आज तक कोई पैदा नही हुआ है। (भाोर एवम व्यवधान) इस समय इण्डियन नै ानल लोक दल के सदन मे उपस्थित सभी सदस्य सदन की वैल मे आ गए और नारे बाजी करने लगे। स्पीकर सर, मै नही

चाहता था कि इस तरह की बात की जाए लेकिन ये लोग मुझे ऐसा बोलने पर मजबूर कर रहे हैं। (भाोर एवम व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, इनको यह सिखाए कि जब माननीय सदस्य अपनी बात बोल रहे हो तो इनको इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। आप इनको अपनी सीटो पर बिठाएं। (भाोर एवम व्यवधान) ये सदन मे ठीक तरह से बात करनी तो सीख ले। (भाोर एवम व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह डांडी: अध्यक्ष महोदय, अब वे वाक आउट करेगे। (भाोर एवम व्यवधान) अब इनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। (भाोर एवम व्यवधान)

Mr. Speaker: I should obtain the sense of the House whether the leave of absence be granted or not?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि ओम प्रकाश जी ने लिखा है कि वे अस्वस्थ है और उन्होंने सैदान अटैंड करने की एग्जम्पशन जारी मांगी है इस बारे में डांगी साहब ने चर्चा की है, हमारे दूसरे कई साथियो ने चर्चा की है। अध्यक्ष महोदय, प्रजान्तंत्र है वे चुनकर आए है इसलिए वे सदन में चर्चा कर सकते है अध्यक्ष महोदय, यह प्रजातंत्र के हित में है और मैं भी चाहता हू कि श्री ओम प्रकाश चौटाला जी सदन में आए ताकि उनके जो एक्सपीरियंस है उनसे यह सदन और मैं भी कुछ लाभ उठा सकू। (भाोर एवम व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, एक साल से वे सदन में नहीं आए है। अध्यक्ष महोदय, यह भी सत्य है कि जब

पिछली दफा विधान सभा का सै । न था तो उससे पहले भी और उसके एकदम बाद भी वे पब्लिक मीटिंग अटैंड करते रहे हैं। लेकिन इस वक्त वे अस्वस्थ हैं और अपना इलाज करवाने के लिए विदे । में गए हुए हैं। अस्वस्थ कोई भी हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे आज भी वह समय याद है जब पिछली सरकार के वक्त आप बोलने के लिए खड़े होते थे तो आपको मुंह भी खोलने नहीं दिया जाता था और आपको मा । लिज के द्वारा उठाकर बाहर फैंक दिया जाता था। अध्यक्ष महोदय, हम प्रजातंत्र में वि । वास रखते हैं और मैं आपके माध्यम से सदन में सभी को वि । वास दिलाना चाहता हूँ कि जब ओम प्रका । चौटाला जी यहां पर आएंगे तो हम यह काम नहीं करेंगे जो वे करवाया करते थे। मेरा अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि श्री ओम प्रका । चौटाला जी की लीव ग्रान्ट की जाए।

Mr. Speaker: Question is-

That permission for leave of absence for the current Session of Haryana Vidhan Sabha be granted.

Voices: Yes

The motion was carried.

(ख) सचिव द्वारा

राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी

Mr. Speaker : Now, the Secretary will make an announcement.

सचिव: माननीय महोदय, मैं उन विधेयको को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने दिसम्बर 2005 तथा जनवरी 2006 में हुए सत्रों में पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है सादर सदन की मेज पर रखता हूँ।

December Session, 2005

1. The Kurukshetra Shrine (Repeal) Bill, **2005.**
2. The Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2005.
3. The Haryana Industrial Promotion Bill. 2005.
4. The Haryana Special Economic Zone, Bill, 2005.
5. The Haryana Municipal (Second Amendment) Bill, 2005.
6. The Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill. 2005.
7. The Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill, 2005.
8. The Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) 2nd Amendment Bill, 2005.
9. The Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill, 2005.
10. The Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill, 2005.
11. The Haryana Murrah Buffalo and other Mulch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandry and Dairy Development Sector) Amendment Bill,

2005.

12.The Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill, 2005.

January Session, 2006

1. The Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendement Bill, 2006.

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now I report the time table of the various Business fixed by the Business Advisory Committee.

"The Commitee meet at 11.00 P.M. on Friday, the 17th March, 2006 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

"The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs, the Assembly, whilst in session, shall meet on Monday at 2.00 P.M and adjourn at 6.30 P.M. Tuesday, Wednesday, and Friday will meet at 9.30 A.M and adjourn at adjourn at 1.30 P.m without question being put.

However, on Friday, the 17th March, 2006 the Assembly shall meet at 2.00 P.M and adjorn after the conclusion of business entered in the list of business for the day.

The Committee after some discussion also recommends that the business on 17th, 20th to 24th March, 2006 be transacted by the Sabha as follows:-

Friday, the 17 th June, 2006 (2-00 P.M)	1	Obituary Referecnes
	2.	Question Hour.
	3	Presentation and adoption of First Report of the Business Advisory Committee
	4.	Motion under Rule 121
	5.	Papers to be laid/re- laid on the Table of the House.
	6.	Presentation of Supplementary Estimate for the year 2005-2006 and the report of the Estimates Committee thereon,
	7.	Presentation of Budget Estimates for the year 2006-2007
Saturday, the 18 th	1.	Holiday.

March, 2006.		
Saturday, the 19 th March, 2006.	1.	Holiday.
Monday, the 20 th March, 2006 (2.00 P.M)	1.	Question Hour
	2.	General Discussion on Budget Estimates for the year 2006-2007.
Tuesday, the 21 th March, 2006 (9.30 A.M)	1.	Question Hour
	2.	Presentation of Report of Assembly Committees.
	3.	Resumption of Discussion on Budget Estimates for the year 2006-2007
Wednesday, the 22 th March, 2006 (9.30 A.M)	1.	Questions Hour
	2.	Reply by the Finance Minister

	3.	Discussion and Voting On Supplementary Estimates for the year 2005-2006
	4.	Discussion and Voting on Demands for Grants on Budget Estimates for the year 2006-2007.
Thursday, the 23 rd March, 2006 (9.30 A.M)	1.	Questions Hour
	2.	Non official Business
Friday, the 24 th March, 2006 (9.30 A.M)	1.	Questions Hour
	2.	Presentation of Reports of Assembly Committees.
	3.	The Haryana Appropriation Bill in respect of Supplementary Estimates for the year

		2005-2006.
	4.	The Haryana Appropriation Bill in respect of Budget Estimates for the year 2006-2007.
	5.	Legislative Business
	6.	Any other Business.”

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion that this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move--

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker: Question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory

Committee.

The motion was carried

नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : No the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 121.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I

beg to move—

That the provisions of Rules 231, 233, 235 and 270 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in so-far they relate to the constitution of the: —

(i) Committee on Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates;

(iii) Committee on Public Undertakings, and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled

Tribes & Backward Cusses,

for the year 2006-2007 be suspended.

Sir, I also beg to move—

That this House authorizes the Speaker, Haryana

Vidhan Sabha, to nominate the Members of tilt. Aforesaid Committees for the year 2006-2007, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the provisions of Rules 231, 233. 235 and 270 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in so-far they relate to the constitution of the: —

(i) Committee on Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates;

(iii) Committee on Public Undertakings, and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled

Tribes & Backward Cusses,

for the year 2006-2007 be suspended.

And

That this House authorizes the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Members of tilt. Aforesaid Committees for the year 2006-2007, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the provisions of Rules 231, 233, 235 and 270 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in so far they relate to the constitution of the: —

(i) Committee on Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates;

(iii) Committee on Public Undertakings, and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled

Tribes & Backward Castes,

for the year 2006-2007 be suspended.

That this House authorizes the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 2006-2007, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

The motion was carried

सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे कागज पत्र

Mr. Speaker: Now, a Minister will lay the papers on the Table of the House.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to lay on the Table of the House.

The Haryana State Legislature (Prevention of

Disqualification amendment Ordinance, 2006 (Haryana Ordinance No. 1 of 2006).

Sir, I also beg to re-lay on the Table of the House—

The Personnel Department Notification No. GS.R. 3/Const./Art. 320/2005, dated the 15th June, 2005 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Amendment Regulations, 2005, as required under Article 320 (5) of the Constitution of India.

The Personnel Department Notification No. GS.R. 5/Consu'Art. 320/2005, dated the 20th June, 2005, regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Amendment Regulations, 2005, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Personnel Department Notification No. GS.R. 18/Const./Art. 320/ 2005, dated the 29th November, 2005 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Amendment Regulations, 2005, as required under Article 320 (5) of the Constitution of India.

Sir, I also beg to lay on the Table of the House—

The General Administration Department Notification No. S.O. 4/H.A. 9/ 19791S.8/2006, dated the 13th January, 2006, regarding the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Rules, 2005, as required under section 8 (3) of the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Act, 1979.

The Parliamentary Affairs Department Notification No. S.O. 5/H.A. 3/ 1970/S.9/2006, dated the 13th January,

2006 regarding the Haryana Ministers Allowances (Amendment) Rules, 2005, as required under section 9 (2) of the Haryana Salaries and Allowances of Ministers Act. 1970.

The Parliamentary Affairs Department Notification No. S.O. 30/H.A. 3/ Sc .8 and 9/2006, dated the 27th Febuary, 2006 regarding the Haryana Ministers Allowances (Amendment) Rules, 2005, as required under section 9 (2) of the Haryana Salaries and Allowances of Ministers Act. 1970.

The Excise and Taation Departement Notification No. S.O. 1/H.A. 6/2003/Sc 6/2006, dated the 10th January, 2006 regarding the Haryana Value Added Tax (Amendment) Rules, 2006, as required under section 60 (4) of the Haryana Value Added Tax Act. 1970.

The Excise and Taation Departement Notification No. S.O. 2/P.A.16/1955/S 3/2006, dated the 12th January, 2006 regarding the a,emd,emtom the Haryana Government Prohibition, Excise and Taxation Department Notification No. S.O 89/P.A 16/55/S.3/2001, dated 29th June, 2001, reducing the rate of the duty as required under section 3(4) of the Punjab Entertainmetns Duty Act. 1970.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 2005 (Civil) Government of Haryana in pursuances of the provisions of Cluase (2) of Article 151 of the Contitution of India.

The Annual Report of the Haryana Electricitiy Regulatory Commission for the year 2003-2004, as required under section 10 4(4) and (4) 105 of the Haryana Electricitiy Act. 2003.

वाक आउट

ड० सु गीला इंदौरा: अध्यक्ष महोदय, मैने जीरो आवर के लिए नोटिस दिया है कि चौधरी देवी लाल थर्मल पावर प्लांट से उनके नाम हटाये जाने के बार मे सरकार स्टेटमेंट दे क्यांकि सदन स्वतन्त्रता सेनानियों को नमन करता है और चौधरी देवी लाल को स्वतंत्रता सेनानी रहे है। (गोर एवम व्यवधान)

Mr. Speaker: Indora Ji, It is an old convention कि जिस दिन बजट पे ग होता है उस दिन जीरो आवर नही होता। यह जनरल कन्वै िन है। You know everything. You know parliamentary practices.

ड० सु गीला इंदौरा: अध्यक्ष महोदय, हमने कुछ मुद्दे हाउस मे उठाने के लिए नियमानुसार नोटिस दिया है लेनिक यदि आप हमारी बात नही सुनते तो हम सदन से एज ए प्रोटैस्ट वांक आउट करते है।

इस समय इण्डियन नै ानल लोकदल के सदन से उपस्थित सभी सदस्य एज एक प्रोटैस्ट सदन से वाक आउट कर गये है।

अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत करना

Mr. Speaker: Now, the Hon'ble Finance Minister will present the Supplementary Estimates 2005-2006.

Finance Minister (Shri Birender Singh): Sir, I beg

to present the Supplementary Estimates 2005-2006.

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

Mr. Speaker: Now, Sh. Karana Singh Dalal, Chairperson, Committee on Estimates will present the Report of the Committee on Estimates of the Supplementary Estimates, 2005-06.

Shri karan Singh Dalal: Sir, I Beg to present the report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates, 2005-06.

वर्ष 2006-07 के लिए बजट अनुमाना प्रस्तुत करना

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will present the Budget Estimates for the year 2005-06.

Finance Minister (Sh. Birender Singh): Hon'ble Mr. Speaker, I rise to present before this august House the Budget Estimate for the year, 2005-06.

2. This is the second budget of this Government which received people's mandate in the election 2005 with a landslide victory. It was a vote for change in favour of rule of law and for good governance. We acknowledge the silent but effective signals emanating from our enlightened electorate. Though one year is too short a time to fulfill all the expectations of the people of the people and to boast so much of concrete achievements; nevertheless the different steps taken by us so far have contributed substantially in bringing about qualitative change in the life of the people. There was a general erosion of authority visible during the regime of the previous Government

which had demoralized the law enforcement machinery. In the last budget, I had promised our Government's commitment to provide clean & benevolent governance sans fear, intimidation and insecurity. We have successfully fulfilled this promised our governance sans fear, intimidation and insecurity. We have successfully fulfilled this promise and restored the confidence of people in democratic process and the rule of law. The state of Haryana has now embarked the gains of economic liberalization and strengthened the States economic base. Our innovative and progressive policies have been duly endorsed by the people of the State as has been amply reflected in the recent by elections by the people of the State as has been amply reflected in the recent by elections of Rohtak Parliamentary Constituency, three Assembly Constituencies and the the election to Panchayati Raj and Urban Local Bodies.

3. Indian National Congress party has fought the last election in the State with a set of proposals/promises duly incorporated in our Election Manifesto. These proposals are comprehensive and involve every aspect of economy from agriculture to industry and from social sector to employment. It reflects the concern for common man. Our priorities are in conformity with the economic reforms started in 1991 by the then Union Finance Minister Dr. Manmohan Singh who is now Prime Minister of our Country. The reforms have brought qualitative change in the country's economy. However to further accelerate the process we need to address certain key challenges. It calls for integration of rural economy and the lower income urban population with the economic mainstream. The holistic development of both the agricultural and non-agricultural rural economy would be a key focus area of our Government.

4. The progressive and forward looking policies being followed by UPA Government at the Centre are likely to bring about profound changes in the functioning of the State economy. Considering the fact that majority of the people in the country reside in rural areas and poverty is most visible amongst them, the present Central Government has rightly focused their attention on bringing about radical changes in the rural set up. Lack of employment is a perennial problem in the rural area and to address that, the Central Government has launched a Rural Employment Guarantee Scheme to be substantially funded by them. Haryana is going to be benefited to the extent that two of its districts have been included out of the 200 districts identified at the national level in the first phase. The other flagship programme of Government of India is Bharat Ninnan which is again focused on the infrastructure upgradation in the rural area and to unleash its growth potential. Haryana is likely to get substantial financial assistance in improvement of the rural roads under this programme. We are proud that most of the schemes envisaged under the Bharat Nirman programme have already been completed by the State long back through its rural connectivity programme in power, road network, providing drinking water facilities etc. Simultaneously with the rural upliftment, high priority has also been attached for bringing about structural transformation in the urban areas through Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission. Faridabad in Haryana has been chosen as one of the towns which would be taken up under this programme for which detailed planning is being carried out. Separately we have made a request to Government of India to include entire

NCR of Haryana and Panchkula town under this Mission since the problems of these areas are of same nature. In case our request is acceded to, we expect substantial flow of funds in this area for augmentation of urban infrastructure facilities.

5. The national economy has been at a high growth path in the recent years. Naturally the budget announced by the UPA Government a few days back rides on the upbeat economic momentum. It increases spending on social sector, agriculture and infrastructure and at the same time lays emphasis on fiscal consolidation. Spending restraint is also a key point on which fiscal deficit projection for the new year is based. The budget sends a clear message about the Government priorities of higher investment in the farm and rural sector with a firm commitment to social equity. Haryana State is likely to benefit substantially due to sufficient higher allocations by Government of India during 2006-07 under their flagship Bharat Nirman Programme.

STATE OF ECONOMY

6. Sir now, we are the leaders of the States of the country so far as the economy is concerned. The Economic Survey of Haryana, which has already been Circulated amongst the Humble Members, highlights the overall economic situation of the State. It indicates that the Gross State Domestic Product (GSDP) of Haryana at constant (1993-94) prices has recorded a growth of 8.4, percent from Rs. 40131 crore in 2003-04 to Rs. 43502, during 2004-05. At current prices the GSDP has recorded a growth of 12.2 percent from

Rs. 73961 crore in 2003-04 to Rs. 83003 crore in 2004-05 as against 11.8 percent at the national level. Further, it reveals that the contribution of primary sector including agriculture has declined to 28.2 percent in 2004-05 from 42.5 percent in 1993-94 whereas secondary and tertiary sector contribute 27.4 percent and 44.4 percent respectively as against 26.2 percent and 31.3 percent in 1993-94. The increase in secondary and tertiary sector is indicative of healthy growth of our economy.

7. The per capita income at constant prices has grown to Rs. 16872 in 2004-05 as compared to Rs. 15752 in 2003-04, indicating a growth rate of 7.1 percent. The per capita income at current prices is estimated at Rs. 32712 in 2004-05 as against Rs. 29504 in 2003-04, with growth rate of 10.9 percent. The per capita income of the State is highest in the country only next to Goa. In the current fiscal year also the State's economy has witnessed a steady growth coupled with stability despite complex and challenging national and international environment. The recent economic trend indicates strong buoyancy with rising industrial growth, a healthy expansion of service sector and improvement in agricultural performance. Rising domestic demand has proved to be a key growth driver as increasing household income has led to demand for a variety of products and services which has accelerated the economic growth and household prosperity.

TWELFTH FINANCE COMMISSION

8. The Hon'ble Members would recall that the recommendations of Twelfth Finance Commission (TFC) are likely to bring about radical change in the financing of the

State economy. The recommendations have already been accepted by the Central Government and have become mandatory for the State Government to implement them in order to avail financial incentives mentioned therein. Consequently we have chalked out comprehensive fiscal correction path to achieve the targets mentioned in the TFC report. We would try to increase our revenue base and reorient our expenditure with more focus on social sector and economic infrastructure.

9. TFC has recommended consolidation of all existing loans provided to the States up to March 31, 2004 which are outstanding on March 31, 2005 and rescheduling them for a fresh repayment period of 20 years with an interest rate of 7.5 percent on the precondition of adopting Fiscal Responsibility legislation. In addition to providing general relief by consolidating and rescheduling of loans, TFC has framed a scheme of debt waiver based on fiscal performance.

10. As per the above recommendations of TFC, our Government has enacted the Fiscal Responsibility & Budget Management (FRBM), Act in July 2005. The State Government is now under an obligation to eliminate the revenue deficit and to contain fiscal deficit to the level of 3 percent of GSDP by 2008-09. Further, the State debt including contingent liabilities of the guarantees is to be brought down to the ratio of 28 percent of GSDP in the next four years from the present level of about 32 percent.

11. The financial management of State Government has been acclaimed both by Government of India and the 12th Fiancé Commission of India particularly in the areas of

revenue growth, expenditure control, and reduction of deficit indicators. We are confident that fiscal indicators would further improve in future as per the FRBM targets. We feel that by adhering to the Fiscal Correction Path chalked out by our State, we shall be able to derive maximum benefit out of the fiscal consolidation, reschedulement, and debt waiver facility offered by Government of India under TFC recommendations.

COMPLIANCE OF FRBM ACT

12. We have taken a number of measures in compliance of Fiscal Responsibility & Budget Management Act, 2005. It is a composite strategy of revenue augmentation, expenditure curtailment, and debt management. I am briefly listing them as under:-

Increase in Revenue Receipts: Due to sustained efforts by various Departments our revenue receipts are likely to increase by Rs. 600 crore over the budget estimates (2005-06).

Debt Swapping to reduce interest Liabilities: In the past we had resorted to debt swap under a Government of India scheme whereby debts carrying interest rates higher than 13 percent were swapped with lower interest debts which reduced our interest burden by Rs. 200 crore per annum. Our efforts in this regard are continuing and we are in the process of debt swapping of all loans carrying interest rate above 10 percent.

Reduction of Contingent Liabilities by transferring to hypothecation in lieu of State Guarantees:

We have taken up with Power utilities, HUDA and HSIDC to discharge the State Government of our liability on account of State guarantee and secure the debt by hypothecation of their assets with lending agency.

A Resource Mobilization Committee has been set up under the Chairmanship of Chief Minister. The Committee has taken a number of stamps to mop up additional revenue.

We have introduced **New Contributory Pension Scheme** w.e.f. 1-1-2006 and all employees recruited hereafter will be covered under this scheme. It will reduce our pension liability in future.

With a view to facilitate quicker decision making, the administrative departments have been delegated vast financial powers to sanction expenditure under approved plan schemes. This will facilitate efficient utilization of funds.

13. Financial management cannot be looked into in isolation as it is an integral part of the overall administration of State. Any administrative reform and restructuring is bound to improve the financial management as well. In recognition of the need for fiscal restructuring, the present Government has initiated a number of reforms including updating of rules, delegation/decentralization of powers, and integration of different Departments and rationalization of staffing pattern in Government and public sector undertakings. These, apart from improving administrative efficiency, are likely to bring substantial savings for the Government. Sir, when there was news for 6th Pay Commission to be constituted by the Government of Indian, we are committed to implement the pay

revision benefits as would be recommended by the 6th Pay Commission to our employees. (Thumping)

ANNUAL PLAN 2006-07

14. Speaker Sir, in the five years of the last Government, they have raised their Annual Plan from 1800 crore to 2060 crore. Now, you can see from the last year that there is an increase of more than 40%. Speaker Sir, to adhere to our Government's commitment to usher in an all round development of the State, the State Plan outlay for 2006-07 has been kept still higher at Rs. 3300 crore. It has already been approved by the Planning Commission of India in its meeting held with Chief Minister on 13th February, 2006. This indicates the capability of the State Government to generate such high level of resources for plan after meeting all our non-plan commitments. Through judicious allocation of resources to different sectors of economy, we have tried to achieve a balanced growth with equity and social justice.

15. It would be relevant to mention here that in the Annual Plan 2006-07, 35 old schemes have been dropped and in their place 41 new schemes have been taken up keeping in view the changing economic scenario and the necessity of introducing new schemes ideas for all round development.

16. Our Government has maintained its highest priority to the development of social services and physical infrastructure. Accordingly, Rs 1568.92 crore, which constitute 47.54 percent of Plan outlay, has been allocated towards social sector. It includes Rs. 490 crore for social welfare with special focus on allowance for the aged,

handicapped, and widows and destitute towards whom we owe a special responsibility. Further, a sum of Rs. 290 crore has been allocated for education which is 27 percent more than the last year's plan. There is a provision of Rs. 60 crore of improving technical education which is 20 percent higher than last year's allocation. Similarly for health sector, the outlay is Rs. 144.5 crore which is 12 percent higher than last year's allocation. A sum of Rs. 330 crore has been proposed for augmenting the drinking water supply & improvement of sanitation, which is 35 percent greater than the last year's allocation.

17. Due attention has continued to be given to the improvement of physical infrastructure in the State with an outlay of Rs. 1250 crore which constitutes 37.88 percent of the total plan outlay. Adequate allocations have been made for irrigation with an outlay of Rs. 498 crore for generation, transmission, & distribution of power and Rs. 303.2 crore for the improvement of roads, and transport. An allocation of Rs. 42.5 crore has been made for housing sector which also includes police housing. There is a provision of Rs. 90.89 crore for urban development.

18. The year 2006-07 is the last year of the Tenth Five Plan which was approved at Rs. 12000 crore for the State with highest priority to the expansion of social services followed by improvement in economic infrastructure. With the finalization of our annual plan 2006-07 at Rs. 3300 crore we shall be able to achieve our targets as envisaged under the Tenth Five Year Plan.

19. Speaker Sir, the outlay for the Annual Plan 2006-07, is resource based and our Government is fully committed to optimally utilize these funds for the all round development of the State in best interest of its citizens. Our emphasis would be on performance and quality.

MAJOR INTIATIVES

20. Sir, despite our achievements we have still to find out the ways for our thrust areas. Our Government took a very bold initiative to settle the long pending issue of arrears of power bills of farmers and rural domestic consumers. This problem is more than a decade old. This issue was politically exploited from time to time to misguide the farmers by promising free supply of water and electricity. इस विशय बारे मे मुख्यमंत्री जी को एक भोर से सम्बोधित करना चाहता हू।

मै एक कतरा हू मेरा एक अलग वजदू तो है
हुआ करे जो समुद्र मेरी तला । मे तो है ।

It goes to the credit of the present Government for launching an innovative scheme to benefit all those farmers who are keen to pay the current power bill by remitting their arrears to the tune of Rs. 1600 crore. The scheme has received encouraging response. The consumers who had been chronic defaulters have been brought within the mainstream and a sense of discipline was introduced in the power sector. This has brought about much needed changes in the country side and would usher in an era of prosperity in the long run. By waiving

off the unpaid bills, the Government has neither paid a dole to the farmers nor set up ad bad precedent of distribution of free electricity.

21. Another bold initiative, which has benefited the farmers, is fixing a floor rate for land acquisition keeping in view the economic potential of the area. It would not only give a just price to the land owners but would also reduce numerous litigations arising out of inadequate land compensation in the past. अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात इसमें कहना चाहूंगा कि मैं करीब एक महीने पहले टी.वी. देख रहा था। उस समय टी.वी. पर कह रहे थे कि हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा करोड़पति हैं और उनमें सबसे ज्यादा किसान हैं। उसमें बता रहे थे कि दिल्ली के 100 किलोमीटर के दायरे में जिस किसान के पास दो एकड़ जमीन भी है वह किसान भी करोड़पति है अध्यक्ष महोदय, यह इस सरकार की देन है। आज चौटाला साहब की जो हालत है वह मैं एक भोर से कहना चाहूंगा कि

कल को जो माझी भी था, पाती भी था

और आज एक एक को कहता है बचा लो मुझे

Investment, both domestic well as foreign and achieve balanced development by focusing on backward areas of State.

22. Our Government has revised the State Advised Price of Sugarcane to Rs. 135 per quintal which is highest in the country. It will give much needed relief to farmers who were shifting away from sugarcane production. This will also generate an extra income of Rs. 90 crore per year to them.

23. The norms of compensation to farmers on account of failure of crops due to natural calamities fixed by Government of India were quite low. Our Government has revised them upward to compensate substantially in the event of loss of crop under circumstances beyond their control.

24. Equitable and fair distribution of canal water to all the regions of the State is one of the priorities of our Government. A new irrigation project viz BMLHansi-Butana Multi Purpose Link Channel at an investment of Rs. 1259 crore is being taken up for this purpose. Our Government has supplied 25 per cent more canal water in the year 2005-06 to southern Haryana than what was given in the earlier years.

25. Our Government is keen on utilizing the excess water of Yamuna which goes waste in the peak season. During rainy season, huge quantity of water flows down the river causing floods in the region whereas in lean season the water availability is very meagre. To tackle this problem, there is a dire need of constructing 3 dams at Renuka, Kishau and Lakhwar-Wyasi in the upper reaches of river Yamuna. Sir, this would go a long way to strengthen the economy of the entire State. These projects require huge investments for which we have taken up the matter with Government of India.

26. The new Industrial Policy 2005 announced by our Government has started yielding rich dividends and the investors have started to look at Haryana as a favorable destination. The policy primarily aims at providing time bound clearance to prospective investors for setting up of industries through a single window approach. The policy also facilitates

spatial dispersal of economic activities particularly in economically and socially backward regions of the State.

27. The recently passed Haryana Industrial Promotion Act, 2005 provides the much needed mandate for expeditious grants of approvals and sanctions. The Government of India has already granted its approval in principle for establishing ten Special Economic Zones (SEZs) in the State and ten more are in the process to be approved. Some more mega SEZ proposals are likely to come up in near future. The main objective of this policy is to generate maximum employment by inviting

28. We have come up with State Labour Policy announced on 12-1-2006 which is first of its kind in the country. The Labour Policy aims at evolving a mutually & increasingly beneficial partnership between employers and workers, to create conducive conditions at workplace for increasing productivity, prevention of exploitation of workers and protection of their rights, resolution of industrial disputes through social dialogue, fostering peaceful and in-house settlement of disputes etc. The Endeavour is to maximize the welfare of labour without compromising industrial productivity.

29. Unemployment is a threat to our social fabric. My Government is committed for creating employment opportunities within the State and facilitates overseas job seekers. As per my announcement a in the last budget, Haryana Overseas Placement Assistance Society has been set up. The Society shall provide information, guidance and assistance in respect of opportunities available for overseas

studies & placements, facilities for skill improvement and obtaining passport, visa etc. All the employment exchanges of the State shall function as facilitation centers. The Society shall also obtain certificate of registration under the Emigration Act from Government of India and thereafter an Overseas Placement Bureau shall be set up under the aegis of the Society to function as recruiting agency for the purpose of overseas placements.

30. We have also come up with a forward looking Excise Policy which aims at curbing monopolistic tendencies and formation of cartels in the allotment of liquor vend. Under this policy, the system of auction of retail liquor outlets has been discontinued and instead, the same will be allotted by inviting applications and draw of lots if there are more than one applicant for a particular vend. At the same time we have reduced the excise duty rates on country and Indian made foreign liquor (IMFL) to prevent malpractices like smuggling, adulteration etc. The revenue on account of reduction of excise duty is to be recovered in the form of license fee. We anticipate excise revenue of Rs. 1200 crore during 2006-07 as against budget provision of Rs. 967 crore of 2005-06.

2006 THE YEAR OF GIRL CHILD

31. Haryana has witnessed a sharp decline in the sex ratio over the years. Our Government is very conscious of this and has taken steps to remedy the situation. A number of decisions have been taken by our Government to raise the status of girl children. A new scheme namely 'Ladli' has been launched under which an incentive of Rs. 5000 per year for five years shall be provided to the family on the birth of a

second girl child. The panchayats shall be granted incentives for ensuring 100 enrolments of girls in the age group of 6-14 years in schools. Health card would be provided to all girl children up to the age of 18 years. Girl students will receive 50 per cent additional concession on their bus passes. To attract more girls to technical education, 25 per cent seats in technical institutes and engineering colleges have been reserved for them.

32. Similarly for raising the status of women, our Government has taken effective steps. Transfer of property in the name of a woman will invite 2 per cent lower stamp duty than man. Housing Board Haryana has reserved 33 per cent of houses for women applicants in their housing schemes. In the recruitment of school teachers, 33 per cent posts have been reserved for women. Under the "Ladli Samajik Suralscha Pension Yojana", the parents who have only girl children will receive an allowance of Rs. 300 per month from the age of 55 years instead of 60 years in other cases. The "Indira Gandhi Priyadarshini Vivah Shagun Yojana" is being implemented to provide financial assistance of Rs. 15000 to scheduled caste and denotified tribe families and Rs. 5100 to other families living below poverty line for the marriage of their daughters. Thus, the financial burden on the marriage of girl would no longer make the poor families consider girls as unwanted.

SALUTE TO THE BRAVE SOLDIERS OF HARYANA

33. In recognition of the services and the supreme sacrifices being made by our brave soldiers in safeguarding the border of the country, our Government has decided to substantially enhance the amount of cash awards

and annuity being paid to gallantry award winners, both of the pre-independence and post-independence era, irrespective of the ranks held by them in the Defense Forces. A four-fold increase has been made in the annuity of gallantry prizes like Param Vir Chakra, Mahavir Chakra etc. Separate reservation for defense personnel and ex-servicemen in Group Housing Societies has been made. Besides, Defence Colonies will be developed at Rohtak, Rewari, Jhajjar and End. Items purchased from CSD canteens have also been made tax free for parents of deceased un-married service officers and widows of service officers. Ex-servicemen Contributory Health Scheme has been introduced under which they can avail free medical facility in Government Hospitals besides Army Hospitals. A War Museum will be constructed at Rewari.

34. We have also not forgotten the heroes of our independence movement and enhanced the amount of 'Samman Pension' to freedom fighters from Rs. 1400 to Rs. 3500 per month. We have also decided that the personnel of all ranks in the para-military forces will get ex-gratia payment at par with Army personnel.

RATIONALIZATION OF SURCHARGE ON DELAYED PAYMENTS

35. Sir, this is one of the very progressive steps, which our Government has taken. The Departments of Irrigation, Public Health and Power are presently levying heavy surcharge on the principal amount of user charges paid after the due date. For every subsequent month of delay a further surcharge is levied on the outstanding

amount of the consumers. The surcharge levied at present is excessively punitive and acts as a disincentive for the consumers who want to make the delayed payments. It is felt that there is a strong case for rationalizing the rate of surcharge on such services to improve recoveries and to provide relief to the consumer in future.

36. I propose that consumers who make payment of their dues within one month from the date of the bill may be given discount on the billed amount. **The** existing rate of surcharge will be suitably modified for every subsequent month of delay. Comprehensive guidelines on the subject would be issued shortly.

37.No I would briefly discuss the budgetary allocation made in some of the key sectors which form a part of our Government's development agenda for the year 2006-07.

POWER SECTOR

38. Sir, this is a most crucial sector. Electricity is a critical input for the development of the State. Our Government is laying highest priority to maximize power availability in the State and to improve the quality of its supply. In spite of insufficient rains during kharif season and severe shortage of power in the northern grid, 7 per cent more power was supplied up to December, 2005 during 2005-06 as compared to corresponding period of the previous year.

39. Speaker Sir, the demand for power is increasing at a rapid pace and our Government is taking all possible steps to narrow the gap between demand & supply. The Government has embarked on an ambitious plan to add over

4000 MW of generation capacity during 11th Five Year Plan both in the State sector as well as through private sector participation. The 600 MW Yamunanagar Thermal Power Project is expected to be commissioned by March 2008. In addition, arrangements are being made for facilitating generation of 1065 MW at Faridabad, 1080 MW each at Hisar and Jhajjar and 1000 MW at Panipat preferably through gas-based plants. Steps are also being taken to set up 1000 MW coal-based plants at Hisar and Faridabad.

40. Besides increasing power generation, our Government is constantly endeavoring to strengthen the transmission & distribution network not only to supply quality power to consumers but also to cut down transmission & distribution losses. Since March 2005, 17 new sub-stations have been commissioned, 83 existing sub-stations augmented and 396 KM of new transmission lines erected with a total investment of Rs. 111 crore. In the next two years, 63 new sub-stations will be constructed and 58 existing sub-stations will be augmented and 109 km of transmission lines would be constructed with an investment of Rs. 700 crore. Similarly, power utilities have prepared plans for investment of Rs. 500 crore in transmission and distribution network in the next two years in order to provide quality power to consumers. •

41. Proposals worth Rs. 252 crore have been submitted to Government of India under 'Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana' for the expansion and improvement of power infrastructure to provide electricity to all rural households.

42. While the present power shortage is being

tackled through purchase of power even at high cost from all possible sources, the State Government is committed to stabilize the power situation and the financial health of the power utilities in the near future. Steps to improve transmission and distribution efficiency and for ensuring availability of power at reasonable rates have been initiated. Future availability of sufficient power is being ensured through signing of long term Power Purchase Agreements for the projects coming up in various parts of the country. Simultaneously, our own generation capacity is being augmented through additional coal-based generation. Efforts are also being made to have a plant based on petroleum coke being produced as a by-product at Panipat Refinery and for making sufficient gas available for gas-based generation.

43. Our Government is also attaching due importance to renewable sources of energy for sustainable growth. We have formulated a policy on power generation through non-conventional sources under which incentives would be provided for private investment in this sector. This policy aims to add at least 500 MW of power to be generated through renewable energy power projects by 2012.

A total outlay of Rs. 2104.93 crore has been kept for power sector including renewable energy in 2006-07.

IRRIGATION AND DRAINAGE

44. Our Government is committed to provide equitable distribution of water to all regions in the State and in accordance with our assurance; we have already enhanced the availability of irrigation water to southern Haryana which

had received a raw deal during the previous regime. We have made available 25 per cent more canal water during Kharif 2005 and 59 per cent more in the Rabi season as compared to corresponding periods in the previous year.

45. We have undertaken two prestigious irrigation projects since coming to power. The first project is BML-Hansi-Butana multi-purpose link channel of 2000 cusecs costing Rs. 259 crore, which will augment the availability of irrigation water of southern Haryana besides improving the availability of sub-soil water level in its command area. The other project is Dadupur-Shahbad-Nalvi canal, which will help to utilize the surplus water of Yamuna river during monsoon season and also recharge ground water of Yamunanagar, Ambala & Kurulshetra Districts. In addition, a ground water recharge project for Masarti Barrage in Rewari District has been commenced costing Rs. 6.7 crore.

46. The State Government is determined to realize our full share of Ravi Beas waters through SYL canal at the earliest. We have demanded early completion of SYL and will strongly defend legitimate right of our State in the case before the Hon'ble Supreme Court of India. SYL is the life line of Haryana and our Endeavour would be to see that it becomes a reality.

47. During the current year. 48 flood control schemes have been completed and 45 are in progress. Recently the Flood Control Board has sanctioned 134 new and 45 ongoing schemes involving an estimated cost of Rs. 140 crore.

There is an allocation of Rs. 1059.03 crore for

irrigation & drainage works during 2006-07.

ROADS & BRIDGES

48. The State Government attaches great importance to rail, road and bridge Infrastructure of the State and are taking all possible steps to strengthen as well as

Expand it. For a long time, no new rail line was laid in the State though there has been considerable talk about it. Within a year) 1-the present Government, a new rail line from Rohtak to Rewari at a cost of Rs. 21:-. Tore has been got sanctioned from the Ministry of Railways on 50:50 cost sharing, basis. This is the first example in the country when our State is sharing with du Railways on 50:50 cost sharing basis. There is good news that from Delhi to Rohtak railway track would be electrified.

49. With the efforts of the State Government a few more crucial National Highway projects are being taken up. The Government of India has agreed to four lanes the National Highway No. 10 from Delhi to Rohtak and Zirakpur-Panchkula-Kalka portion of NH-22. The work for construction of 10 km. long highway including 3.408 km elevated portion at Panipat has beg-e this year. In addition, Ambala-Zirakpur section of National Highway No. 22 is likely to start soon.

50. The State Government has realized the importance of bridges, especially Rail Over Bridges (ROBs). The PWD has prepaid a master plan of constructing 88 ROBs to be taken up in a phased manner. The construction on 9 ROBs has already commenced and the work on 9 more ROBs at a cost of Rs. 140 crore would start very soon. The

construction work on 13 bridges on canals and roads has been completed during this year.

51. In order to tap resources and e- expertise available with the private sector, the State Government has also decided to take up five State roads on build, operate and transfer (BOT) basis.

52. For improving quality, design and introducing cost effective technologies of roads, bridges and buildings, the State Government has decided to upgrade the existing Laboratory of the PWD located at Hisar and convert it into an autonomous society. It has also been decided to revise and update age old PWD Code incorporating the latest construction technologies and management practices.

53 Village roads and municipal roads are also proposed to be strengthened/ improved with LADT funds passed on by State Government to Rural & Urban Local Bodies. We are engaging consultants for introducing new trends in design, construction and management of works.

Total outlay for Roads & Bridges has been provided at Rs. 739.76 crore in 2006-07.

MODERNIZING THE TRANSPORT NETWORK

54. Our Government has been attaching high priority for providing safe, efficient, reliable and adequate transport services. Haryana Roadways is performing a pivotal role by transporting over 11 lakh passengers every day by deploying a fleet of 3500 buses. An amount of Rs. 78 crore was allocated in the current year for acquisition of new fleet,

construction of new buildings, modernization of workshops and strengthening of Drivers Training Institutes. A similar provision of Rs. 78 crore has been made in the next year out of which Rs. 58.85 crore are proposed for acquisition of new fleet.

55. Raen Baseras (Night Shelters have been set up at important bus stands. About 500 buses are being replaced in the current year and more than 300 buses are proposed to be replaced in the next year. It is also proposed to include CNG, AC & Deluxe buses the fleet for renovation & up gradation of bus stands & workshops. A special provision of Rs. 10 crore was made for the first time in the current year and the same amount has been earmarked next year also. Improved training & health *check* up of drivers and better maintenance of fleet has resulted in reduction of accident rate from 0.14 per lakh KM in 1999-2000 to 0.08 per lakh KM in 2004-05 which is half of the national average of all the State Transport Undertakings.

56. The spiraling price of oil in the recent past has had its effect on the sustainability of transport sector the expenditure on diesel of Haryana Roadways which was Rs. 150 crore in 2002-03 has increased to Rs. 252 crore during 2005-06. The staff expenses have **also gone up considerably. The last** fare revision had taken place in August 2003. In order **to carnally** offset the extra burden on Haryana Roadways, I propose a modest increase of 5 paise per kilometer in the fare to be charged from the passengers. This is likely to generate additional revenue of Rs. 40 crore for the State during the **next year.**

A provision of Rs. 754.96 crore has been made for transport sector for the year 2006-07.

AUGMENTATION OF DRINKING WATER SUPPLY

57. Drinking water supply facilities had been extended to all the villages in the State by 31st March, 1992. However survey carried out in December 2004 revealed that there are 1971 villages in the State where the per capita availability of drinking water was less than 40 lpcd. During the current year, work on augmentation in 680 such villages has been taken up and work on 1100 villages will be initiated in next financial year.

58. In order to augment drinking water supply in 503 villages of Mewat, which is a chronic water deficit area, a Ranney wells based project sanctioned by NCR Planning Board at a total project cost of Rs. 425 crore is under implementation. The NCR Planning Board has also approved an augmentation project for rural areas falling in the districts of Faridabad, Gurgaon, Panipat, Rewari, Rohtak, Jhajjar & Sonipat at an estimated cost of Rs. 162.10 crore covering 652 villages.

59. A special campaign was launched during 2005-06 to ensure adequate drinking water supply in Scheduled Caste Bastis for which Rs. 6 crore were allocated. So far 414 Scheduled Caste Bastis have been benefitted as a result of this project. A similar provision has been made in the current year as well.

There is a total provision of Rs. 759.63 crore for improving water supply and sewerage in 2006-07.

AGRICULTURE AND All ACTIVITIES

60. Agriculture continues to be the mainstay of 75 per cent of our population although its contribution to Gross State Domestic Projects is declining over the years. Our Government intends to tackle the problem of declining farm productivity by adopting a composite strategy of improved practices, diversification of cropping pattern and support services including insurance and market intervention.

61. To protect the interests of farmers growing sensitive crops like mustard and gram, the scope of National Agriculture Insurance Scheme has been extended to cover these crops also along with the crops already covered under the scheme. We have recently brought out an amendment in the State Agriculture Produce Marketing Act for providing an enabling provision to support contract farming in the State. Efficient marketing is as good as increasing production for the benefit of farmers. The use of Information Technology is being encouraged, especially with a view to harness the potential thrown up by creation of agriculture commodity markets in India. A new scheme "Support to State Extension for Extension Reforms" is being implemented in order to make extension delivery system more broad-based and holistic in content & scope.

62. For the integrated development in horticulture, Haryana State Horticulture Development Agency has been set up under the aegis of National Horticulture Mission. An end to end approach covering production, post harvest management, processing and marketing has been adopted to ensure increased returns to the growers.

63. Our Government has taken up a comprehensive program for the control of 'Foot & Mouth Disease' amongst our livestock. An ambitious program for preservation, multiplication & improvement of indigenous germplasm of Murrah buffalow, Haryana and Sahiwal cow is under implementation in the State. To provide veterinary services at the farmer's doorsteps, 198 veterinary institutions have been opened or upgraded during last year. We have planned to open/upgrade 60 more veterinary institutions in the current financial year.

64. Keeping in view the vast potential of fish farming in the State, technical & financial assistance is being imparted to fish farmers through Fish Farmers' Development Agencies. The fish production in the State has gone upto 48000 tonnes in the current year and it is envisaged to raise it further to 55000 tonnes by the end of next year. Fish markets at Bahadurgarh & Gurgaon will be made operational during 2006-07 to benefit the fish farmers. Two new schemes of "Development of Ornamental Fisheries" and "Strengthening of Post Harvest Infrastructure" are being introduced this year.

A total provision of Rs. 480-46 crore has been made during 2006-07 for Agriuculture & allied activites.

RURAL DEVELOPMENT

65. Our Government is keen to involve Panchayati Raj Institutions in our Endeavour to achieve all round development in rural areas. We have abolished the post of Gram Vikas Sahayak and Village Development Committees put in place by previous Government to encroach upon the

autonomy of PRIs provided under the Constitution. The finalization of activity mapping as a follow up on MOU signed between our Chief Minister and the Union Panchayati Raj Minister in August last year demonstrates our intention to strengthen the grass -root democratic institutions in Haryana.

66. A number of rural development schemes are being implemented in the State with the support of Government of India. Haryana Rural Employment Guarantee Scheme has been launched in Mahendergarh and Sirsa Districts from 2nd February, 2006. The scheme has been formulated under the National Rural Employment Act, 2005. The primary objective of the scheme is to enhance livelihood security in rural areas by providing round the year employment with minimum guarantee of 100 days of wage employment in a financial year to every household volunteering to do unskilled manual work_ There is a provision of Rs. 5.50 crore as 10 per cent State share under the scheme for next year and 90 per cent funds will be provided by Government of India. Sir, this is a revolutionary step which has been taken up by the Government of India. Now wherever this scheme is applicable, any abled man coming forward with a request that I want to do some manual work, either the Government will have to give him the work for 100 days or after 15 days if Government fails to give him the work then he would be entitled for minimum wages. We must congratulate and we are thankful to our leader Smt. Sonia Gandhi in this regard. (Thumping)

67. During current year. with the funds provided by HRDF Administration Board, rural development works

especially for rural streets, drainage, sanitation and other purposes have been taken up with an allocation of Rs. 195 crore. During the current year. Common Minimum Program was formulated under the president ship of Smt. Sonia Gandhi who heads that Coordination Committee. Try to understand and try to appreciate what I say. On the recommendations of 2nd State Finance Commission, which was received in the current year only, a sum of Rs. 50 crore has been released to PRLs for various development works suited to the local needs. In addition Rs. 116 crore has been released by our Government to PRIs as a share in LADT for taking up creation and up gradation of rural infrastructure.

A total provision of Rs. 282.95 crore has been made for Rural Development and Panchayats Department in 2006-07.

MUNICIPAL ADMINISTRATION AND URBAN DEVELOPMENT

68.. Speaker Sir, municipal institutions play a key role in providing civic amenities in urban areas and local governance. Our Government is taking significant steps for integrated development of urban areas particularly those falling in the National Capital Region.

69. We are conscious of the fact that without adequate funds, civic bodies cannot function properly. During 2005-06, a sum of Rs. 50 crore on the recommendations of 2nd State Finance Commission, Rs. 116 crore as LADT share and Rs. 18.20 crore on the recommendations of 12th Finance Commission has been provided to Urban Local Bodies in addition to normal budget allocation of the State. This is for

the first time last year we have provided this much of amount to the local municipal committees. We propose to release more funds during the next year also. A sum of Rs. 57.77 crore has been provided for development of urban infrastructure including slum areas. Sir, in addition to that HUDA and HSIDC together with provide more than 425 crore rupees annually to strengthen the urban and industrial infrastructure in the State.

70. Our Government is also giving the much needed attention on expanding and strengthening the sewerage system in urban areas in the State. Out of 68 towns in the State, there are 15 towns where there are no sewerage facilities. A special project to strengthen the sewerage system covering 11 towns in the State will be taken up during 2006-07.

71. Significant steps have been taken for development of National Capital Region. A global corridor has been planned on both sides of KW expressway which would become the focus of futuristic development activities. The proposed expressway is likely to generate huge potential for setting up of industrial model townships and new urban centers. Keeping in view the rapid trend in urbanization, we have reversed the decision of the previous Government and reconstituted eight abolished municipal bodies.

72. In the recent past distinct upward swing has become visible in the real estate and housing sector. This is primarily because of the improved infrastructure facilities provided by the Government and the strategic location of the State. However, excess liquidity in this sector is causing concern and there is likelihood of situation getting out of

hand. Hence, some discipline needs to be infused in this sector. To start with I suggest that the person dealing with land properties should be compulsorily registered with the local authority for which the State. Government is examining the possibility of bringing out comprehensive guidelines. (Thumping) We also propose to periodically revise the Collector rates of land with a view to bridge the gap between the prevailing market rates and the actual rate at which the land transactins are being registered. हर 15 दिन मे भाव बढ जाते है हमे कई सौ करोड रूपया इस मद मे आएगा ।

A total provision of Rs. 168.87 crore has been made during 2006-07 for Urban Development.

73. Our Government accords high priority on expansion of educational infrastructure in the State along with improving its quality. We intend to achieve universalization of Primary education by the year 2007-08 through mission mode

Delivery system to rural women, 300 delivery huts have been planned to be constructed out of which 160 of such delivery huts have already been established. This figure was at that time when this budget was being prepared. No it has gone up to from 160 to 230. In order to improve health coverage in Mewat, multi specialty health camps are being organized at suitable intervals. To make available the services of specialists to poor people, an innovative scheme called '1p' has been launched on pilot basis in four districts under which the services of private medical practitioners would be made available free of cost. The Government will pay suitable

remuneration to such private medical specialists on the basis of services rendered by them Under the Sarv Siksha Abhiyan by opening am schools providing teachers, alternate school facilities & strengthening of school infrastructure. In order to encourage brilliant students & promote girl education 'Rajiv Gandhi Scholarship for Excellence in Education scheme has been launched by the State Government.

74 Our Government plans to raise quality of education input through EDUSAT. A central studio and a hub is being established at Panchkula for broadcasting EDUSAT programs.

75. For improving quality of science education in high Senior Secondary schools, equipments would be provided to strengthen the laboratories. To develop reading habits among students Vidyalaya Nehru pusatkaylya would be opened in all the schools. Selection of books will be made by involving eminent persons from the field of education, literature, administration etc.

76. The State Government has decided to set up a 'Rajiv Gandhi Education City' at Kundli where educational institutions of international repute will be invited to set up 'Centers of Excellence'. With a view to promoting women's higher education, a women's university is proposed to be established and a women's college has been set up in rind. A National Law Institute at LMT Manesar is also proposed to be set up by the Central Government.

77. For up gradation of sports and youth welfare activities in the State, the Government has adopted focused

approach towards creating infrastructure for games and mass participation of players in sports. Our Government proposes to set up a 'Sports Academy' at Rohtak with the help of Government of India. A multipurpose hall would be constructed in Moti Lal Nehru Sports School at Rai (Sonipat).

A total provision of Rs. 2432.89 crore has been proposed for Education and Sports in 2006-07.

HEALTH SERVICES

78. Speaker Sir, providing good and affordable health services to the people of State is one of the priorities of our Government. We are conscious of the fact that per capita expenditure on health coverage must go up along with education. in order to ensure better human development in this State.

79. During the year 2005-06, a provision of Rs. 102 crore was made in the Annual Plan for health sector which was 76 per cent higher than the previous year (2004-05). For the next year (2006-07), this provision has been further enhanced by 12 per cent to Rs. 114.5 crore. The emphasis is on improvement of health infrastructure which includes addition of bed capacity, purchase of modem medical equipments. Provision of basic and life saving medicines and maintenance and up gradation of hospital buildings to provide more congenial environment for patients.

80. A number of innovative health schemes have been initiated to increase the coverage of health services especially in rural areas. To facilitate institutional Delivery system to rural women, 300 delivery huts have been planned

to be constructed out of which 160 of such delivery huts have already been established. This figure was at that time when this budget was being prepared. Now it has gone up to from 160 to 230. In order to improve health coverage in Mehat, multi specialty health camps are being organized at suitable intervals. To make available the services of specialists to poor people, an innovative scheme called '1p' has been launched on pilot basis in four districts under which the services of private medical practitioners would be made available free of cost. The Government will pay suitable remuneration to such private medical specialists on the basis of services rendered by them

81. Under the National Rural Health Mission Phase-II, a number of schemes are being implemented with a view to reduce infant and maternal mortality. Janani Suraksha Yojana is one of such innovative schemes which integrate the cash assistance with ante-natal care, institutional care during delivery under the care of the field level health workers. A similar scheme called 'Janani Suvidha Yojana' has been launched recently to enable poor women living in urban slums to avail of free ante-natal, delivery and post-natal services from selected nursing homes.

A provision of Rs. 565.78 crore has been made for Health sector during 2006-07.

WELFARE OF WEAKER SECTIONS

82. Speaker Sir, our Government is in the forefront of taking welfare measures for all sections of society particularly the weaker and disadvantaged social groups. Major emphasis is given to promote education amongst scheduled caste & backward class students. A new scheme

known as "Dr. Ambedkar Medhavi Chhatar Yojana" has been started under which 2000 scheduled caste and 1000 backward class (Block 'A') students scoring 60 per cent or above marks in matriculation will be given scholarship @ Rs. 1000p. in 10±1 and 10-T-2 classes.

83. Our Government has decided to enhance the amount of grant for the construction of houses of scheduled castes and de-notified tribes from Rs. 10000 to Rs. 50000. We have also strengthened the social security net for the aged, widows and disable persons for which Rs. 479.7 crore have been earmarked during next year.

A total provision of Rs. 811.82 crore has been made for the various social welfare measures in 2006-07.

EMPLOYMENT AND VOCATIONAL EDUCATION

84. Technical manpower is an essential input for industrialization, modernization and promotion of trade and business. It has vital contribution for research and development. Our Government has planned to set up ITIs, VEIIs and Technical institutes at different places of the State where such institutions do not exist. During the next 4 years 20 more ITIs, including 5 ITIs for women will be upgraded. Five Its would be upgraded into Centers of Excellence during the year 2006-07.

85. Some private industries have agreed to have partnership with Government ITIs in technical training and management to produce highly skilled manpower. Under this industry-institution collaboration program. ITIs at Gurgoan.

Faridabad. Nagina and Karnal will be covered. I would like to make it very clear at the stage that this scheme is not going to lead in any way to privatization of ITIs in Haryana.

. 86. The payment of unemployment allowance has been rationalized through the new scheme known as - Unemployment Allowance for the Educated Unernpolyed Scheme. 2005". Under this scheme. 10+2 pass and two year certificate diploma holders are getting allowance of Rs. 300 per month against earlier allowance of Rs. 100 while graduates and others having passed three year certificate/diploma course after 10+2 are getting allowance of @ Rs. 500 per month against earlier allowance Rs. 200, registering an increase of up to 200 per cent.

E-GOVERNANCE FOR TRANSPARENT & EFFECIIVE PUBLIC DELIVERY SYSTEM

87. Speaker Sir, our State is an aspiring leader in E-Governance as per the E-Governance readiness index of the country. Haryana not only wishes to attain leadership position but is also going ahead with E-Governance initiatives by establishing State Wide Area Network (SWAN). The SWAN is being set up connecting the State Headquarters and District Headquarters and all Block Headquarters. SWAN also envisages village connectivity through wireless. A comprehensive E-Governance road map has been prepared and submitted to Government of India for approval. This will enable transparency, efficiency and accountable Governance that shall throw up opportunities and provide access to the citizen centric services. E-Disha, a single point multi-service

delivery system for providing citizen-centric services is being launched across the State. One District Level E-Disha Centre will be established by 31st March, 2006 at each District Headquarter.

TAX-REFORMS

88. Our Government is committed to provide a friendly tax structure in the State in the overall interest of consumers, manufacturers, trading community and the farmers. To integrate the economy of the State with the rest of the country, the Government has aligned rates of taxes on various commodities with the recommendations of the Empowered Committee set up by the Central Government. As a consequence thereof, rates of taxes on a large number of commodities of common use have been reduced. Tax on medicines and other articles of medical care has been further reduced from 10 per cent to 4 per cent. Even though Empowered Committee favored taxing fertilizer at 4 per cent and diesel at 20 per cent, considering that fertilizers and diesel constitute important inputs for crop production, our Government has decided to exempt fertilizers from VAT and also to maintain the present 12 per cent rate of tax on diesel. Charging of lower tax on Diesel shows our commitment to the farmers and encouragement that we are providing for increase of agriculture production in the State. Further, certain items of general use by common man have been exempted from the payment of VAT. For the information of the House, the State government, on the representation of traders, manufacturers and consumers has taken a decision to either exempt or reduce tax on 22 commodities i.e. dairy products, tractor

tyres, animal feed, industrial chemicals, syringes, nuts & bolts, etc. which would give revenue loss to the State Government of Rs. 84 crores per annum. A case for exemption or reduction of tax on 9 other items is under consideration of the Government, which include butter, paper and plastic cups, bricks made of fly ash, toys. etc. involving a revenue loss of Rs. 4 crores.

89. In order to give boost to entertainment .industry in the State, the Government has decided to reduce rate of entertainment duty from 50 per cent to 30 per cent. The State Government has constituted a State Level Consultative Committee for addressing the genuine grievances of trade and industry through a consultative mechanism between the Government and the tax-payers. Sir, it would be a continuous process whenever we feel that the demand of certain sections of the traders is genuine. This Committee would certainly consider those demands. Now, Sir, in the last I move to the budget estimates of 2006-2007.

BUDGET ESTIMATES 2006-07

90. Hon'ble Speaker, now I present before this august House the Budget Estimates for the year 2006-07.

91. The year 2005-06 opened with a deficit of Rs. 48.15 crore as per RBI books and is likely to be closed with a deficit of Rs. 53.91 crore.

92. The financial year 2006-07 is likely to open with a deficit of Rs. 53.91 crore and to close with a deficit of Rs. 65.47 crore. The transactions on year's account, thus, show a deficit of Rs. 11.56 crore.93.

93. The Consolidated Fund of the State shows total receipts of Rs. 17666.48 crore in Budget Estimates 2006-07 as against Rs. 16097.85 crore in Revised Estimates 2005-06. The budget proposals indicate an expenditure of Rs. 17576.56 crore as against Rs. 15922.54 crore in Revised Estimates of 2005-06. The budget estimates provide for State Plan outlay of Rs. 3300 crore in addition to an outlay of Rs. 602.33 crore for Centrally Sponsored Schemes and other development plan schemes.

94. The revenue receipts in Budget Estimates 2006-07 are likely to increase by Rs. 1100.85 crore to Rs. 13746.65 crore from Rs. 12645.80 crore in Revised Estimates of 2005-06. The revenue expenditure in Budget Estimates is estimated at Rs. 14066.66 crore, which is higher by Rs. 817.53 crore over the Revised Estimates of Rs. 13249.13 crore of 2005-06.

95. The budget deficit of Rs. 65.47 crore is within manageable limits and the measures proposed for financial discipline are likely to help containing the deficit. It is hoped that the share in central taxes and other devolutions would also go up as result of higher expected growth in national economy. Similarly, the State tax revenue is also expected to give substantial increase. I am confident that we will be able to implement all our programmes successfully by full utilization of plan outlay with the cooperation and assistance of Hon'ble Members of this House and people of Haryana.

96. Before, I conclude, I acknowledge the un tiring efforts of officers and employees of Finance. Department and NIC who worked hard to help me prepare the budget

proposals. So Sir, before I commend I must close my speech with this one more couplet.

मस्जिद की अजा हो, ि त्वालय की गजर हो ।

अपनी तो यह हसरत है, किसी तौर भाहर हो ॥

एक नया सवेरा हो हरियाणा की जनता के लिए एक अच्छी भुरुआत हो ।

97. Sir, Now I Commend the budget estimates 2006-07 for the consideration and approval of this august House.

Mr. Deputy Speaker: Now, the House is adjourned till 2-00 PM. On Monday the 20th March, 2006.

17.11 hrs.

(The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, 2.00 P.M. on Monday the 20th March, 2006.)